चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 14 सितंबर-20 सितंबर 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव

जनता में उत्साह नहीं है

बिहार में विकास की किरण तो दूर, विकास की परछाई भी कहीं नज़र नहीं आती. ज़िंदगी के बोझ से दबे परेशान चेहरे, कुपोषित महिलाएं-बच्चे, कच्चे मकान, टूटे-फूटे सरकारी भवन और अंधकार में डूबे गांव, यही आज बिहार की पहचान बन गई है. ग़रीबी और महंगाई की ऐसी दोहरी मार है कि जीविकोपार्जन के लिए आज भी आम बिहारी दर-दर की ठोकरें खा रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर मीडिया के ज़रिये देश के सामने पहुंच रही है, वह सच्चाई से कोसों दूर है. मीडिया में तो काफ़ी चहल-पहल है, लेकिन बिहार की जनता चुनाव को लेकर फिलहाल उत्साहित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लालू यादव, नीतीश कुमार एवं सोनिया गांधी का महा-गठबंधन, किसी की रैलियों में आम जनता की भागीदारी न के बराबर है. इन रैलियों में सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टी कार्यकर्ता, सक्रिय समर्थक एवं भाड़े पर लाए गए लोग नज़र आते हैं. दरअसल, बिहार की जनता राजनीतिक दलों, सरकार और सरकारी तंत्र से निराश हो चुकी है. राजनीति में जिस तरह की अवसरवादिता का उदाहरण विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिहार में पेश किया है, उससे लोग भ्रमित हो गए हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और ग़लत कौन? यही वजह है कि बिहार में चुनाव को लेकर आम जनता में कोई उत्साह नहीं है.

मनीष कुमार

भारत में राजनीतिक दलों ने प्रजातंत्र का तमाशा बना दिया है. राष्ट्रीय पार्टियां हों या फिर क्षेत्रीय, सबने मिलकर प्रजातंत्र को मात्र एक चुनाव प्रबंधन की प्रक्रिया में तब्दील कर दिया है. देश को आज़ाद कराने और संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने प्रजातंत्र को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का माध्यम माना था. उनके सामने साफ़ लक्ष्य था कि सरकार का चरित्र कल्याणकारी और जन-हितकारी होगा. सरकार अपनी नीतियों से ग़रीबों के दु:ख-तकलीफ दूर करेगी. ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी विभिन्न संसाधन मुहैया कराएगी. गांवों का पिछड़ापन दूर करके उन्हें विकास की ओर ले जाएगी. ग़रीब, पिछड़े, दलित एवं शोषित वर्ग की मदद करेगी, ताकि वे भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें और देश के विकास में अपना योगदान कर सकें. देश की जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास की

- प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार सबसे ग़रीब राज्य है.
- सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ़ 36 हज़ार रुपये है.
- दिल्ली में सालाना प्रति व्यक्ति आय बिहार से सात गुना ज़्यादा है.
- बिहार के महज 52.8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है.
- लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 66 प्रतिशत मतदान हुआ.
- लेकिन, बिहार में महज 56 प्रतिशत लोगों ने ही वोट डाले.
- दस विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में महज 47 प्रतिशत मतदान.

ज़िम्मेदारी राजनीतिक दलों की थी, लेकिन उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का माध्यम बना डाला. सत्ता का एकमात्र उद्देश्य कॉरपोरेट्स और उद्योगपतियों का विकास बना दिया गया. आज राजनीति का मतलब सिर्फ़ यह हो गया है कि ग़रीब जनता को झूठी दिलासा देकर, वादे करके वोट ले लो और सत्ता पर विराजमान होते ही उसे भूल जाओ. झूठे वादों की भी एक सीमा होती है. बिहार की जनता का अब नेताओं के वादों से विश्वास उठने लगा है. शायद यही वजह है कि बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों

और मीडिया में भारी शोरगुल है, लेकिन जनता के बीच कोई उत्साह नहीं है.

बिहार के लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह कम होने के कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों का नेताओं से भरोसा उठ गया है. उन्हें लगता है कि सरकार किसी की भी बने, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, उनके इलाके का विकास नहीं होने वाला. बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व हैं. बड़े विश्वास के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन चुनाव के डेढ़ साल के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी. लोगों को कोई भी वादा ज़मीन पर उतरता दिख नहीं रहा है, वे खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं. जिस तरह लोग मोदी से निराश हैं, उसी तरह नीतीश कुमार से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है. नीतीश कुमार जंगलराज ख़त्म कर विकास करने का वादा करके बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में क़ानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी थी और उस दौरान बिहार में सड़कों की हालत में भी खासा सुधार हुआ था. नीतीश कुमार के पिछले पांच वर्षों का कार्यकाल राजनीति की भेंट चढ़ गया. हर राजनीतिक दल अपनी-अपनी सरकार की तारीफ़ करता है, बिहार के विकास में अपने योगदान का दावा करता है और इसके लिए तरह-तरह के आंकड़े पेश करता है. टीवी चैनलों

> बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर काफ़ी परिपक्व हैं. बड़े विश्वास के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन चुनाव के डेढ़ साल के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी. लोगों को कोई भी वादा ज़मीन पर उतरता दिख नहीं रहा है, वे खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं. जिस तरह लोग मोदी से निराश हैं, उसी तरह नीतीश कुमार से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है.

पर बहस के लिए तो यह सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आम जनता पर इन दावों और आंकड़ों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह तो भुक्तभोगी है. गांव-ब्लॉक में कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचती नहीं हैं, स्कूल-कॉलेज नहीं हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है. सड़कें नहीं हैं. जो सड़कें पहले बनी थीं, वे देखरेख के अभाव में टूटने लगी हैं और क़ानून व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. एक वाक्य में अगर कहा जाए, तो यह कि बिहार में सरकार का एक भी महकमा ऐसा नहीं है, जिस पर बिहार के लोग नाज कर सकें. ऐसे माहौल में लोगों की निराशा न तो पैकेज की राजनीति से ख़त्म होने वाली है और न बड़े-बड़े वादों से.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गुजरात पाटीदार आंदोलन आरक्षण से अलग भी कई सवाल हैं | P-3

महा-गठबंधन की स्वाभिमान रैली हीरो और विलेन दोनों रहे लालू | P-4

क़ादर ख़ान को पद्म पुरस्कार क्यों नहीं | P-6

बिहार विधानसभा चुनाव

जनता में उत्साह नहीं है

पृष्ठ 1 का शेष

सरकारी तंत्र के प्रति निराशा के लिए कोई एक राजनीतिक दल या सरकार ज़िम्मेदार नहीं है. इसमें सारे राजनीतिक दलों और सरकारों का योगदान है. प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार देश का सबसे ग़रीब राज्य है. यहां सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 35-36 हज़ार रुपये है. जबकि गोवा और दिल्ली जैसे राज्यों में सालाना प्रति व्यक्ति आय बिहार से सात गुना ज़्यादा है. इसकी वजह यह है कि बिहार में उद्योग नहीं हैं, आर्थिक गतिविधियां थमी हुई हैं. दूसरी बड़ी समस्या यह है कि बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. मतलब यह कि सीमित अवसर, रोज़गार एवं मूलभूत सुविधाओं पर लगातार बढ़ते दबाव के अनुरूप बिहार में विकास नहीं हो रहा है. बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार पिछड़ता जा रहा है. इतना ही नहीं, बिहार में शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं एवं कमियों के चलते शिक्षित-अप्रशिक्षित युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है. गांवों का हाल और भी खराब है. भूमिहीन कृषक-मज़दूरों की संख्या बहुमत में है. मनरेगा जैसी योजनाओं से ग़रीबों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन यह किसी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पर्याप्त नहीं है. इससे दूसरे राज्यों की ओर पलायन तो थोड़ा थमा, लेकिन जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया.

बिहार की सबसे बड़ी समस्या ग़रीबी और सरकारी तंत्र की तबाही है. मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वाले हर महकमे की स्थिति बद से बदतर है. आज़ादी के बाद 68 वर्ष बीत गए, लेकिन बिहार के ज़्यादातर जिलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ है. मतलब, 21वीं सदी के बिहार में ऐसे हज़ारों गांव हैं, जहां बिजली पहुंची ही नहीं है. यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के ग्रामीण इलाकों में महज 52.8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है. बिहार के ग्रामीण इलाकों में मात्र छह प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच सकी है. मतलब यह कि 85 प्रतिशत ग्रामीण बिना बिजली के जीवन बिताने को मजबूर हैं. अब इन गांव वालों को इससे क्या मतलब है कि विद्युतीकरण का काम संविधान के मुताबिक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है या नहीं है? इन गांव वालों को बजट के आंकड़ों से क्या लेना-देना है? उनके लिए तो सिर्फ़ एक ही सत्य है कि उनके गांव-घर में बिजली नहीं पहुंची. आज के जमाने में बिजली न होने का मतलब ज़िंदगी अंधकारमय है. ज़्यादातर गांव ऐसे हैं, जहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं. आज भी बिहार के गांवों में झाड़-फूंक से इलाज कराने का प्रचलन है. ब्लॉक स्तर पर भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं. सरकार पीने का साफ़ पानी तक उपलब्ध कराने में नाकाम रही है. अब तो बिहार के कई इलाकों में कुएं का पानी भी प्रदूषित हो चुका है. बच्चों की पढ़ाई पेड़ के नीचे हो रही है. स्कूल और शिक्षा के नाम पर जो कुछ चल रहा है, वह हास्यास्पद है. एक तो योग्य शिक्षकों का घोर अभाव है और जो हैं भी, वे पढ़ाने से ज़्यादा मिड डे मील मुहैया कराने में व्यस्त रहते हैं. यही हाल कमोबेश हर सरकारी महकमे का है. दुनिया न जाने कहां से कहां निकल गई और बिहार में आज भी ऐसा कुछ नहीं है, जो 21वीं सदी के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलने लायक हो.

बिहार में उत्साह की कमी के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि राजनीतिक दल अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में तब्दील हो गए हैं. जनता से उनका न तो अब कोई संपर्क-सरोकार है और न उनकी प्राथमिकता में जनता की समस्याएं हैं. दरअसल, राजनीतिक दलों का डीएनए खराब हो चुका है. राजनीतिक दलों ने अपना दायित्व भुला दिया है. नेताओं को पता ही नहीं है कि एक राजनीतिक दल की ज़िम्मेदारी क्या होती है? राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ़ सत्ता पाने का माध्यम समझ लिया है. यही वजह है कि सारे दल सिर्फ़ चुनाव के समय जीवंत होते हैं और चुनाव के बाद सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं. दो चुनाव के बीच इनका जनता से अब कोई रिश्ता ही नहीं रहता. जीवंत और क्रियाशील प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के बाद भी जनता से सीधा संवाद रखना ज़रूरी है. कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, जन-जागरण अभियान चलाना, स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों को लामबंद करना आदि कई ज़िम्मेदारियां राजनीतिक दलों की होती हैं.

भारत में राजनीतिक दलों ने यह सब करना छोड़ दिया है. जनता से संवाद वे सिर्फ़ मीडिया के माध्यम से रखते हैं. राजनीतिक दल टीवी चैनलों एवं अख़बारों में बयान देकर और प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी सारी ज़िम्मेदारी से मुक्ति पा लेते हैं. जहां तक बात कार्यकर्ता बनाने की है, तो यह महज पैसे का खेल हो गया है. यह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि उसमें अब विचारधारा का कोई स्थान नहीं रहा. इसलिए जो युवा राजनीति में आते हैं, वे या तो बेरोज़गार होते हैं या फिर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले धनाढ्य होते हैं. हक़ीक़त यह है कि जिसके पास धन है, वह नेता बन जाता है और जो पैसे लेकर पार्टी का काम करता है, वह कार्यकर्ता बन जाता है. ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता ही पार्टी और जनता के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है. जब पैसे लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे, तो पार्टी जनता से कट जाती है. यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने जन-जागरण अभियान चलाना बंद कर दिया है. जन-जागरण का काम भारत में अब सिविल सोसाइटी के ज़िम्मे आ

गया है. राजनीतिक दल जनता से बिल्कुल कट चुके हैं. यही वजह है कि लोगों में निराशा बढ़ी है. बिहार में इसका असर ज़्यादा है. आम तौर पर हर विश्लेषक का मानना है कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा जागरूक है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे कम मतदान हुआ. पूरे देश में लोकसभा चुनाव में 66 प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन बिहार में महज 56 प्रतिशत लोगों ने ही वोट डाले. लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें मात्र 47 प्रतिशत लोगों ने ही मतदान किया. इसका मतलब साफ़ है कि चुनाव को लेकर बिहार की जनता में उत्साह की कमी है.

> जनता जानती है कि इस चुनाव में भी बिहार में धार्मिक उन्माद, जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति का खेल चलेगा. हर राजनीतिक दल उसे ठगने के लिए नए-नए पैंतरे आजमाएगा. यही वजह है कि लोगों में उत्साह नहीं है. राजनीतिक दलों और सरकार चलाने वाले लोगों की ख़ुशनसीबी यह है कि बिहार के लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर नहीं उतरे, इतनी सारी समस्याओं से लड़ते हुए उन्होंने धैर्य नहीं खोया और प्रजातंत्र में अब तक उनका भरोसा कायम है. लेकिन जिस दिन धैर्य का यह बांध टूट गया, तो अनर्थ हो जाएगा.

अब जब बिहार में चुनाव सिर पर हैं, तो राजनीतिक दल सक्रिय हुए हैं. आजकल राजनीतिक दलों के सक्रिय होने का मतलब भी अजीबोग़रीब है. चुनाव की घोषणा से पहले हर दल के नेताओं के होर्डिंग्स लगने लगे हैं, रेडियो-टीवी पर प्रचार आने लगा है, टीवी और अख़बारों में ख़बरें आने लगी हैं. राजनीतिक दलों ने रैलियां करना शुरू कर दिया. कहने का मतलब यह कि राजनीतिक दलों ने पैसा बांटना शुरू कर दिया. हर रैली में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते हैं. इसकी वजह यह है कि राजनीतिक रैलियों में आम जनता ने शामिल होना बंद कर दिया है. राजनीतिक दलों को गाड़ी, खाना-पीना और पैसे देकर लोगों को जुटाना पड़ता है. हालत यह है कि अब इसे ग़लत भी नहीं माना जाता है. चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आएंगे, तमाशा और बढ़ेगा. फिल्मी सितारों को प्रचार में लगाया जाएगा, गांवों-कस्बों में नाच-गाने के कार्यक्रम होंगे और शराब बांटी जायेगी. इन सबसे काम न चला, तो वोट खरीदने का भी काम धड़ल्ले से होगा. फिर विचारधारा, मुद्दे और समस्याएं, सब कुछ पीछे चला जाएगा. चुनाव के दौरान भी राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करते हैं.

बिहार चुनाव के बारे में टीवी चैनलों पर बहस करने वाले राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर वोट के लिए झूठे वादे करने वाले नेता, सब यही कहते नज़र आते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का ऐतिहासिक महत्व है. इसके नतीजे भारतीय राजनीति के भविष्य का फ़ैसला करेंगे. कुछ लोग तो कहते हैं कि यह बिहार का नहीं, बल्कि देश का चुनाव है. अगर बिहार की जनता का फ़ैसला इतना ही महत्वपूर्ण है, तो बिहार के लोगों की समस्याओं को महत्व क्यों नहीं दिया गया? आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा, भूखा और असहाय राज्य क्यों है? क्यों यहां के लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं? बड़ी-बड़ी बातों से ग़रीब का पेट नहीं भरता और आंकड़ों से ज़मीनी हक़ीक़त का पता नहीं चलता. सवाल यह है कि जिस देश में केरल और पंजाब जैसे खुशहाल राज्य हों, वहां बिहार जैसा मेहनतकश राज्य पिछड़ा क्यों है, बदहाल क्यों है? जिस देश में दिल्ली और बंगलुरू जैसे आधुनिक शहर हों, वहां के दूसरे बड़े राज्य बिहार का कोई शहर, शहर जैसा नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? बिहार के लोग रोजी-रोटी की तलाश में देश के कोने-कोने में मौजूद हैं. वे इस विषमता को जानते-देखते हैं और भलीभांति समझते भी हैं. इसके बावजूद कोई महाज्ञानी यह कहे कि बिहार के चुनाव का ऐतिहासिक महत्व है, तो यह मज़ाक के सिवाय कुछ और नहीं है. ये लोग भूल चुके हैं कि प्रजातंत्र में सरकार जन-संसाधन के प्रतिपादन का तंत्र होती है. जनता के बीच संसाधनों और अवसरों का बंटवारा सरकार का सबसे अहम दायित्व है. इससे ही जनता एवं सरकार के बीच विश्वास और सार्थकता का रिश्ता बनता है. अगर बिहार की जनता के हाथ में भारत का भविष्य है, तो देश के संसाधन और आधुनिक मूलभूत सुविधाएं बिहार की जनता के क़दमों में होने चाहिए थे.

आज बिहार की जो हालत है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक दल एवं नेता ज़िम्मेदार हैं. बिहार में कांग्रेस का शासन रहा, लालू यादव ने राज किया, नीतीश कुमार ने सरकार चलाई और भारतीय जनता पार्टी भी सात वर्षों तक सत्ता में रही. इसलिए कोई भी राजनीतिक दल यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उसे मौक़ा नहीं मिला. यही वजह है कि बिहार के लोग निराश हैं, उन्हें किसी से कोई आशा नहीं है. उन्हें पता है कि राजनीति अब समाजसेवा नहीं रही, समाज को बदलने का ज़रिया नहीं रही. हर उम्मीदवार अपने स्वार्थ, ऐशोआराम और सत्ता की भूख मिटाने के लिए चुनाव लड़ता है. इसके लिए हर नेता झूठ और फरेब की हर सीमा लांघने के लिए तैयार है. जनता जानती है कि इस चुनाव में भी बिहार में धार्मिक उन्माद, जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति का खेल चलेगा. हर राजनीतिक दल उसे ठगने के लिए नए-नए पैंतरे आजमाएगा. यही वजह है कि लोगों में उत्साह नहीं है. राजनीतिक दलों और सरकार चलाने वाले लोगों की खुशनसीबी यह है कि बिहार के लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर नहीं उतरे, इतनी सारी समस्याओं से लड़ते हुए उन्होंने धैर्य नहीं खोया और प्रजातंत्र में अब तक उनका भरोसा कायम है. लेकिन जिस दिन धैर्य का यह बांध टूट गया, तो अनर्थ हो जाएगा. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 28
दिल्ली, 14 सितंबर-20 सितंबर 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बस्सी की जगह कौन

दिल्ली के पुलिस आयुक्त पद के लिए अधिकारियों के बीच सबसे ज़्यादा होड़ रहती है. हालांकि, वर्तमान पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को सेवानिवृत्त होने में अभी छह महीने बाकी हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उनकी जगह पर काबिज होने के लिए अभी से ही पुलिस अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से होड़ मच गई है. दरअसल, बस्सी ने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी योजना को लेकर इशारा शुरू कर दिया है और उनका यही इशारा उन सबके लिए अवसर के द्वार खोल रहा है, जो उनकी जगह आने को आतुर हैं. बस्सी के बाद उनके पद के प्रमुख दावेदारों में दो आईपीएस अधिकारियों आलोक कुमार वर्मा और धर्मेंद्र कुमार के नाम सामने आ रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, धर्मेंद्र कुमार के बैचमेट दीपक मिश्रा का नाम भी अन्य मजबूत दावेदारों में है. दिल्ली पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी विमल मेहरा भी बस्सी के साथ ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए उनका नाम इन दावेदारों में नहीं है. सरकार एजीएमयूटी कैडर के अलावा किसी अन्य राज्य के किसी अधिकारी को इस पद पर नियुक्त कर सकती है. इस तरह का निर्णय 1999 में भी लिया गया था, जब एनडीए सरकार ने यूपी कैडर के अधिकारी अजय राज शर्मा को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया था. संभावनाएं कई हैं. देखना दिलचस्प होगा कि अटकलबाजियां किस अधिकारी के नाम पर सच साबित होती हैं. ■

नौकरशाही में बड़े बदलाव

कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने नौकरशाही में बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे. मोदी सरकार का यह प्रयास अतिरिक्त सचिवों एवं संयुक्त सचिवों के वे खाली पद भरने को लेकर था, जिन पर नियुक्त अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे या अपने मूल कैडर में वापस चले गए थे. हालांकि, गृह सचिव एलसी गोयल की जगह राजीव महर्षि की नियुक्ति कुछ आश्चर्य में डालने वाली थी. कुछ लोग गोयल प्रकरण की तुलना उनके पूर्ववर्ती अधिकारी अनिल गोस्वामी से कर रहे हैं,

क्योंकि गोस्वामी के कार्यकाल में भी इसी तरह कटौती कर दी गई थी. हालांकि, उस समय कारण कुछ और थे. इस मसले पर गोयल का कहना है कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना पद छोड़ा है. लेकिन, सूत्रों का कहना है कि गोयल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बदलाव अपने राजनीतिक आकाओं को जानकारी दिए बगैर कर दिया था, इसलिए उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा. गोयल को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के तौर पर महर्षि की नियुक्ति होने से यह बात साफ़ हो जाती है कि मोदी सरकार को उनसे बहुत उम्मीदें हैं. दिलचस्प बात यह है कि 35 अधिकारियों के इस फेरबदल में यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव अनंत कुमार सिंह को पेट्रोलियम मंत्रालय में भेज दिया गया है. अनंत राजनाथ सिंह के विश्वासपात्र हैं और उनका गोयल के साथ कथित तौर पर टकराव चला आ रहा था. गोयल के बाहर होने और महर्षि के अंदर आने से उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा.■

स्थानांतरण से परेशान बाबू

चुनाव का समय हमेशा तनाव लेकर आता है. यह तनाव न सिर्फ़ राजनीतिज्ञों के लिए होता है, बल्कि नौकरशाहों के लिए भी होता है. बिहार में इस समय चुनाव का मौसम है. बाबुओं का तेजी से स्थानांतरण हो रहा है. कभी-कभी तो बिना उन्हें पूरा कारण बताए और सूचना दिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है. इस समय इसमें कुछ नई बात भी नहीं है. हालांकि, नीतीश के शासन में एक स्थानांतरण ऐसा है, जिससे बाबू चिढ़े हुए हैं. हाल में पटना की ज़िलाधिकारी डॉ. प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा का

स्थानांतरण कर दिया गया, जो केवल 26 दिन पहले आई थीं. इस स्थानांतरण से उनके सहयोगी परेशान हैं. ज़िलाधिकारी के तौर पर किसी अधिकारी का राज्य की राजधानी में इतने कम समय का कार्यकाल हो, तो इस तरह का स्थानांतरण सामान्य नहीं माना जाता. हालांकि, परेशान और हतोत्साहित बाबू यह मानकर चल रहे हैं कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, तक तक ऐसा चलता रहेगा. उनका यह भी मानना है कि सरकार को चुनाव आयोग के आगे उस समय तक झुके रहना होगा, जब तक कि चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाते. ■

dilipcherian@gmail..com

गुजरात के कुछ चमचमाते शहरों से गुजरात के हज़ारों गांवों की सही तस्वीर का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है. हार्दिक पटेल की मांग को सही या ग़लत ठहराया जा सकता है, लेकिन इस आंदोलन ने गुजरात की हक़ीक़त को लेकर कुछ सवाल तो ज़रूर उठाए हैं. पाटीदार अनामत (आरक्षण) आंदोलन से आज पूरा गुजरात प्रभावित हुआ है. 12 वर्षों के बाद एक बार फिर वहां अर्द्धसैनिक बलों एवं सेना के जवानों को तैनात करने की नौबत आ गई. आरक्षण की वजह से एक बार फिर गुजरात हिंसा की चपेट में आ गया.

गुजरात पाटीदार आंदोलन

आरक्षण से अलग भी कई सवाल हैं

शशि शेखर

गुजरात, पटेल और आंदोलन की एक अनोखी कहानी है. 41 वर्ष पहले यानी 1974 में गुजरात में एक आंदोलन हुआ था, जिसे बाद में नवनिर्माण आंदोलन कहा गया था. उस समय कांग्रेस के चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे. उक्त आंदोलन अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में भोजन महंगा किए जाने के विरोध में शुरू हुआ था. नतीजतन, चिमन भाई पटेल को इस्तीफ़ा देना पड़ा था. आज 41 वर्ष बाद, एक बार फिर गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ है. इस बार भी एक पटेल यानी आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ़ है पटेल समुदाय, जो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है. इस आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल गुजरात के नए हीरो के तौर पर पेश किए जा रहे हैं. चूंकि आंदोलन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए इसके किसी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

उक्त सवाल गुजरात के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मसलों से जुड़े हुए हैं. मसलन, पटेल समुदाय की छवि न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी काफी संपन्न समुदाय वाली मानी जाती है, लेकिन हार्दिक पटेल का मानना है कि यह छवि आंशिक तौर पर ही सही है. हार्दिक के मुताबिक, गुजरात के पटेलों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, जो व्यवसाय के ज़रिये या अपनी ज़मीनें बेचकर संपन्न हुआ है. वहीं दूसरी तरफ़ बहुसंख्यक पटेल आबादी खेती पर निर्भर है और यहां तक कि खेती में नुक़सान उठाने की वजह से कई पटेलों ने आत्महत्या भी की है. हार्दिक के मुताबिक, बहुसंख्यक पटेलों की आर्थिक हालत खराब है, इसलिए उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है. यहां सवाल आरक्षण देने या न देने का नहीं है, बल्कि उस तस्वीर का है, जो अब तक पटेल समुदाय को लेकर लोगों के मन में थी. दूसरा सबसे अहम सवाल है, गुजरात की छवि को लेकर. गुजरात को भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य बताया जाता रहा है. इसकी तस्दीक वित्तीय एवं औद्योगिक आंकड़े भी करते रहे हैं. इस लिहाज से पिछले कुछ सालों से यह आम धारणा बन गई थी कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है, मूलभूत सुविधाओं के साथ जनता खुश है. लेकिन, हार्दिक पटेल द्वारा आरक्षण की मांग उठाए जाने के बाद अब यह सवाल भी उठता है कि क्या सचमुच वे सारे आंकड़े, जो अब तक दिखाए–बताए जाते रहे हैं, सही हैं? क्या विकास की रोशनी सचमुच गुजरात के हर कोने तक पहुंची है?

ज़ाहिर है, ऐसा नहीं है. गुजरात के कुछ चमचमाते शहरों से गुजरात के हज़ारों गांवों की सही तस्वीर का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है. हार्दिक पटेल की मांग को सही या ग़लत ठहराया जा सकता है, लेकिन इस आंदोलन ने गुजरात की हक़ीक़त को लेकर कुछ सवाल तो ज़रूर उठाए हैं. पाटीदार अनामत (आरक्षण) आंदोलन से आज पूरा गुजरात प्रभावित हुआ है. 12 वर्षों के बाद एक बार फिर वहां अर्द्धसैनिक बलों एवं सेना के जवानों को तैनात करने की नौबत आ गई. आरक्षण की वजह से एक बार फिर गुजरात हिंसा की चपेट में आ गया. पुलिस फायरिंग हुई, कई लोगों की जानें गईं, बसें जलाई गईं और ट्रेनें रोकी गईं. यह सब तब हुआ, जब अहमदाबाद की शांतिपूर्ण रैली निर्धारित समय सीमा के बाद भी चलते देखकर पुलिस वहां उसे रोकने पहुंची. पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया और बलपूर्वक लोगों को वहां से खदेड़ा. इसके बाद कई शहरों में इंटरनेट, व्हाट्स–एप पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि लोगों में संवाद स्थापित न हो सके.

हालांकि, इस आंदोलन के पीछे कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. मसलन, यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है. साथ ही यह भी कि इसके ज़रिये देश से आरक्षण ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है. ऐसी ख़बरें भी आईं कि गुजरात के ही एक पूर्व मंत्री हार्दिक पटेल को पीछे से समर्थन दे रहे हैं. उक्त सारी बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, क्योंकि आम तौर पर हर आंदोलन के पीछे ऐसी बातें कही जाती हैं, जिनमें से कई बार कुछ सही भी होती हैं. लेकिन, पटेल आंदोलन के शुरुआती चरण में ही ऐसी बातों के ज़रिये आंदोलन के पीछे छिपे मूल सवालों को नहीं टाला जा सकता है. मूल सवाल एक बार फिर यही है कि ऐसे क्या कारण हैं, जिनके चलते गुजरात के पटेलों को अपने लिए आरक्षण की मांग करनी पड़ रही है, क्योंकि गुजरात के बाहर तो यही छवि बनी हुई है कि पटेल काफी संपन्न समुदाय है. ज़ाहिर है, पटेल आरक्षण की मांग कहीं न कहीं गुजरात की चमचमाती तस्वीर के पीछे छिपी बदरंग तस्वीर से भी जुड़ी हुई है. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

कौन हैं हार्दिक पटेल

- 22 वर्षीय हार्दिक गुजरात के वीरमगाम के रहने वाले हैं और उन्होंने अहमदाबाद के सहजानंद कॉलेज से बीकॉम (स्नातक) तक शिक्षा ग्रहण की है.
- हार्दिक इससे पहले पाटीदारों के युवा संगठन सरदार पटेल ग्रुप के सदस्य थे.
- हार्दिक ने कुछ समय पहले पाटीदार अनामत (आरक्षण) आंदोलन की नींव डाली और पटेलों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग की.
- गुजरात की कुल आबादी में पटेलों की लगभग 20 फ़ीसद हिस्सेदारी है.
- पाटीदार समुदाय के लोग खुद को भगवान श्रीराम का वंशज कहते हैं. उनके मुताबिक, वे श्रीराम के बेटे लव एवं कुश की संतान हैं.
- पाटीदारों की चार मुख्य जातियों में से लेउवा और कडवा पाटीदार को आरक्षण नहीं मिला है.
- हार्दिक पटेल कडवा पाटीदार समुदाय के हैं.

कितना कारगर होगा विज़न डॉक्यूमेंट

शफीक आलम

बिहार विधानसभा चुनाव अब बिलकुल नज़दीक आ चुके हैं. राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए हर तरह के दांव आज़मा रहे हैं. वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव को काफी अहमियत दे रहे हैं. उनके मुताबिक, देश की भविष्य की राजनीति पर इस चुनाव के नतीजों का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है. इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक राज्य में चार चुनावी सभाएं–रैलियां कर चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ़ महा–गठबंधन, जिसमें सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस शामिल हैं, भी पटना में एक रैली कर चुका है. हालांकि, अभी तक किसी भी गठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा–पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन दोनों तरफ़ से मतदाताओं, खास तौर पर युवाओं को लुभाने के प्रयास जारी हैं. जहां एक तरफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आरा रैली में बिहार के लिए एक लाख 65 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज देने की घोषणा की, वहीं इसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी विकसित बिहार के सात सूत्र नाम से अपना विज़न डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें उन्होंने अगले पांच वर्षों के अपने कार्यों और उन पर आने वाली लागत का एक खाका पेश किया. आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह विज़न क्या है? इसमें उन्होंने जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया भी जा सकता है या ये महज़ चुनावी वादे हैं? इन वादों में क्या नया है और क्या पुराना? जो पुरानी योजनाएं हैं, उन पर क्या प्रगति हुई है?

नीतीश कुमार के इस सात सूत्रीय विज़न डॉक्यूमेंट में युवाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्किल डेवलपमेंट, विद्यालयों–कॉलेजों में मुफ्त वाई–फाई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना, 24 घंटे बिजली आपूर्ति और शौचालय निर्माण आदि कार्य शामिल हैं. उनके मुताबिक, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 2.70 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. अब सवाल यह उठता है कि क्या इन कार्यक्रमों के लिए नीतीश कुमार बजट आवंटित कर सकते हैं? वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के लिए बिहार सरकार ने 57 हज़ार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. इस बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, समाज कल्याण जैसे कार्यक्रम शामिल थे, जिनका संबंध सात सूत्रीय विज़न डाक्यूमेंट में शामिल कर्यक्रमों से भी है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में 2.70 लाख करोड़ रुपये की राशि मुहैया करा सकते हैं.

जहां तक महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, तो राज्य में शिक्षकों एवं पुलिस की भर्ती में महिलाओं को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार का योगदान नकारा नहीं जा सकता. उन्होंने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना चलाई, जिसकी वजह से स्कूलों से न केवल लड़कियों का ड्राप रेट कम हो गया, बल्कि आज लड़कियां लड़कों की तरह साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं, जिसकी कल्पना आज से 10–15 वर्ष पूर्व बिहार में कोई नहीं कर सकता था. जहां तक बसावटों में बिजली पहुंचाने की बात है, तो इसमें भी नीतीश कुमार का रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं है. हालांकि, राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 144 किलोवाट है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है. जहां तक बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर का सवाल है, तो पिछले वर्षों में इसमें भी कमी आई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 39,000 बसावटों में से 36,000 को बिजली से जोड़ा जा चुका है. ज़ाहिर है, अगले पांच वर्षों में बाकी बसावटों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना दूर की कौड़ी नहीं है. लेकिन, हर किसी के लिए नल का पानी मुहैया कराना मुश्किल है. शौचालय निर्माण भी एक अभियान के तहत चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहयोग कर रही है, इसलिए यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

नीतीश कुमार बार–बार कह चुके हैं कि राज्य में भले ही खनिज संपदा का अभाव है, लेकिन हमारे पास मानव संपदा है, जो बिहार की सबसे बड़ी पूंजी है. युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, टेक्निकल, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज का प्रस्ताव और शिक्षा ऋण आदि अच्छे वादे हैं. अगर इनमें थोड़ी–बहुत प्रगति होती है, तो भी अच्छा है. अगर पूरी तरह से इनका कार्यान्वयन होता है, तो और भी अच्छा है. लेकिन, मुफ्त वाई–फाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसे वादे चुनावी वादे प्रतीत होते हैं. जहां तक मुफ्त वाई–फाई की सुविधा का सवाल है, तो इसका कोई खास लाभ युवाओं को नहीं होने जा रहा है. दरअसल, यह वादा राज्य के 80 लाख युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया है. वहीं मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी भी चुनावी वादे हैं, जिन्हें पूरा करना मुश्किल है. यदि उन्हें पूरा किया भी गया, तो कुछ न कुछ शर्तें ज़रूर लागू होंगी. दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग नीतीश कुमार के मुफ्त बिजली और मुफ्त वाई–फाई के वादे को उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हालिया मुलाकातों से जोड़कर देख रहे हैं.

बहरहाल, नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे राजनेता की है, जिन्होंने बिहार जैसे पिछड़े राज्य को प्रगति की राह पर ला खड़ा किया. उनके शासनकाल में बिहार की विकास दर 10 प्रतिशत के ऊपर थी. राज्य में क़ानून व्यवस्था की स्थिति में उन्होंने उल्लेखनीय सुधार किया और लोगों में उम्मीद जगाई कि बिहार भी देश के दूसरे राज्यों की तरह विकास कर सकता है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य के चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले कई चुनावों से उनके साथ थी, अब उनके लिए चुनौती पेश कर रही है. वहीं राजद, जो पहले विपक्ष में था, अब उनके साथ है. नीतीश कुमार के इस 2.70 लाख करोड़ के विज़न डॉक्यूमेंट को नरेंद्र मोदी के 1.65 लाख करोड़ के पैकेज के जवाब में भी देखा जाना चाहिए. एक दूसरी आपत्ति नीतीश कुमार पर यह लगाई जा रही है कि उनकी पार्टी जदयू केवल 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ज़ाहिर है, अगर वह अपनी सभी सीटें जीत भी जाती है, तब भी सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना आवश्यक होगा. जब नीतीश कुमार अपना विज़न डॉक्यूमेंट जारी कर रहे थे, तो उनके गठबंधन के किसी घटक का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था. बहरहाल, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये वादे पूरे भी होते हैं या नहीं? और, जब गठबंधन का घोषणा–पत्र जारी होगा, तो उसमें विज़न डॉक्यूमेंट का ज़िक्र होता है या नहीं? लेकिन, हालिया अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस तरह के लोक–लुभावन वादों को चुनाव जीतने के बाद पूरा करने की कोशिश शायद ही होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुख्य बिंदु

1. विद्यालयों एवं कॉलेजों में मुफ्त वाई–फाई की सुविधा, 20 से 25 वर्ष के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार तलाश करने के लिए दो बार नौ महीने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता.
2. 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना और उसके ब्याज में तीन प्रतिशत की सहायता देना. युवाओं को स्व–रोज़गार और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड मुहैया कराना.
3. राज्य के सभी ज़िलों में रोज़गार परामर्श केंद्र की स्थापना, भाषा एवं संवाद कौशल और कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराना.
4. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान.
5. सभी गांवों और बसावटों तक बिजली पहुंचाना, सभी घरों में बिजली का कनेक्शन, 24 घंटे बिजली आपूर्ति.
6. हर घर में नल का पानी पहुंचाना.
7. हर घर तक पक्की गली और सड़क
8. शौचालय निर्माण कार्यक्रम के तहत एक करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण.
9. तकनीकी–उच्च शिक्षा के लिए पांच मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना.
10. इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन पर 2.70 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.

संभावित ख़र्च

मद	राशि (करोड़ में)
युवा	49,800
पाइप जलापूर्ति	47,700
हर घर बिजली	55,600
पक्की सड़कें	78,000
मेडिकल कॉलेज	10,300
घरेलू शौचालय	28,700
कुल	2,70,100

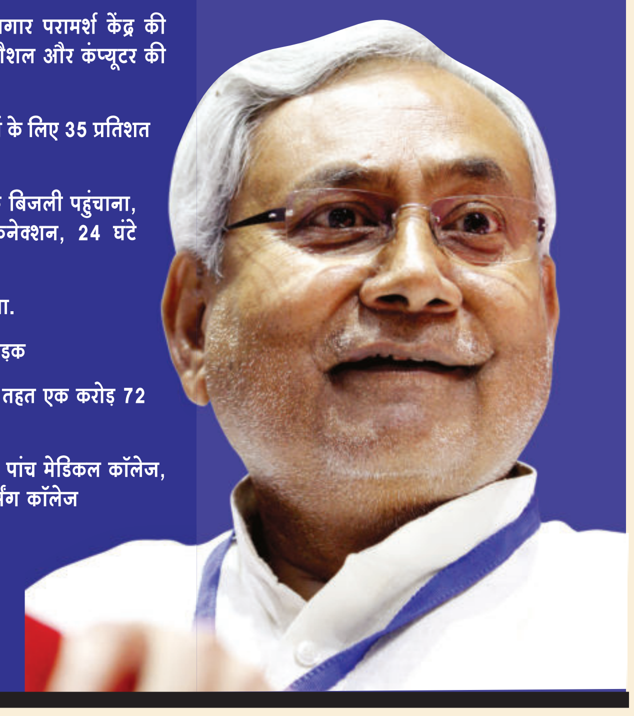

स्वाभिमान रैली में अपेक्षा के अनुरूप माय सामाजिक समूहों की भागीदारी राज्य के अन्य सामाजिक समूहों से काफी अधिक दिख रही थी, लेकिन अति पिछड़े एवं दलित (महादलित) सामाजिक समूहों की मौजूदगी अपेक्षाकृत काफी कम रही. मंच भी इससे इतर आभास नहीं दे रहा था. महा-गठबंधन की यह रणनीतिक सफलता तो नहीं कही जा सकती. बिहार में पिछले कई चुनावों से सामाजिक समूहों की राजनीतिक गोलबंदी साफ़ दिखती रही है.

महा-गठबंधन की स्वाभिमान रैली

हीरो और विलेन दोनों रहे लालू

यह रैली बिहारी स्वाभिमान के सवाल को लेकर आयोजित थी, लिहाजा वक्ताओं का ज़ोर उस पर ज़्यादा रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्वाभिमान के साथ-साथ अपने दस वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों और सुशासन को अपने भाषण का मुद्दा बनाया.

चौथी दुनिया ब्यूरो

विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पटना के गांधी मैदान की यह पहली और शायद आख़िरी राजनीतिक रैली रही. महा-गठबंधन में शामिल दलों के आह्वान पर आयोजित यह स्वाभिमान रैली भीड़ के लिहाज से हाल के वर्षों की बड़ी रैलियों में गिनी जाएगी. राजधानी के विभिन्न इलाकों की सड़कों पर रैली में भाग लेने वालों का हुजूम देखा गया. राज्य के सुदूर अंचलों से लोग आए, अपने नेताओं के आवास पर रहे, गांधी मैदान एवं अन्य सड़कों पर छाए रहे और फिर वापस लौट गए. महा-गठबंधन की यह बहु-प्रतीक्षित और बहु-प्रचारित रैली अपने तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य यानी विधानसभा चुनाव का ताप परवान चढ़ाने में कामयाब रही. रैली की सबसे बड़ी राजनीतिक परिघटना इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति मानी जा सकती है. रैली में उनकी मौजूदगी को लेकर कई नकारात्मक कयास लगाए जा रहे थे, पर चुनावी राजनीति ने सभी कयासों को धता बता दिया. बिहार की धरती पर सोनिया गांधी पहली बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ एक मंच पर मौजूद थीं. सोनिया ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तो हमले किए ही, सांप्रदायिकता को भी अपना निशाना बनाया. उन्होंने मोदी सरकार पर केवल शो-बाजी करने का आरोप लगाया. इस लिहाज से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का राष्ट्रीय महत्व गंभीर रूप से रेखांकित किया. यह रैली बिहारी स्वाभिमान के सवाल को लेकर आयोजित थी, लिहाजा वक्ताओं का ज़ोर उस पर ज़्यादा रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्वाभिमान के साथ-साथ अपने दस वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों और सुशासन को अपने भाषण का मुद्दा बनाया. राजद प्रमुख

ने एक बार फिर पुरज़ोर तरीके से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशन का मुद्दा तो उठाया ही, अपनी राजनीति के अनुरूप पिछड़ा कार्ड और मंडल की राजनीति को चुनावी मुद्दा बनाने की हरसंभव कोशिश की. पिछड़ों को गोलबंद करने के अघोषित एजेंडे के फ्रंट पर यह रैली सफल रही, इसमें शक है. लालू प्रसाद के आह्वान पर आयोजित रैलियों की एक खासियत रही है कि उनमें ग़रीबों-वंचितों का सैलाब उमड़ता रहा है, लेकिन इस बार ऐसे चेहरे कम थे. शहरी बिहार के साथ-साथ ग्रामीण बिहार के चेहरे तो थे, पर वैसे चेहरे काफी कम थे, जो अमूमन लालू प्रसाद की रैलियों में हुआ करते हैं. लालू प्रसाद की रैलियों में बिहार के अगड़े सामाजिक समूहों की भागीदारी बहुधा कम होती रही है, इस बार भी यही हुआ. स्वाभिमान रैली में अपेक्षा के अनुरूप माय सामाजिक समूहों की भागीदारी राज्य के अन्य सामाजिक समूहों से काफी अधिक दिख रही थी, लेकिन अति पिछड़े एवं दलित (महादलित) सामाजिक समूहों की मौजूदगी अपेक्षाकृत काफी कम रही. मंच भी इससे इतर आभास नहीं दे रहा था. महा-गठबंधन की यह रणनीतिक सफलता तो नहीं कही जा सकती. बिहार में पिछले कई चुनावों से सामाजिक समूहों की राजनीतिक गोलबंदी साफ़ दिखती रही है. इस बार यह गोलबंदी अधिक तीखी होती दिख रही है. लेकिन, इस गोलबंदी के दौर में भी अति पिछड़ों के अधिकांश समूह राजनीतिक तौर पर किसी राजनीतिक गोल से बाहर हैं.

कुछ समूहों को अपवाद मान लें, तो दलित (महादलित) सामाजिक समूहों के बहुमत का भी यही हाल है. सूबे में अति पिछड़ों की 32 और दलित (महादलित) की 14 प्रतिशत से अधिक आबादी है. संयोग से महा-गठबंधन के नेतृत्व ने इन

बिहार चुनाव विशेष बिहार चुनाव

मतदाता समूहों को अपने साथ जोड़ने का स्पष्ट राजनीतिक संदेश नहीं दिया. सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव की महत्ता रेखांकित की, तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. इसके अलावा उन्होंने महिलाओं एवं युवाओं को साधने की हरसंभव कोशिश की. राजद प्रमुख ने पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश में माय और विशेषकर, यदुवंशियों तक स्वयं को सीमित रखा, लेकिन वह मंडल राजनीति के दायरे के सामाजिक समूहों को समग्रता में कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे सके. रैली में युवाओं की भागीदारी तो कम थी ही, जोश से भरे नव-मतदाता समूहों (पहली या दूसरी बार मतदाता बने युवा) की कमी साफ़ दिखी. माना जाता है कि बिहार में छह करोड़ से अधिक मतदाताओं में 60 प्रतिशत से अधिक युवा वर्ग के हैं, जो चुनावी माहौल सरगर्म करते हैं. इसी समूह से राजनीतिक दलों को चुनावी कार्यकर्ता उपलब्ध होते हैं और यही समूह बूथ पर वोटों की रक्षा करता है. सो, इस मतदाता समूह को आकर्षित करने के उपाय होने ही चाहिए. यह कहना अनुचित होगा कि महा-गठबंधन में युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति का अभाव है. उसके साथ युवा हैं, उत्साह और जोश से भरे युवा हैं, लेकिन रैली में इसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई. रैली का एक कृष्ण पक्ष लालू वंश का राजनीतिक सम्मान भी रहा. राबड़ी देवी सहित लालू प्रसाद के परिवार के कोई आधा दर्जन चेहरे मंच पर उपस्थित थे, चहलक़दमी कर रहे थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पैसा और पावर का खेल है चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव आगामी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बिहार विधानसभा-2010 के आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों एवं विधायकों की एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. आइए एक नज़र डालते हैं, एडीआर के आंकड़ों पर...

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बिहार इलेक्शन वाच के अनुसार, 2010 के विधानसभा चुनाव में 3,523 उम्मीदवारों में से 2,235 ने हलफनामा दिया था, जिनमें से 797 (36 प्रतिशत) उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में उन पार्टियों का भी जिक्र किया है, जिनके उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन है. मसलन, भाजपा के 102 उम्मीदवारों में से 66 (55 प्रतिशत), लोक जनशक्ति पार्टी के 75 में से 42 (56 प्रतिशत), कांग्रेस के 240 में से 92 (38 प्रतिशत), बसपा के 232 में से 89 (38 प्रतिशत) और एनसीपी के 106 में से 30 (28 प्रतिशत) उम्मीदवार ऐसे थे, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 497 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन पर हत्या, अपहरण, डकैती, जबरन वसूली जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें बसपा के 58, जदयू के 53, कांग्रेस के 46, राजद के 46, भाजपा के 29 और लोजपा के 23 उम्मीदवार शामिल हैं.

एडीआर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि हलफनामा देने वाले 2,235 उम्मीदवारों में से 227 (10 प्रतिशत) उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और 12 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है. इनमें से 263 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक बताया. रिपोर्ट में राज्य की विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की औसतन कुल संपत्ति का भी जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार, राजद के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति एक करोड़ रुपये रही, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों की 94 लाख, जदयू के उम्मीदवारों की 85 लाख, लोजपा के उम्मीदवारों की 80 लाख और भाजपा के उम्मीदवारों की 66 लाख रुपये. 2,235 में से 1,440 (64 प्रतिशत) ने अपने पैनकार्ड का ब्यौरा नहीं दिया. 308 महिला उम्मीदवारों ने भी अपने पैनकार्ड का ब्यौरा नहीं दिया. एडीआर की रिपोर्ट में इन उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का भी जिक्र किया गया है. 2,235 उम्मीदवारों में से 1,001 (45 प्रतिशत) की शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे ज़्यादा है. ■

भागलपुर रैली

माय समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश

कोसी और पूर्वी बिहार में अपनी ख़राब हालत भाजपा शीर्ष नेतृत्व की निगाह में सबसे अहम मुद्दा है. हालांकि सीमांचल में थोड़ी बेहतर स्थिति होने के बावजूद पार्टी के शीर्षस्थ नेता कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं. मोदी की रैली में महादलितों, यादवों और अल्पसंख्यकों की मौजूदगी पर विपक्षी गठबंधन की भौंहें तन सकती हैं. दरअसल भाजपा ने कोसी और पूर्वी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने और माय समीकरण को जोड़ने में पूरी ताकत झोंक दी है. पढ़िए भागलपुर रैली के निहितार्थों पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट-

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार चुनाव में एक-दूसरे के आमने-सामने दोनों विपक्षी गठबंधनों में बड़ी रैलियां करने की होड़ मची है. दोनों ही गठबंधन अपनी रैलियों को सफल बनाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं. पटना में महागठबंधन की रैली के बाद भागलपुर में नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली पर सबकी नज़र टिक गई थी. मोदी अच्छे वक्ता हैं और अपनी रैलियों में भीड़ खींचने की ताकत भी रखते हैं. ऐसा हुआ भी. भागलपुर में बड़ा जनसैलाब उन्हें सुनने आया. उनकी रैली में उमड़ी भीड़ के पीछे भी कई कारण हैं. इसकी एक वजह पटना में हुई महागठबंधन की रैली में मोदी के ख़िलाफ़ हुई ज़बरदस्त बयानबाज़ी भी मानी जा रही है. पटना रैली में लालू यादव द्वारा किए प्रत्येक व्यंग्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैली में दिया.

इस रैली से पूर्वी बिहार और सीमांचल की राजनीति असर पड़ सकता है. रैली में भारी संख्या में महादलितों, यादवों और ठीक-ठाक संख्या में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी ने यह जता दिया कि लालू यादव के आधार वोट बैंक माय समीकरण में सेंध लगनी शुरू हो गई है. उन्हें माय समीकरण को बरकरार रखने में खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है. मोदी की रैली में अल्पसंख्यकों की मौजूदगी विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात रही. अल्पसंख्यकों को रैली तक खींच के लाने के पीछे शाहनवाज़ हुसैन और अफ़ज़र शमशी को श्रेय दिया जा रहा है. रैली के माध्यम से कोसी और सीमांचल को साधने की कोशिश की गई. शीर्ष भाजपा नेताओं ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा. दरअसल असदुद्दीन आवैसी की एंट्री और पप्पू यादव के मैदान में कूदने के बाद सीमांचल और कोसी का राजनीतिक समीकरण विल्कुल बदल गया है. ऐसे समय में भाजपा के लिए इस रैली का सफल होना मायने रखता है.

अब रैली के इंपैक्ट पर चर्चा करते हैं. किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार

सीमांचल क्षेत्र में आते हैं. यहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है. वहीं कोसी के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा और सुपौल आते हैं. यहां यादव निर्णायक भूमिका में है. ऐसे में मोदी ने जातिवाद और सांप्रदायिकता का जुमला छोड़कर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की.

दरअसल इस क्षेत्र में भाजपा की साख पूरी तरह दांव पर लगी है. पूर्वी बिहार, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, के भागलपुर, मुंगेर और बांका में पिछले लोक सभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था. कमोवेश वही स्थिति कोसी और सीमांचल में भी है. आश्चर्य की बात है कि सीमांचल इलाके, जहां मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत से भी अधिक है, में भाजपा सेफ जोन में है. यहां 24 विधान सभा सीटों में से 13 पर भाजपा का कब्ज़ा है. कोसी और पूर्वी बिहार में पप्पू यादव का खासा प्रभाव है. भाजपा की रणनीति है कि अगर पप्पू यादव से किसी तरह की बात बनती है तो पूर्वी बिहार और कोसी में अपने खोये जनाधार को फिर से हासिल किया जाए. वहीं सीमांचल में ओवैसी के चुनावी जंग में कूदने के बाद अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने के भी ठोस रणनीति की जा रही है. रैली में मोदी द्वारा पेश किए गए आंकड़े भले ही जनता के समझ मे नहीं आए, लेकिन कार्यकर्ता यह अवश्य समझ गए कि अगर किला फतह करना है तो इन क्षेत्रों में जम कर पसीना बहाना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कालीमठ घाटी की बात करें, तो आपदा के दौरान कुणजेठी तल्ली गांव के निचले हिस्से में सरस्वती नदी के कटाव के कारण गुप्तकाशी–कालीमठ–चौमासी मोटर मार्ग का लगभग दो सौ मीटर तक नामोनिशान मिट गया था. साथ ही 15 आवासीय भवन आपदा की भेंट चढ़ गए थे. गांव के ऊपरी हिस्से में बीस मीटर चौड़ी और दो सौ मीटर लंबी दरार पड़ने से कुणजेठी तल्ली गांव भी ख़तरे की जद में आ गया.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

मौलाना आज़ाद चेयर के साथ धोखाधड़ी

फ़िरोज़ बख़्त अहमद

भारत के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना आजाद चेयर के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले दिनों काफी गैरजिम्मेदाराना और लापरवाही वाला बर्ताव सामने आया. इसकी तस्दीक आरटीआई से मिले दस्तावेज भी करते हैं. पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2009 में 6 विश्वविद्यालयों में मौलाना आजाद चेयर प्रदान की, जिनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम प्रमुख हैं. जब जामिया को मौलाना आजाद चेयर प्रदान की गई तो विश्वविद्यालय में बिना जांच–पड़ताल के इसे 2009 से 2014 तक अर्थात् 5 वर्ष तक एक ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दिया गया, जिसने इस अवधि में देश के इस सपूत पर एक पृष्ठ का भी कार्य नहीं किया और लगभग सवा लाख रुपये प्रति मास से भी अधिक की मोटी रकम वह डकारता रहा. मजे की बात तो यह है कि इस व्यक्ति का संबंध जामिया के फोटोग्राफी विभाग से है और मौलाना आजाद शोध से इसका दूर–दूर तक कुछ लेना–देना नहीं है. विश्वविद्यालय में कोई कहने–सुनने वाला नहीं. उर्दू की यह कहावत बिल्कुल सही उतरती है कि माल–ए–मुफ्त दिल–ए–बेरहम!

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी मान्य व्यक्ति के नाम में चेयर का संस्थापन इसलिए करता है, ताकि भावी पीढ़ियों को इस व्यक्ति का योगदान याद रहे. इसी प्रकार से जब जामिया को मौलाना आजाद चेयर प्रदान की गई तो इसमें कहा गया था कि यह एक ऐसे व्यक्ति को मौलाना पर शोध कार्य के लिए यह कुर्सी दी जाए, जो समाज में गणमान्य हो. साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से एक कमेटी उप कुलपति की निगरानी में बनाई जाती है, जिसमें विशिष्ठ प्रतिनिधि चेयर पर विस्थापित होने वाले व्यक्ति का चयन करते हैं. जामिया में यह सब नहीं किया गया. साथ ही, पांच वर्ष पूर्ण होने पर एक कमेटी इस शोध कार्य की जांच करती है कि यह ठीक तौर से हुआ या नहीं. बिना किसी चयन कमेटी के जामिया के फोटोग्राफी विभाग के फरहत बसीर खान को मौलाना आजाद चेयर पर विस्थापित कर दिया गया. इसके अतिरिक्त अवधि पूरी होने पर किसी ने नहीं देखा कि क्या काम हुआ है. जो व्यक्ति भी किसी चेयर पर कार्यरत होता है, उसे पांच साल तक कम से कम 1.25 लाख प्रतिमास का वेतन तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ उसे और अलग से भी 'पर्क्स' भी दिए जाते हैं.

जब सूचना का अधिकार के अन्तर्गत इस लेखक ने 23 जुलाई, 2015 को जामिया को चिट्ठी में छः प्रश्न लिखे तो एक महीना चार दिन गुजर जाने के बाद (जबकि एपिलेट अथॉरिटी को दूसरी चिट्ठी देने का समय होता है) जामिया से 27 अगस्त 2015 को जवाब आया, जिसमें केवल तीन प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया. मगर इससे इस बात का पता चल गया कि 5 वर्ष तक मौलाना आजाद चेयर पर कार्यरत व्यक्ति ने 2009 से 2014 तक कोई भी कार्य नहीं किया, यहां तक कि एक पृष्ठ भी नहीं लिख कर दिया मौलाना आज़ाद पर!

वास्तव में जब जामिया से ही इस प्रकार की शिकायतें आने लगीं कि इस चेयर पर कुछ भी नहीं हुआ तो इन पंक्तियों के लेखक ने जांच–पड़ताल कर इस बात का निर्णय लिया कि अब न्यायालय का सहारा लेना आवश्यक है. यूजीसी के 25 जुलाई 2011 के पत्र के अनुसार इस चेयर पर कार्य करने के लिए 33.10 लाख रुपये की राशि जामिया को प्रदान कर दी गई थी. इसका अर्थ यह हुआ कि मात्र आजाद चेयर पर कार्य करने के लिए 5 वर्ष में लगभग एक करोड़ 55 लाख रुपए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए और बदले में शोध कार्य टांय–टांय फिस्स या कपिल शर्मा की भाषा में बाबा जी का ठुल्लू!

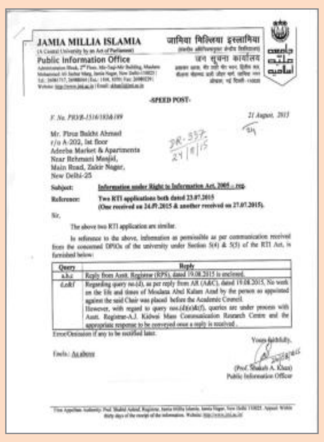

एक और मजे की बात यह है कि यूजीसी ने जामिया में आजाद चेयर के अतिरिक्त और कई चेयर्स भी दी, जिनमें एम के गांधी चेयर डॉ सुजीत दत्ता को दी गई, सैफुद्दीन किचलू चेयर संजॉय हजारिका को दी गई, सज्जाद जहीर चेयर शोहिनी घोष को दी गई (जिनको उर्दू का अलिफ, बे, ते तक नहीं आती), फोर्ड फाउंडेशन चेयर वीणा सीकरी एवं ए एम ख्वाजा चेयर डॉ विनय लाल को दी गई. अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इन सभी कुर्सियों पर कोई भी कार्य नहीं हुआ. हो सकता है कि ये घोटाले बाद में सामने आएं. जिन वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने इन चेयर्स पर उपर्युक्त नामी व्यक्तियों को अधीन किया, उनमें नामचीन लोग शामिल हैं जैसे–प्रो एस इनायत ए जैदी (डीन, भाषा विभाग), प्रो देवी सिंह (अध्यक्ष, आईआईटी, कानपुर) और डॉ मुकुल केसवन (इतिहास विभाग, जामिया). अब इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किये जाने पर विचार किया जा रहा है. ■

(लेखक शिक्षाविद् और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पौत्र हैं)

feedback@chauthiduniya.com

दूषित पानी से विकलांग हो रहे हैं खैरावासी

कुमार कृष्णन feedback@chauthiduniya.com

आखिर कब तक नसीब होगा खैरा के लोगों को शुद्ध जल, यह सवाल यहां का हर नागरिक पूछ रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारा है–न्याय के साथ विकास, लेकिन खैरा का न तो विकास हुआ और न ही यहां के लोगों को इंसाफ मिला. जल के जहर होने से यहां के लोग विकलांगता का दंश झेलने को विवश हैं. मुख्यमंत्री यह कहते आए हैं कि हर इंसान को स्वच्छ जल मिलना चाहिये. उन्होंने 2010 में विश्वास यात्रा के दौरान मुंगेर जिला के खैरा गांव का दौरा किया था तो पूरे गांव को फ्लोराइड से प्रभावित पाया था. उन्होंने 5 जून, 2010 को विश्वास यात्रा के क्रम में करोड़ों रुपयों की राशि से जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया था. इस काम को दो वर्षों में यानी 2012 में पूरा करना था. काम की जिम्मेदारी पुंजलाइट कंपनी को दी गयी. पांच साल पूरे होने पर भी यह योजना पूरी न हो सकी. लिहाजा, यहां के लोगों के लिए जल अमृत नहीं, अभिशाप बन गया है. इससे बड़ी लापरवाही और शासन व्यवस्था के लचर होने का प्रमाण और क्या हो सकता है कि पांच साल पूरे होने पर भी योजना पूरी नहीं हो पायी.

योजना के अनुसार, खड़गपुर झील से खैरा तक शुद्ध पेयजल खैरावासियों को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों के उदासीन रवैयों के कारण आज तक झील का पानी खैरा गांव नहीं पहुंच पाया. पुंजलाइट कंपनी द्वारा झील में इंटेक वेल का निर्माण कराया जा रहा था. इंटेक वेल से झील के निचले भाग से पानी पहुंचाने के लिए केमिकल हाउस बनाया गया है. इंटेक वेल से केमिकल हाउस तक पानी आना है. इसके लिए न तो सिंचाई विभाग से और न ही वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया. अनापत्ति प्रमाण पत्र के पचड़े में यह मामला फंस कर रह गया है. इस तरह इंटेक वेल से केमिकल हाउस तक पानी लाने के लिए पाइप बिछानी होगी. खड़गपुर–जमुई मार्ग पर स्थित मणी नदी पर खंभे के जरिए पाइप बिछाने में समय तो लगेगा ही और समस्याएं बढ़ेंगी.

कार्य की शिथिलता के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समक्ष मामला संज्ञान में आने पर काम करनेवाली ऐजेंसी पुंजलाइट को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था. इससे पहले स्थानीय लोगों ने प्रशासन के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया था. इस कंपनी ने सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले लिया था. बिहार सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है. बिहार सरकार की ओर से इस आशय का शपथपत्र दायर किया गया. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुंजलाइट कंपनी को पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा. पटना उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया. अबतक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया है.

योजना के अनुसार, खड़गपुर झील से खैरा तक शुद्ध पेयजल खैरावासियों को एक वर्ष के भीतर उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों के उदासीन रवैयों के कारण आज तक झील का पानी खैरा गांव नहीं पहुंच पाया. पुंजलाइट कंपनी द्धारा झील में इंटेक वेल का निर्माण कराया जा रहा था. इंटेक वेल से झील के निचले भाग से पानी पहुंचाने के लिए केमिकल हाउस बनाया गया है.

जिस समय कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, उस समय योजना का काम बंद था. बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 14 करोड़ रुपये की लागत से निविदा निकाली गयी. निकाले गए निविदा पर किसी भी कंपनी ने कार्य के लिए निविदा भरा नहीं. अब तीसरी बार निविदा निकाली गयी और उसकी राशि बढ़ाकर 18 करोड़ रुपये कर दी गयी है. योजना में बार–बार हो विलंब के सवाल पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता सरयुग राम कहते हैं कि तीसरी बार निविदा निकाली गयी है, अगर कोई निविदा नहीं डालता है तो वैसी स्थिति में विभाग स्वयं काम कराएगा.

फ्लोराइड नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है. रमनकाबाद पंचायत का खैरा गांव फ्लोराइड की चपेट में है. इस गांव के लोगों के लिए जल जीवन नहीं मौत है. दूषित जल के सेवन से कई अपंग हो गए, तो कई असमय ही काल के गाल में समा गए. स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के मुताबिक, 2010 में ही गांव के 70 लोगों को विकलांग घोषित किया गया है. मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर का खैरा गांव फ्लोराइड से सबसे अधिक प्रभावित है. भू–जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाए जाने के कारण अनेक शारीरिक व्याधियां पैदा हो गई हैं. लोग समय से पहले बूढ़े लगने लगे हैं. फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण यहां के लोगों को खड़ा होने, चलने, दौड़ने या बोझ ढोने में कठिनाई एवं पीड़ा हो रही है. लोगों का कहना है कि उनकी हड्डियों के जोड़ें सख्त हो रही हैं तथा हड्डियों, गर्दन एवं जोड़ों में तेज दर्द रहता है. दन्त फ्लोरोसिस नामक बीमारी भी यहां के बच्चों में देखने को मिल रहे हैं. दन्त फ्लोरोसिस मुख्यतः बच्चों की बीमारी है. फ्लोराइड युक्त पेयजल के लगातार इस्तेमाल से यह बीमारी आठ–नौ वर्ष की उम्र से दिखने लगती है. इस बीमारी में बच्चों के स्थायी दांत गन्दे एवं क्षैतिज पीली धारी से युक्त दिखते हैं. क्या यह मानवाधिकार का सवाल नहीं है? आखिर जीने के हक़ से क्यों सरकार वंचित करना चाहती है? कुल मिलाकर यह व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. ■

उत्तराखंड

आपदा प्रभावित गांवों को भूल गई सरकार

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

केदार घाटी और कालीमठ में वर्ष 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के जख्म आज भी ताजे हैं. आपदा प्रभावित कई गांव ऐसे हैं, जहां के निवासी ख़तरे के साये में ज़िंदगी बिता रहे हैं. इन प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं किए गए. कालीमठ घाटी के कुणजेठी तल्ली गांव के ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार की मरम्मत आज तक नहीं हो सकी. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2013 में केदार घाटी, कालीमठ घाटी एवं मदमहेश्वर घाटी के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदा से कई गांवों को भारी नुक़सान पहुंचा था. आपदा के दौरान कई गांवों के ऊपरी और निचले हिस्सों में दरारें पड़ गई थीं. मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी के किनारे भू–कटाव होने के कारण कई गांव ख़तरे की जद में आ गए थे. नदियों के किनारे सुरक्षा दीवारों का निर्माण न होने से आज भी भू–कटाव जारी है. आपदा प्रभावित सेमी गांव की हालत बहुत दयनीय है. इस गांव के प्रत्येक घर में मोटी–मोटी दरारें पड़ी हैं. साथ ही गांव लगातार नीचे की ओर धंस रहा है. तीन परिवार गांव से पलायन भी कर चुके हैं. अभी भी 60 परिवार गांव में मौजूद हैं. शासन–प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, किसी तरह की सहायता का कोई नामोनिशान नहीं है. आपदा के बाद यह गांव विस्थापन सूची में दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक यहां के लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकी. पूर्व ग्राम प्रधान कुंवरी बर्त्वाल ने कहा कि शासन–प्रशासन गांव सेमी की उपेक्षा कर रहा है. यदि कहीं भूकंप का एक बड़ा झटका आ गया, तो पूरा गांव मलबे में तब्दील हो जाएगा. आपदा के चलते खेत–खलिहान भी नष्ट हो चुके हैं. मंदाकिनी नदी के किनारे लगातार भू–कटाव के चलते केदार नाथ हाईवे के साथ–साथ सेमी गांव भी नदी की ओर धंस रहा है. गौशाला क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों ने अपने मवेशियों को सड़क के किनारे बांध रखा है.

कालीमठ घाटी की बात करें, तो आपदा के दौरान कुणजेठी तल्ली गांव के निचले हिस्से में सरस्वती नदी के कटाव के कारण गुप्तकाशी–कालीमठ–चौमासी मोटर मार्ग का लगभग दो सौ मीटर तक नामोनिशान मिट गया था. साथ ही 15 आवासीय भवन आपदा की भेंट चढ़ गए थे. गांव के ऊपरी हिस्से में बीस मीटर चौड़ी और दो सौ मीटर लंबी दरार पड़ने से कुणजेठी तल्ली गांव भी ख़तरे की जद में आ गया. आपदा के समय बेघर हुए लोग नाला, देवर, मस्ता एवं गुप्तकाशी की ओर पलायन कर चुके हैं. जबकि 68 परिवार आज भी गांव में मौजूद हैं. गांव के ऊपर पड़ी दरार की सुध न लिए जाने से लोगों में खासा रोष है. आलम यह है कि आसमान में बादल छाते ही या फिर हल्की बूंदाबांदी होते ही गांव के 68 परिवारों की नींद उड़ जाती है. सामाजिक कार्यकर्ता दिलबर सिंह रावत कहते हैं कि गांव के ऊपर पड़ी दरार के ट्रीटमेंट के संबंध में शासन–प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई. गांव के ऊपर पड़ी दरार वाला भू–भाग यदि एक साथ खिसकता है, तो कुणजेठी मल्ली के 85 परिवारों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी. ■

2002–03 के दौरान केएलएम के अधिकारियों को नीरा की चालाकी का पता चलने लगा. इसके बाद वे लोग मुझमें भरोसा दिखाने लगे और इस बात को समझ गए कि नीरा ने हम दोनों को धोखा दिया है. जॉन डेर्बीशायर, इयान स्मिथ और एक महिला, जो इस पूरे मामले की जांच के लिए उत्तरदायी थे, मुझसे मिले और इस बात पर सहमत हो गए कि मेरी फीस के 5,50,000 यूएस डॉलर मुझे अब तक नहीं मिले हैं. वे इस मसले को सुलझाना चाहते थे. क़ानूनी तरीके के तहत उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उनके ख़िलाफ़ अपने पैसों के लिए एक मुक़दमा दाखिल करूं.

क़ादर ख़ान को पद्म पुरस्कार क्यों नहीं

चौथी दुनिया ब्यूरो

बॉलीवुड के जाने–माने अभिनेता क़ादर ख़ान को पद्म पुरस्कार देने की मांग उठने लगी है. अब तक अभिनेता ओमपुरी, लेखिका–निर्देशक रूमी जाफरी, निर्माता निर्देशक डेविड धवन, अभिनेता शक्ति कपूर और ऋषि कपूर जैसे कई कलाकारों ने इस मांग का समर्थन किया है. क़ादर खान निर्माता–निर्देशक फौज़िया अर्शी की फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** से एक दशक बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं. फिल्म जगत और आम दर्शकों की तरफ से भी यह बात उठी कि इतने लंबे समय तक भारतीय रंगकर्म, हिंदी फिल्म जगत की सेवा करने वाले श्री कादर खान को अब तक पद्म पुरस्कार क्यों नहीं मिला और न ही किसी ने अब तक इसकी मांग क्यों नहीं की. उन्हें पद्म पुरस्कार देने की मांग होती देख निर्माता–निर्देशक फौज़िया अर्शी ने पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और क़ादर ख़ान को पद्म श्री देने की मांग की है. फौज़िया अर्शी ने बताया कि वह बॉलीवुड की जानी–मानी हस्तियों, खासकर अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, गोविंदा और अनिल कपूर सहित उनके साथ काम कर चुके कलाकारों से इस पहल का समर्थन करने का अनुरोध कर रही हैं. फौज़िया अर्शी ने बताया कि उनके ऊपर इस बात का दबाव था कि इतने दिनों तक फिल्मों से दूर रहने वाले क़ादर खान को पद्म पुरस्कार देने की मांग की जाये, ऐसा करने से क़ादर खान साहब को एक नया जीवन मिलेगा.

क़ादर खान को पद्म श्री से नवाज़े जाने की मांग करते हुए ओम पुरी ने कहा है कि वह यह पुरस्कार डिजर्व करते हैं. उन्होंने इतने साल बतौर एक एक्टर और राइटर फिल्म इंडस्ट्री की ख़िदमत की है, हमारी सरकार से गुजारिश है कि वह उन्हें पद्म श्री से नवाज़े. लेखिका–निर्देशक रूमी जाफरी ने कहा कि क़ादर खान पद्म श्री पाने के सबसे प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने हिंदी फिल्मों में के लिए बहुत योगदान दिया है. उनका यह भी मानना है कि आजकल पुरस्कार केवल उन लोगों को मिलते हैं जिनके पुरस्कार देने वालों के साथ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, क़ादर खान कभी पार्टियों में नहीं गये, न ही उन्होंने फिल्म जगत के बाहर के लोगों के साथ कभी मेलजोल रखा. इसी वजह से उन्हें अब तक यह पुरस्कार नहीं मिल सका. फिल्म निर्माता डेविड धवन और अभिनेता शक्ति कपूर भी क़ादर खान को पद्म श्री दिए जाने के समर्थन में आगे आए हैं. दोनों चाहते हैं कि उनके बतौर लेखक और अभिनेता हिंदी फिल्मों में किए गए काम को मान्यता मिले. वहीं ऋषि कपूर ने कहा कि उन्हें उनके बेजोड़ लेखन और अभिनय में योगदान के लिए निश्चित तौर पर पद्म श्री से पुरस्कृत किया जाना चाहिए.

उनकी वापसी को लेकर फिल्म जगत से लेकर दर्शकों तक सभी में ग़ज़ब का उत्साह है. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी उनकी फिल्मों में वापसी का स्वागत कर चुके हैं. अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने–जाने वाले क़ादर ख़ान ने बॉलीवुड में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक लोकप्रिय फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे. उन्हें विभिन्न श्रेणियों के चार फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया जा चुके हैं. उन्हें साल 2013 में भारत सरकार ने साहित्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया था, लेकिन भारत सरकार

क़ादर ख़ान को पद्म श्री दिए जाने की मांग करते हुए ओम पुरी ने कहा है कि वे इस पुरस्कार के हकदार हैं. उन्होंने इतने साल बतौर एक एक्टर और राइटर फिल्म इंडस्ट्री की ख़िदमत की है. हमारी सरकार से गुज़ारिश है कि क़ादर ख़ान साहब को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करे. लेखिका-निर्देशक रूमी जाफरी ने कहा कि क़ादर ख़ान पद्म श्री पाने के सबसे प्रबल दावेदार हैं. उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत योगदान दिया है.

ने उन्हें कभी पद्म सम्मान देने पर विचार नहीं किया. उम्र के 79 वें पड़ाव पर पहुंच चुके क़ादर खान को पद्म श्री से नवाज़े जाने के लिए उनके साथी कलाकारों को सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है. पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों के चयन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. सैफ अली ख़ान को साल 2010 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उसी साल अभिनेत्री रेखा को भी पद्म श्री से नवाजा गया. सैफ को इतनी जल्दी और रेखा को इतनी देर से पद्म पुरस्कार दिए जाने की आलोचना भी हुई थी. अब तो यह भी माना जाने लगा है कि राजनीतिक सहयोग या राजनीतिज्ञों की अनुशंसा के बिना किसी भी शख्स को पद्म पुरस्कार नहीं मिल सकता है. इसी प्रवृति का शिकार क़ादर ख़ान भी हुए हैं. भले ही कुछ लोगों को क़ादर ख़ान का अभिनय क्लासिकल न लगता हो लेकिन उन्होंने कई लोकप्रिय और सुपरहिट फिल्मों के संवाद लिखे हैं, इस आधार पर एक बेहतरीन लेखक के रूप में ही उन्हें पद्म श्री निश्चित रूप से मिलना चाहिए. पिछले साल सलमान खान के पिता और मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान को पद्म श्री से नवाजे जाने की घोषणा हुई लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया. लोगों ने भी इस निर्णय को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि यह देर से दिया गया अपर्याप्त सम्मान है.

अमिताभ बच्चन को अस्सी–नब्बे के दशक की जिन फिल्मों के लिए याद किया जाता है उनमें से अधिकांश फिल्मों की पटकथा और संवाद क़ादर ख़ान ने ही लिखे हैं. अमिताभ बच्चन के महानायक बनने के सफर में महत्वपूर्ण योगदान क़ादर ख़ान का भी रहा है. क़ादर ख़ान ने अपना जीवन फिल्मों के लिए समर्पित कर दिया और बॉलीवुड को एक नई दिशा दी. अस्सी और नब्बे के दशक में लोगों को ठहाके लगाने के लिए मजबूर करने वाले क़ादर ख़ान का फिल्म जगत में सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने आम लोगों की बोलचाल की भाषा को फिल्मों में जगह दिलवाई. अमर अकबर एंथनी में एंथनी के किरदार का वह टपोरी स्टाइल आज भी लोगों को याद है. क़ादर ख़ान की लिखी इस तरह की और भी कई फिल्में हैं जिनकी चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी है, और इसका सबसे बड़ा कारण उन फिल्मों की कहानी और डायलॉग हैं. जिससे लोग एक बार फिर अस्सी के दशक में लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

आज वक्त आ गया है कि ऐसे वरिष्ठ कलाकार को सम्मानित किया जाए. गोविंदा के साथ क़ादर ख़ान उनकी कॉमिक जोड़ी हमेशा याद की जायेगी. क़ादर ख़ान अपनी नई फिल्म ***होगया दिमाग़ का दही*** में ओम पुरी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और रज़्ज़ाक़ ख़ान जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आयेंगे. इससे पहले उन्होंने साल 2004 में आई फिल्म ***मुझसे शादी करोगी*** में अभिनय किया था. इसके बाद खराब सेहत की वजह से वह लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे. किसी भी कलाकार के लिए प्रशंसकों की तारीफ से बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं होता है, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी सम्मान मिलना, उनके काम को सराहने का सबसे बेहतर तरीका है. क़ादर ख़ान ने फिल्मों और थिएटर को जो कुछ दिया, वह उन्हें पुरस्कार दिए जाने के लिए पर्याप्त है या कहें कि आज तक जिस किसी को भी पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, उनकी उपलब्धियों से क़ादर ख़ान की उपलब्धियां किसी भी सूरत में कम नहीं हैं. शायद इसीलिए ओम पुरी कह रहे हैं कि क़ादर खान को पद्म श्री से सम्मानित करने में देर भले ही हो गई हो, लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

झूठ, फ़रेब और ब्लैकमेल

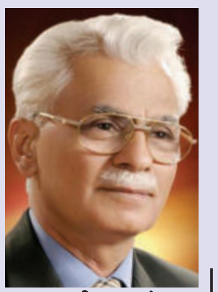

आर. के. आनंद

दो साल बाद इयान स्मिथ को स्वयं खुद के अनुभव से नीरा के सच का पता चला. वह मुझसे मिले और बताया कि नीरा ने उन्हें भी धोखा दिया है. उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि कैसे नीरा ने उन्हें यह समझाया था कि उसने मुझे पैसे दे दिए हैं. दिसंबर 2000 में इंग्लैंड में मेरे, नीरा और केएलएम के बीच एक बैठक तय हुई. नीरा ने बैठक में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके बाद भी कई बार डेर्बीशायर ने केएलएम अधिकारियों की उपस्थिति में मेरे और नीरा के बीच आमने–सामने की मुलाकात तय कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार नीरा इंकार करती रही. 2002 तक केएलएम को पता चल गया था कि उसे नीरा ने धोखा दिया है. नीरा की साख केएलएम की निगाह में ख़त्म हो चुकी थी. नीरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरा सामना कर सके.

नीरा जानती थी कि मैं अगर चाहूं, तो उसके ख़िलाफ़ अभी भी एक ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर सकता हूं यानी उसकी एक रिकॉर्डिंग. जब वह एक बार मेरे दफ्तर में आई थी, तब की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, जिसमें नीरा ने कहा था कि उसने खुद सारा पैसा रख लिया था और उसके लिए उसने माफी भी मांगी थी. दिसंबर 2000 तक नीरा केएलएम की विश्वासपात्र बनी रही, तब तक केएलएम ने नीरा को भारत में अपनी क़ानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है, इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत किया था. लेकिन, संदेह की बात यह थी कि 1999 में नीरा ने मुझसे कहा था कि केएलएम के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है. मेरे लिए यह जानना मुश्किल था कि नीरा से मुझे मिल रहे निर्देश क्या अंतिम थे? लेकिन कुछ भी हो, मेरे हर एक काम का बिल तो आ ही रहा था. असल में नीरा बहुत चालाकी से केएलएम को हैंडल कर रही थी. केएलएम के पैसों से एक सुपर रिच की तरह जीवन जीना उसकी ज़रूरत थी. यूके में एक असफल महिला उद्यमी बनने के बाद से नीरा को भारत में स्थापित होने में केएलएम ने मदद की थी. मैंने नीरा के व्यक्तिगत मामले में कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन नीरा ने केएलएम से भारी फीस वसूली.

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

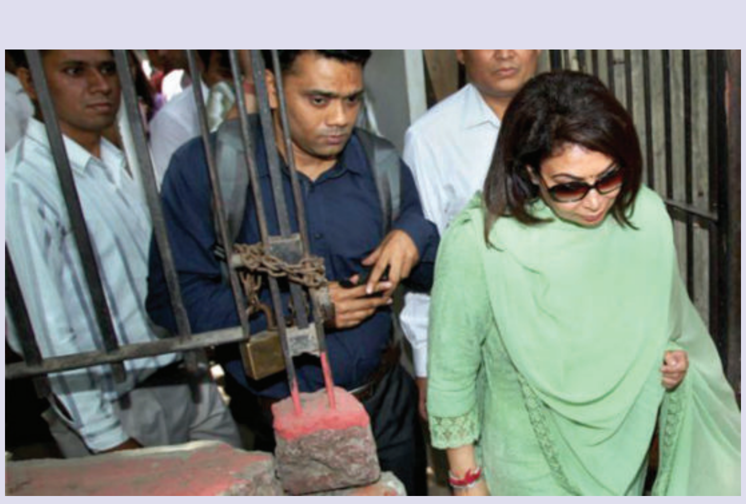

2002–03 के दौरान केएलएम के अधिकारियों को नीरा की चालाकी का पता चलने लगा. इसके बाद वे लोग मुझमें भरोसा दिखाने लगे और इस बात को समझ गए कि नीरा ने हम दोनों को धोखा दिया है. जॉन डेर्बीशायर, इयान स्मिथ और एक महिला, जो इस पूरे मामले की जांच के लिए उत्तरदायी थे, मुझसे मिले और इस बात पर सहमत हो गए कि मेरी फीस के 5,50,000 यूएस डॉलर मुझे अब तक नहीं मिले हैं. वे इस मसले को सुलझाना चाहते थे. क़ानूनी तरीके के तहत उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उनके ख़िलाफ़ अपने पैसों के लिए एक मुक़दमा दाखिल करूं. उसके आधार पर केएलएम नीरा के ख़िलाफ़ ब्रिटिश अदालत में कार्रवाई कर सकती थी. मैंने यह सलाह मानते हुए एक मुक़दमा दाखिल किया. मेरे मित्र विजय एसटी शंकर दास, जो लंदन में ही थे, मुझे सलाह देते रहे. 2002 में केएलएम मुश्किल हालात का सामना कर रही थी. उसे मेरे 5,50,000 यूएस डॉलर भी देने थे, जबकि इतना पैसा वह पहले ही नीरा को दे चुकी थी. इससे पहले उसे सतीश मोदी की ओर से परेशान होना पड़ा था. वह हर तरफ़ से हारी हुई नज़र आ रही थी.

2004 में लंदन में एक बैठक हुई, जिसमें शंकर दास भी मौजूद थे. केएलएम की ओर से मौजूद महिला प्रतिनिधि ने राज खोलने शुरू किए. उसने बताया कि केएलएम नीरा के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाने से इसलिए बच रही है, क्योंकि वह इस विवाद के अलावा भारतीय अधिकारियों और केएलएम के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों में शामिल रही है. उसके पास कई संवेदनशील दस्तावेज़ थे और वह केएलएम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी. उसी वक्त मुझे पता चला कि नीरा मेरी फीस का दस गुना पैसा तभी वसूल चुकी थी, जब अदालत के आदेश पर एयरक्राफ्ट यहां से रिलीज हुए थे. नीरा ने केएलएम से जमकर पैसा वसूला था, यह कहकर कि भारतीय अधिकारियों को बड़ी मात्रा में पैसा देना पड़ रहा है, ताकि एयरक्राफ्ट रिलीज कराए जा सकें. मैं चकित था. मैंने वहां उपस्थित लोगों को बताया कि अब तक डीजीसीए या क़ानून मंत्रालय में मेरी व्यक्तिगत साख रही है, उसी वजह से एयरक्राफ्ट रिलीज हो सके और इसके लिए किसी को भी बेवजह एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने उनसे सीधे पूछा कि जब उनके पास मेरा बैंक खाता विवरण था, तो सीधे मुझे पैसे देने के बजाय उन्होंने नीरा को पैसे क्यों दिए? जवाब था कि उनका भरोसा नीरा में था. खैर, दस वर्षों के बाद (सात वर्षों तक मुक़दमा चला) केएलएम (यूके) ने मेरी फीस मुझे दे दी. लेकिन, तब तक मुझे प्रति डॉलर 30 रुपये का नुक़सान हो चुका था. ■

जारी...

(मशहूर वकील आर. के. आनंद क्लोज एनकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली में अनगिनत झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जिनमें इंदिरा मार्केट एवं आरके पुरम सेक्टर-7 में रहने वाले लोगों को सरकार से काफ़ी शिकायतें हैं. यहीं के अनिल ने कहा कि वह हाईस्कूल करने के बाद कोई भी नौकरी करना चाहता है. एक बुज़ुर्ग महिला का कहना था कि आजकल के बच्चे पढ़-लिख कर भी क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती नहीं. क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी? केजरीवाल ने बहुत वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया.

उधार के अरबपति, कर्ज़दार करोड़पति

विशाल एस. एन.

भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर की सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ हाल में हुई एक बैठक में एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) के ख़तरनाक स्तर तक पहुंच जाने का मुद्दा फिर उठाया गया. इस समय इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. गत दो वर्षों में बैंकों की एनपीए में 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है. वर्तमान में लगभग 2,16,000 करोड़ रुपये की धनराशि सरकारी क्षेत्र के बैंक एनपीए के रूप में घोषित कर चुके हैं और यह धनराशि दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. एनपीए बैंकों की कर्ज देने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम है, लेकिन चिंता का विषय इसकी मात्रा का बेहिसाब बढ़ते जाना है. बैंकों की कर्ज देने की प्रवृत्ति और पिछले दस वर्षों के एनपीए को देखें, तो पता चलता है कि वर्ष 2008 के बाद एनपीए में तेज गति से बढ़ोत्तरी हुई. साथ ही इतिहास में पहली बार कई भारतीय औद्योगिक घराने अपना कर्ज नहीं चुका पाए.

रिजर्व बैंक के हाल के पत्र के अनुसार, सिर्फ़ 10 बड़ी कंपनियां ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 28,000 करोड़ रुपये की डिफॉल्टर हैं. स्वाभाविक तौर पर अगर कई औद्योगिक घरानों ने जनता के पैसों यानी बैंकों पर भरोसा करके जमा की गई धनराशि को कर्ज लेकर नहीं चुकाया है, तो उनकी जांच होनी चाहिए. लेकिन उन्होंने कर्ज क्यों नहीं चुकाया, यह समझने के लिए पहले देखना होगा कि वे करोड़पति कैसे बने? यह एक तथ्य है कि नब्बे के दशक में जब भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो भारतीय कंपनियों में रातोंरात बड़ा बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई. ये रातोंरात खड़े होने वाले औद्योगिक घराने बाज़ार की पूंजी या संस्थागत अथवा रणनीतिक निवेशकों के पैसों के बजाय बैंकों से उधार लिए गए पैसों से खड़े हो गए. चाहे जो भी निहितार्थ हों, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उधार की पूंजी के इस बीजारोपण की प्रक्रिया से शायद भारत में इतिहास के सबसे ज़्यादा करोड़पति हो गए.

हालांकि, इन उधार के करोड़पतियों के भी अपने ईमानदार कारण थे. शेयर बाज़ार से पूंजी उठाने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं बाधाएं पहले से हैं, अब भी हैं. आम निवेशकों को बचाने की मानसिकता के कारण नियामकों द्वारा बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है और सरकार में लालफीताशाही बहुत ज़्यादा है. इसलिए उद्योगपतियों ने अपने इन स्रोतों से पैसा लेने के बजाय पूंजी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपेक्षाकृत सरल तरीके यानी उधार की पूंजी का प्रयोग किया. लेकिन, वर्तमान एनपीए संकट के लिए सिर्फ़ संस्थाओं एवं सरकारी सिस्टम को सारा दोष देना सही नहीं होगा, बल्कि भारतीय उद्योगपतियों को भी इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. भारतीय उद्योगपतियों के बारे में एक अप्रिय बात यह है कि वे कभी भी अपने शेयर (इक्विटी) वितरित करना नहीं चाहते. स्वामित्व का विचार एक बीमारी की तरह जीवन भर उनसे जुड़ा रहता है. जब आप छोटे कारोबारी होते हैं, तो यह विचार अच्छा है, लेकिन जब आपका कारोबार विकसित हो जाता है, तो यह एक कमजोरी हो जाती है. भारतीय उद्योगपतियों की दूसरी समस्या यह है कि उन्हें सोना और अचल संपत्तियां जमा करने का शौक है.

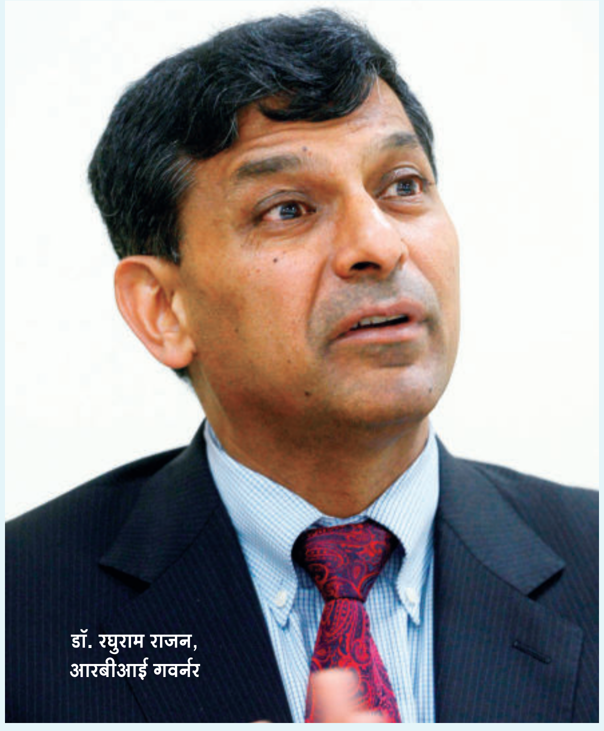

डॉ. रघुराम राजन, आरबीआई गवर्नर

सामूहिक संपत्तियों में निवेश करने के पीछे औद्योगिक घरानों का तर्क यह रहता है कि उनका इस्तेमाल भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने में किया जा सकता है. ज़मीन, सोना और शेयर की लालसा का त्रिकोण एक ऐसा दलदल बन गया है, जहां भारतीय उद्योगपति ब्याज के पैसों से अपना उद्योग चला रहे हैं. इसी वजह से हम ब्याज/ कर्ज न चुका पाने वाली कंपनियां, टूटे हुए व्यापार चक्र और कंपनियों की क़ीमती संपदा बैंकों द्वारा औने-पौने दामों पर बेचने के विज्ञापन आएदिन समाचार-पत्रों में देखते हैं. यह देखकर याद आता है कि जब उधार की रकम से हनीमून मनाया जाता है, तो एक दिन यही होता है. उधार की पूंजी के साथ-साथ एक समस्या और है, उधार के विचार, जिन पर ये रातोंरात खड़ी होने वाली भारतीय कंपनियां टिकी होती हैं. उधार के विचारों का मतलब यह कि भारतीय कंपनियां अपनी सामर्थ्य पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएनडी) नहीं करतीं, न कोई नया उत्पाद बाज़ार में लाने का प्रयास करती हैं, बल्कि दूसरों की सफलता देखकर उसी क्षेत्र में व्यापार करने लगती हैं.

समाधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भारत की महत्वाकांक्षा रखते हैं और पूरी युवा पीढ़ी जिसका सपना देख रही है, वह उधार की पूंजी और उधार के विचारों से हासिल नहीं किया जा सकता. बैंक और रिजर्व बैंक अकेले कोई रास्ता नहीं सुझा सकते. मेरे विचार में उनके द्वारा इस मामले को जिस तरह से देखा गया है, वह निष्पक्ष और अच्छा है, लेकिन हमें अन्य स्टॉक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है, जिनमें भारत सरकार और सबसे बड़े स्टॉक होल्डर शामिल हैं यानी लाखों उद्योगपति. सरकार को उद्योगपतियों को कर प्रोत्साहन देकर बाज़ार से पूंजी से उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. बैंक अधिकारियों को नौकरशाही के तौर-तरीकों में फंसने के बजाय कर्ज प्रस्ताव का मूल्यांकन और ज़्यादा व्यवसायिक तरीके से करना चाहिए. जब एक अत्यधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र के मूल्यांकन की बात आती है, तो बैंक जानकारी और विशेषज्ञता के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं. कैसे एक ऋण अधिकारी इस योग्य हो सकता है कि वह एक तरफ़ इस्पात संयंत्र के प्रस्ताव का मूल्यांकन करे और दूसरी तरफ़ गन्ना शोधन संयंत्र का!

रिज़र्व बैंक के हाल के पत्र के अनुसार, सिर्फ़ 10 बड़ी कंपनियां ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 28,000 करोड़ रुपये की डिफॉल्टर हैं. स्वाभाविक तौर पर अगर कई औद्योगिक घरानों ने जनता के पैसों यानी बैंकों पर भरोसा करके जमा की गई धनराशि को कर्ज़ लेकर नहीं चुकाया है, तो उनकी जांच होनी चाहिए.

भारतीय उद्योगपतियों को मौलिक विचारों, आरएनडी और नवीन उत्पाद की दिशा में निवेश करना चाहिए, अन्यथा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी धमाकेदार शुरुआतों से वे स्वयं को एक तरफ़ धकेल दिया पाएंगे. औद्योगिक घरानों को अपनी शुरुआती अवस्था में प्रवर्तकों को पोषित करना चाहिए. हर औद्योगिक घराने को अपने सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) कार्यक्रम के तहत पांच छात्रवृत्तियां देनी चाहिए. हमें जुगाड़ की प्रवृत्ति के लिए अपनी पीठ नहीं ठोकनी चाहिए. सरकार को इस तरह काम करना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र शोध एवं विकास बने, न कि जुगाड़. और, सबसे बड़ी बात यह कि उद्योगपतियों को अपनी तीनों प्रेयसियां छोड़नी होंगी, शेयर, सोना और अचल संपत्ति. सिर्फ़ व्यापार से संबंध रखना होगा. ■

(लेखक इन्वेस्टमेंट बैंकर एवं जेन एडवाइजर्स के सीईओ हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

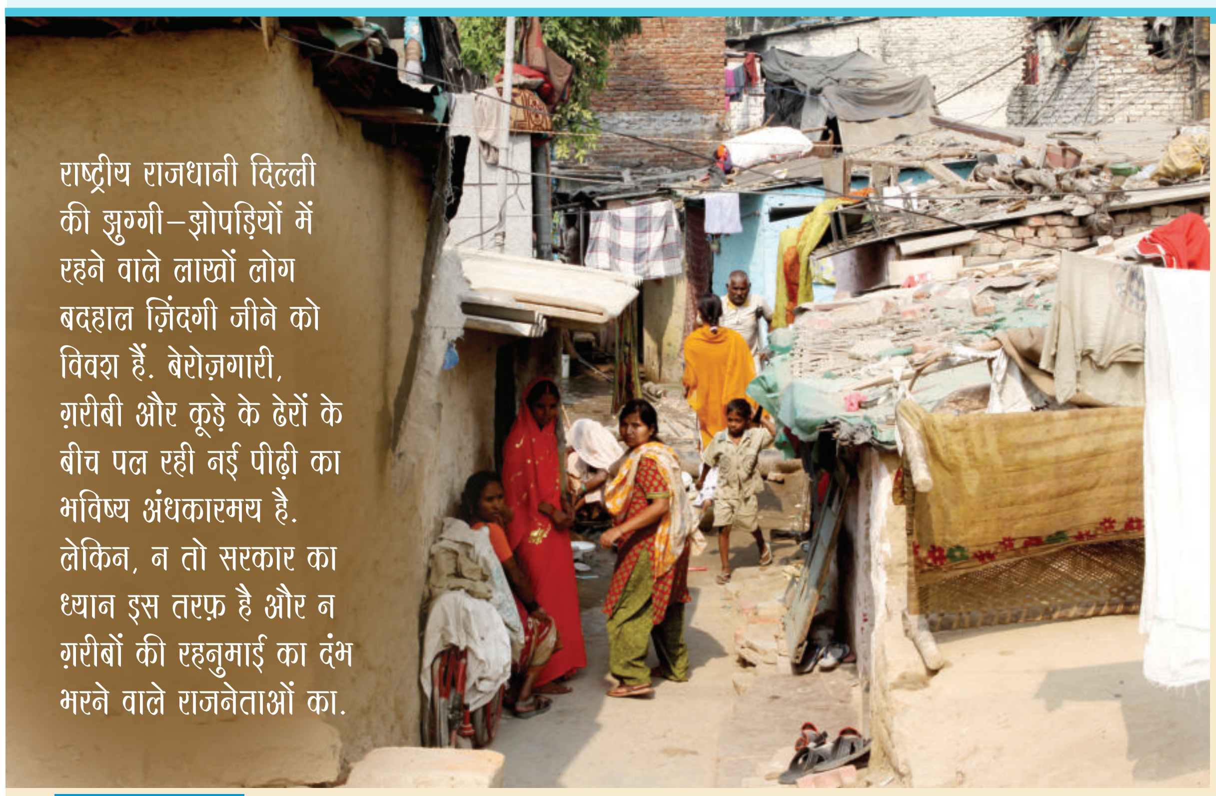

यह है दिल्ली के ग़रीबों का हाल

मसरूर सुग़रा

नरैना-मायापुरी की झुग्गी-झोपड़ियों में लोग गंदे नाले के ऊपर लकड़ी के पटरे डालकर जी रहे हैं. वहीं गुज़र-बसर के लिए किसी-किसी ने अपनी छोटी-सी दुकान भी खोल ली है. भीषण गंदगी के बीच एक डॉक्टर साहब भी अपने छोटे-से क्लीनिक के साथ विराजमान हैं. शायद वह भूल गए कि जहां गंदगी का ज़हर मौजूद हो, वहां दवा किसी भी तरह कारगर नहीं हो सकती. बरसात के दिनों में यहां जगह-जगह नाले भर जाते हैं और उनका गंदा-बदबूदार पानी झोपड़ियों में घुस जाता है. यहां रहने वाले अधिकतर लोग अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं. कई सामाजिक संगठन इनमें जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं. झुग्गियों में रहने वाली लड़कियों की ज़िंदगी एक दर्दनाक किस्से से कम नहीं है.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की डिप्टी सेक्रेटरी शहनाज़ ने बताया कि पहाड़ी इलाके की 22 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनमें से दो बरामद हुईं और दो की लाश मिली, बाक़ी कहां गईं, कुछ पता नहीं चला. वापस आई एक लड़की ने शादी कर ली. बकौल शहनाज़, कुछ लोगों ने उस लड़की को अग़वा करके किसी दूसरे शख्स के हाथों बेच दिया, जिसने उससे शादी कर ली. कुछ लोग झुग्गियों में रहने वाली लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बाहर ले जाते हैं और उनसे ग़लत काम कराते हैं. ऐसे लोग अधिकतर हरियाणा एवं राजस्थान से संबंध रखते हैं, जिनकी रोज़-रोटी का एकमात्र ज़रिया लड़कियों को बहला-फुसला कर ले जाना और उन्हें बेच देना है. इस काम में कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. इस पेशे से जुड़े युवक स्कूल-कॉलेज की छात्राओं से पहले दोस्ती करते हैं और फिर तीन-चार बार उन्हें शॉपिंग कराते हैं. जब वे पूरी तरह उन पर विश्वास करने लगती हैं, तो उनका किसी के हाथ सौदा कर लिया जाता है.

ऐसी लड़कियां अधिकतर जिस्मफरोशी के धंधे में जबरन धकेल दी जाती हैं. पुलिस या अन्य किसी के सहयोग से वापस घर आईं कुछ लड़कियां बताती हैं कि उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया गया, जिससे वे बेहोश हो गईं. उनके साथ क्या-क्या हुआ, यह होश पर ही उन्हें पता चला. बीते जून माह में सीतापुरी की गली नंबर एक में गाज़ियाबाद पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 50 लड़कियों को मुक्त कराया. उन लड़कियों को पश्चिम बंगाल निवासी एक महिला ने वहां कैद कर रखा था और वह उनसे देह व्यापार कराती थी. शहनाज़ बताती हैं कि सीतापुरी की गली नंबर दो की एक लड़की को उसके घर आने वाले एक लड़के ने मकान की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. दबंगों के डर से उस लड़की के माता-पिता ने कहा कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था. सीतापुरी की ही एक 16 वर्षीय लड़की के साथ उसके मकान मालिक एवं एक अन्य शख्स ने बलात्कार किया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया. जांच के दौरान मकान मालिक ने पुलिस से कहा कि इसके घर रोज़ न जाने कौन-कौन आता-जाता था. यही नहीं, मकान मालिक ने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गायब कर दी. हादसे के बाद से लड़की की मां लापता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान मालिक ने उसे कुछ पैसे देकर कहीं दूसरी जगह भेज दिया. बकौल शहनाज़, ऐसे मामलों में जब हम थाने रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो पुलिस कहती है कि ये तो गंदी नाली के कीड़े-मकोड़े हैं, उसी में सड़कर मर जाएंगे. मैडम, आप क्यों परेशान होती हैं? जब ऐसी कई लड़कियों को हमने आज़ाद कराया, तो फोन पर धमकी दी गई कि दोबारा इधर मत नज़र आना, हमें रोज़ी-रोटी कमाने दो, तुम्हारा क्या जाता है? शहनाज़ कहती हैं कि इस सारे गोरखधंधे के पीछे राजनीतिक संरक्षण काम करता है और पुलिस को भी अच्छी-खासी कमाई हो जाती है. इसलिए जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती.

दिल्ली की झुग्गी आबादी पर एक नज़र

हिंदू	8,00,000
मुस्लिम	1,50,000 (लगभग)
ईसाई	3,000 (लगभग)
सिक्ख	4,000
जैन	100
बौद्ध	200
पारसी	190

- 22 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं.
- सिर्फ़ 16 प्रतिशत घरों में शौचालय.
- सात प्रतिशत लोग सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं.
- पहाड़ी इलाके की 22 लड़कियां लापता, जिनमें से दो बरामद, दो की लाश मिली.
- जून, 2015 में सीतापुरी इलाके में पुलिस छापे के दौरान 50 लड़कियां बरामद.

दिल्ली में अनगिनत झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जिनमें इंदिरा मार्केट एवं आरके पुरम सेक्टर-7 में रहने वाले लोगों को सरकार से काफ़ी शिकायतें हैं. यहीं के अनिल ने कहा कि वह हाईस्कूल करने के बाद कोई भी नौकरी करना चाहता है. एक बुज़ुर्ग महिला का कहना था कि आजकल के बच्चे पढ़-लिख कर भी क्या करेंगे, नौकरी तो मिलती नहीं. क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी? केजरीवाल ने बहुत वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया. वहीं प्रमिला श्रीवास कहती हैं कि केजरीवाल सरकार ने बहुत कुछ किया. सबसे बड़ी बात यह कि अब हर समय पुलिस तंग नहीं करती, पहले हर क़दम पर पुलिस का डर सताता था. हालांकि, झुग्गी में रहने वाले अधिकतर लोग प्रमिला के प्रति अच्छी राय नहीं रखते. उनका कहना है कि प्रमिला श्रीवास ने कई लोगों की झुग्गियों पर क़ब्ज़ा करके उन्हें बेसहारा कर दिया. फातिमा ने बताया कि उनका एक पैर खराब है, सरकारी सहायता के लिए उन्होंने इलाकाई विधायक के कार्यालय में आवेदन भी जमा कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मुनिरका स्थित झुग्गी में रहने वाली गजना ने बताया कि उन्होंने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें आज तक एक किस्त भी नहीं मिली. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

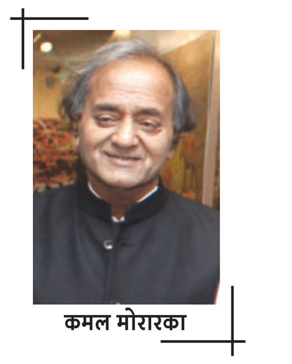

कमल मोरारका

मतदाता वादाख़िलाफ़ी को माफ़ नहीं करता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश देने की घटनाएं बढ़ रही हैं. पुराने समय में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब मुझे याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा किया हो. यदि सरकार कमज़ोर है, अपनी सामान्य गतिविधियां भी ठीक से नहीं निभा रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते. ऐसे में न्यायपालिका निर्देश देगी ही. ताजा उदाहरण है, टोल टैक्स संग्रह का. कोर्ट ने उन सड़कों पर टोल टैक्स रोकने के निर्देश दिए हैं, जहां रखरखाव ठीक नहीं है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन दोनों कैम्पों की ओर से गतिविधियां तीव्र गति से बढ़ गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार के लिए अधिकतम वादों, पैकेज और रियायतों की घोषणा कर देना चाहते हैं. अपने अति उत्साह में उन्होंने जो पैकेज वगैरह दिए हैं, वे पहले से ही आवंटित बजट या वित्त आयोग के आवंटन के हिस्से हैं. खैर, चुनाव के समय इस तरह की हेरफेर चलती है. हालांकि, एक प्रधानमंत्री के लिए, जिसके पास स्पष्ट बहुमत है, यह अच्छी बात नहीं है. लोग यह देखेंगे कि प्रधानमंत्री क्या वादे कर रहे हैं और वे कितने व्यवहारिक हैं. अगर ऐसे ही चलता रहा और अव्यवहारिक वादे होते रहे, तो फिर जनता उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देगी. फिर यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी. तब यह भूल जाइए कि कौन जीतता है या कौन हारता है.

दूसरी ओर, नीतीश और लालू एक साथ आ गए हैं और भाजपा की ओर से यह कहने की कोशिश हो रही है कि ये दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए थे और अब चुनावी लाभ उठाने के लिए बेमेल गठबंधन कर रहे हैं. इस सबका कोई मतलब नहीं है. चुनाव के समय ऐसे राजनीतिक मेल-मिलाप होते रहते हैं. जो लोग पहले साथ नहीं होते हैं, वे बाद में साथ आ जाते हैं. ये सब सामान्य चुनावी परिदृश्य हैं. लब्बोलुआब यह है कि एक तरफ़ केंद्र में हमारे पास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार है और दूसरी तरफ़ ग़ैर-कांग्रेसी, ग़ैर-भाजपाई पक्ष है, जो पिछड़े वर्ग से है. चुनाव इन दो गुटों के बीच है. भाजपा के पास बहुत सारा पैसा है, उसके साथ प्रधानमंत्री की अथॉरिटी है और संसाधन हैं. यह एक सकारात्मक पक्ष है. नकारात्मक पक्ष नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले 15 महीने का कम तीव्रता वाला प्रदर्शन है, जो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है. लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की तुलना अभी के प्रदर्शन से करें, तो यह काफी निराशाजनक है.

बेशक कई वादे ऐसे हैं, जो कार्यान्वित होने योग्य नहीं थे, लेकिन मतदाता चुनाव के समय क्षमा नहीं करते हैं. लोग पूछेंगे कि काला धन वापसी का क्या हुआ, अन्य वादों का क्या हुआ? इन सबका क्या नतीजा हो सकता है, इसे दिल्ली के चुनाव से समझ सकते हैं. दिल्ली में जो हुआ, वह कोई छोटी बात नहीं है. 70 में से 67 सीटें भाजपा हार गई. यह उस पार्टी के लिए काफी दु:खभरी बात है, जो बड़े-बड़े वादों के साथ कुछ ही महीने पहले केंद्र की सत्ता में आई थी और ठीक अपनी नाक के नीचे होने वाला चुनाव हार गई.

बिहार में भाजपा के लिए दूसरी समस्या यह है कि उसके पास कोई चेहरा नहीं है. आप हर राज्य में नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं. आपको एक स्थानीय एवं विश्वसनीय चेहरा चाहिए. एक ऐसा नेता चाहिए, जो कह सके कि हां, अगर भाजपा को जनादेश मिला, तो मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं या मैं नेतृत्व करूंगा. ऐसा कोई चेहरा भाजपा के पास नहीं है. उसके वर्तमान नेता सुशील मोदी हैं, लेकिन वह एक जननेता नहीं हैं. वह नीतीश कुमार के एक बेहतर सहयोगी थे. जब तक भाजपा और जद (यू) साथ थे, कभी किसी ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं की. वह एक ऐसे नेता नहीं दिखते, जो नतीजे दे सके. अन्य नेताओं को पीछे की सीटों पर क्यों बैठाकर रखा गया है, यह भाजपा ही बेहतर जानती है. वह उनमें से किसी को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहती. यह दूसरी बड़ी बाधा है.

नीतीश कुमार के पक्ष से यह कहा जा रहा है कि उनके दस वर्षों के शासन में लोग कोई कमी नहीं निकाल सकते. दरअसल, जब भाजपा नीतीश सरकार के दस वर्षों के शासन, जिसमें आठ साल वह खुद भागीदार रही है, में ग़लतियां निकाल रही है, तो वास्तव में इस सबका कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. तथ्य यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक अच्छा शासन दिया है. नकारात्मक पक्ष यह है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया है, जो

कल तक उनके ख़िलाफ़ थी. लेकिन, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के समय यह सब होता है. असल परीक्षा यही है कि क्या इन दलों के वोट बैंक उनके साथ जुड़े रहते हैं? यदि ऊंची जाति-भूपति वर्ग भाजपा के साथ और पिछड़ा वर्ग नीतीश-लालू के साथ बना रहता है, तो नीतीश-लालू का पलड़ा भारी रहेगा. अब सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, संसाधनों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, इस सबका अंतिम परिणाम से कोई मतलब नहीं होगा? आइए, हम सब इंतजार करें. एक बार आचार संहिता लागू हो जाए, तब आप बिहार के लिए मुफ्त के वादों की झड़ी नहीं लगा सकेंगे.

दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश देने की घटनाएं बढ़ रही हैं. पुराने समय में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब मुझे याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा किया हो. यदि सरकार कमज़ोर है, अपनी सामान्य गतिविधियां भी ठीक से नहीं निभा रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते. ऐसे में न्यायपालिका निर्देश देगी ही. ताजा उदाहरण है, टोल टैक्स संग्रह का. कोर्ट ने उन सड़कों पर टोल टैक्स रोकने के निर्देश दिए हैं, जहां रखरखाव ठीक नहीं है. आख़िरकार टोल टैक्स संग्रह सड़कों को बेहतर बनाए रखने के लिए ही तो किया जाता है. राजमार्ग के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर एक रुपये उपकर और टोल टैक्स की वसूली से एक बड़ी रकम हासिल होती है. यह लोगों का पैसा है. इसलिए लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन की नहीं, बल्कि जनता के मन की बात कही है.

कई अन्य चीजें लंबित हैं, जैसे एनजेएसी बिल, जो न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए पहले की दो प्रणालियों से बेहतर है. पहले की प्रणाली में या तो सरकार नियुक्ति करती थी या अब न्यायपालिका खुद करती है. न्यायाधीश बनाए जाने वाले शख्स की वांछनीयता की समुचित जांच के बाद ही उसे नियुक्त किया जाना चाहिए. यदि आप एक बार किसी को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त कर देते हैं, तब उसे हटाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है. हटाने के लिए भी सरल प्रक्रिया होनी चाहिए. अभी संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग पास करना लगभग असंभव है. इसे सरल बनाने के लिए भारत के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों एवं भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को साथ बैठकर रास्ता निकालना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए. यदि कोई शख्स अक्षम है, उसने कुछ ग़लत किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे हटाना ही चाहिए. आख़िरकार, एक राष्ट्र के तौर पर हमारा दायित्व है कि हम अपनी शीर्ष अदालतों को साफ़-सुथरा रखें. जितनी जल्दी सरकार इस ओर ध्यान दे, उतना ही बेहतर होगा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने अपना समय राज्यों के चुनाव के लिए समर्पित कर दिया है. भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चाहिए कि वे प्रधानमंत्री को उनके कर्तव्य पूरे करने और इस देश को चलाने के लिए छोड़ दें. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अगर यह संपादकीय ग़लत है, तो हमें सच्चाई बताइए

“सरकार के पास योगा-डे के लिए 500 करोड़ रुपये हैं, जो उन्होंने खर्च किए. सरकार के पास हरियाणा के स्कूल में योग सिखाने के लिए सालाना 700 करोड़ रुपये हैं, लेकिन सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के बजट में 20 प्रतिशत कटौती की, क्योंकि स्कूलों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. सरकार के पास कॉरपोरेट घरानों को 64 हज़ार करोड़ रुपये की टैक्स छूट देने के लिए पैसे हैं, लेकिन आत्महत्या कर रहे किसानों का कर्ज चुकाने के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपये नहीं हैं.”

आज का संपादकीय संभवत: पूर्ण रूप से झूठ पर आधारित है. मैं चाहूंगा कि आप इस लेख में लिखी हुई सारी बातों को जांचें और मुझे लिखें कि मैंने यह झूठ क्यों लिखा है. यह झूठ प्रधानमंत्री के सामने भी जाना चाहिए और एक वंचित व्यक्ति के सामने भी, जो सिर्फ़ दो वक्त का भोजन पाने के लिए दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करता है.

26 मई, 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, उस समय इंदौर से भोपाल का रेल किराया पैसेंजर सवारी का 40 रुपये था, जो आज 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बाद 50 रुपये है. उस दिन प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये का था, जो आज दस रुपये में मिलता है और व्यवस्था जस की तस है. सबसे पहले रेल किराया बढ़ाया गया था, तो यह कहा गया था कि अगर किराया नहीं बढ़ेगा, तो वर्ल्ड क्लास रेल नहीं आ पाएगी. अब दो से तीन बार किराया बढ़ चुका है, लेकिन वर्ल्ड क्लास रेल तो छोड़ दीजिए, रेल में किसी भी सुविधा की बढ़ोत्तरी नहीं हुई और हम वैसी ही नारकीय स्थिति में सफर करते हैं. किराया बढ़ाते समय जो वादे किए गए थे, उन वादों का आख़िर क्या हुआ?

2-जी का उदाहरण. आइडिया का नेट बाउचर 98 रुपये में अनलिमिटेड आता था. आज अनलिमिटेड 2-जी 250 रुपये में आता है. उस दिन एक डॉलर 58 रुपये के बराबर था और आज 66 रुपये के बराबर है. तब कॉल रेट 30 पैसे मिनट थी, आज एक रुपये मिनट है. तब कच्चा तेल 105.71 डॉलर प्रति बैरल था, पेट्रोल 71.41 रुपये लीटर था और पेट्रोल पर वेट 21 प्रतिशत था, आज कच्चा तेल 40 डॉलर प्रति बैरल है, पेट्रोल 68.50 रुपये लीटर है और पेट्रोल पर वैट 31 प्रतिशत हो गया है.

तुअर (अरहर) की दाल उस समय 70 रुपये प्रति किलो थी, आज 130 रुपये प्रति किलो है और प्याज 15 रुपये प्रति किलो था, आज 80 रुपये प्रति किलो है.

सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत था, आज 14 प्रतिशत है. एक्साइज ड्यूटी 10 प्रतिशत थी, आज 12.36 प्रतिशत है. सभी दोस्त, खासकर उद्योगपति दोस्त, अपनी बैलेंस शीट चेक करें, चार्टर्ड एकाउंटेंट अपने ग्राहकों और ग्राहक स्वयं की बैलेंस शीट चेक करें, तो सारा माजरा समझ में आ जाता है.

आज मोदी सरकार को 462 दिनों से ज़्यादा हो गए और इस सरकार ने हमसे 100 करोड़ रुपये की गैस सब्सिडी ख़त्म कराने के लिए 250 करोड़ रुपये के विज्ञापन दे दिए हैं. स्वच्छता अभियान का विज्ञापन बजट भी 250 करोड़ रुपये था, लेकिन दिल्ली में सफ़ाई कर्मियों की सालाना तनख्वाह के लिए ज़रूरी 35 करोड़ रुपये का इंतजाम केंद्र सरकार ने नहीं किया.

किसान टीवी पर सालाना 100 करोड़ रुपये का खर्च सरकार दे सकती है, क्योंकि इस चैनल के सलाहकार समेत आधे कर्मचारी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री का प्रिय संगठन है. लेकिन, उन किसानों की खाद्य सब्सिडी इस सरकार ने छीन ली, जिनके टीवी चैनल पर 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.

सरकार के पास योगा-डे के लिए 500 करोड़ रुपये हैं, जो उन्होंने खर्च किए. सरकार के पास हरियाणा के स्कूल में योग

आज मोदी सरकार को 462 दिनों से ज़्यादा हो गए और इस सरकार ने हमसे 100 करोड़ रुपये की गैस सब्सिडी ख़त्म कराने के लिए 250 करोड़ रुपये के विज्ञापन दे दिए हैं. स्वच्छता अभियान का विज्ञापन बजट भी 250 करोड़ रुपये था, लेकिन दिल्ली में सफ़ाई कर्मियों की सालाना तनख्वाह के लिए ज़रूरी 35 करोड़ रुपये का इंतजाम केंद्र सरकार ने नहीं किया.

सिखाने के लिए सालाना 700 करोड़ रुपये हैं, लेकिन सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के बजट में 20 प्रतिशत कटौती की, क्योंकि स्कूलों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं.

सरकार के पास कॉरपोरेट घरानों को 64 हज़ार करोड़ रुपये की टैक्स छूट देने के लिए पैसे हैं, लेकिन आत्महत्या कर रहे किसानों का कर्ज चुकाने के लिए 15 हज़ार करोड़ रुपये नहीं हैं.

स्किल इंडिया के लिए 200 करोड़ रुपये का विज्ञापन बजट है, लेकिन युवाओं की छात्रवृत्ति में 500 करोड़ रुपये की कटौती बिना किसी हिचक के सरकार कर डालती है. यह वह सरकार है, जो विदेशियों को 17.26 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचकर उसे 45 रुपये प्रति किलो की दर से वापस खरीदेगी, जो ट्रांसपोर्ट आदि का खर्च जोड़कर 50 रुपये प्रति किलो में वापस मिलेगा.

और सबसे मजे की बात, इस सरकार ने विपक्ष और किसानों के दबाव में आकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर घुटने अवश्य टेके, लेकिन चौतरफ़ा विरोध से घिरी सरकार जान-बूझकर भूमि अधिग्रहण क़ानून लाने की जिद पर बनी रही और सारे देश में अपनी किरकिरी करा ली. आख़िर में किसानों की जीत हुई. कहा गया कि अब सरकार इस विषय पर अध्यादेश नहीं लाएगी.

सरकार घाटे में है. ओएनजीसी को बेचने की तैयारी चल रही है. रेलवे की ज़मीनें बेचने के लिए टेंडर जारी किया जाए, यह फ़ैसला लिया गया है, लेकिन गुजरात के उद्योगपति के लिए 22 हज़ार करोड़ रुपये सरकार ने बहुत आसानी से दे दिए हैं. हमने मनमोहन सिंह सरकार को मौन सरकार की संज्ञा दी, लेकिन उनके कार्यकाल में विकास की दर नौ प्रतिशत थी और अब काम करने वाली सरकार, नया भारत बनाने वाली सरकार में विकास की दर सात प्रतिशत रह गई है.

मैं मानता हूं कि ये जानकारियां ग़लत हैं, क्योंकि इन्हें उन साधारण लोगों ने मुझे भेजा है, जो देश का अर्थशास्त्र नहीं जानते, मंत्रियों के तर्क नहीं जानते, अधिकारियों की सपने दिखाने की कला नहीं जानते, लेकिन अंत में तो पेट में जाने वाली रोटी और टूटते सपनों की सच्चाई का जिन्हें सामना करना होता है, वे ऐसी जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाते हैं. और, हम इन जानकारियों को झूठा कहते हैं या पर्चा फाड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे लिए लोगों के दु:ख-दर्द से ज़्यादा इंद्राणी मुखर्जी की कहानी मायने रखती है. जब इंद्राणी मुखर्जी की लड़की, जिसकी अब हत्या हो चुकी है या हत्या हुई है, यह साबित किया गया है, तब किसी चैनल या अख़बार ने पीटर मुखर्जी जैसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के ख़िलाफ़, भाईचारा दिखाते हुए, रिपोर्ट नहीं किया. अब रोज़ाना नई कहानियां सामने आ रही हैं और इन कहानियों में सच्चाई का पुट कम, कल्पना का पुट बहुत ज़्यादा है.

हम अपने पाठकों से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस संपादकीय में लिखे हर शब्द को ग़लत साबित करें, क्योंकि हो सकता है कि यह ग़लत हो. हमने इसे स्वयं परखा नहीं है, क्योंकि हमें लगा कि परखने का काम यदि हम साथ-साथ करें, तो कैसा रहे. इसलिए हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

जब एक स्त्री डाकू बदला लेने पहुंचती है-4

नरसंहार पर ओछी राजनीति करने की होड़

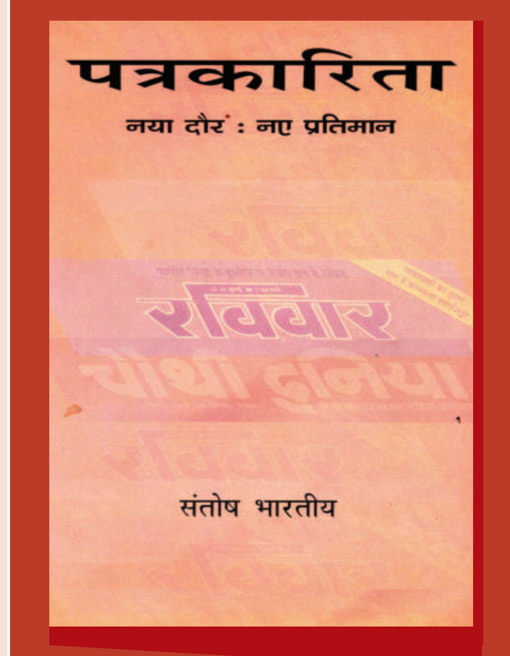

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

बेहमई में हुए नरसंहार के बाद स्थानीय नेताओं द्वारा उसका राजनीतिक लाभ उठाने के जो प्रयास किए गए, उन्हें भी घिनौना कहा जाएगा. ज़रूर बेहमई में जो हुआ, उसके पीछे जातीय भेदभाव की सोच और एक जाति से बदला लेने की उत्तेजना कार्यरत थी, लेकिन उसे कांग्रेस (इं) व भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा एक घृणित तथ्य के रूप में चिन्हित किए जाने के बजाय अपनी ज़मीन को पुख्ता करने के लिए जातीय आधार पर लोगों की भावनाएं उभारने के लिए ही इस्तेमाल किया गया. संभवत: इसके पीछे एक तीर से दो शिकार करने की योजना थी. एक तो यह कि इससे क्षेत्र के ठाकुर इकट्ठे होने की ज़रूरत महसूस करेंगे और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, जो स्वयं ठाकुर हैं, में भी जातीय भावना को उभारा जा सकेगा. इसका यह असर तो अवश्य हुआ कि क्षेत्र के ठाकुर आपस में मोर्चेबंदी की बात करते नज़र आ रहे हैं. क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी खुर्शीद आलम, जिन पर घटनास्थल पर पड़े 305 बोर के कारतूसों को बदल कर 13 बोर के कारतूस फेंके जाने का आरोप है व थाना सिकंदरा के प्रभारी राम नाथ सिंह यादव को हटाकर उनके स्थान पर क्रमश: अभिमन्यु त्रिपाठी व श्यामवीर सिंह राठौर की नियुक्ति कर दी गई है. संभव है, दोनों नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों का सवर्ण होना महज संयोग हो, लेकिन क्षेत्र के कुर्मियों द्वारा इसे सुनियोजित कार्रवाई की ही संज्ञा दी जा रही है.

क्षेत्रीय विधायक राम स्वरूप वर्मा घटना की सूचना पाकर पांच दिन बाद राजपुर गए और बेहमई गए बिना ही लखनऊ वापस लौट गए. कहते हैं, वहां उन्हें किसी ने यह समझा दिया कि बेहमई में उनके खास स्वागत की तैयारियां हुई हैं और उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे वह भयभीत हो गए. यह भी चर्चा है कि उनके चतुर अनुभवी राजनीतिक मस्तिष्क ने घटना से जन्मी जातीयता के उन्माद को समझ लिया और उन्होंने सोचा कि वहां जाकर मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से क्षेत्र के कुर्मियों में उनके विरुद्ध आक्रोश फैल सकता है.

अब जरा पुलिस व्यवस्था का चेहरा देखिए. उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन के समय 1980 में जालौन, इटावा, मैनपुरी, एटा व फर्रुखाबाद में चुन-चुनकर ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए, जिन्हें विभाग में सबसे घटिया समझा जाता था. जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें समझाया गया कि चूंकि इन्हें अभी ही नियुक्त किया गया है, अत: इन्हें न हटाया जाए. यह सिफारिश इंका के ऐसे नेताओं ने की, जो डाकुओं को संरक्षण देने के लिए बदनाम हैं. जितने भी अच्छे आईपीएस अफसर हैं, सबको इंटेलिजेंस तथा सीआईडी में भेज दिया गया. इन ज़िलों में नियुक्त सभी अधिकारी पैंतालिस वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं. लगता है, उन्हें प्रदेश के संवेदनशील ज़िलों में अवकाश पूर्व पेंशन-सी दे दी गई है. इन अफसरों के विरुद्ध बहुत-से शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

पुलिस की भी अपनी दिक्कतें हैं. एसएसपी या एसपी को प्रतिदिन खाता-बही लिखने का काम करना होता है, जिसके कारण वह हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता है. सन् 1978 से 303 बोर की गोलियां पुलिस को अभ्यास के लिए नहीं दी गई हैं, जबकि डकैत रोज उनका अभ्यास करते हैं. परिणामत: डकैतों का निशाना सही होता है, पुलिस का ग़लत. पुलिस आयोग की 1960 की रिपोर्ट पर अमल अभी तक नहीं किया गया. नतीजा यह है कि आज भी पुलिस को यदि एक मुर्दा लाना हो, तो 60 मील का किराया 35 रुपये दिए जाते हैं. गवाही के लिए किसी को लाना हो, तो एक रुपये 25 पैसे किराए के लिए दिए जाते हैं. चौकीदार को अभी भी पांच रुपया महीना वेतन मिलता है. कठिनाइयां और भी हैं. एक उच्च पुलिस अधिकारी के शब्दों में, यहां पीएसी के लोग पूरी तरह पुलिस पर ही निर्भर हैं. एक तरह से पुलिस ही उनकी आंखें हैं. उन्हीं के निर्देशन में उन्हें कार्रवाई करनी होती है. बीहड़ों में पड़ी पीएसी की टुकड़ियों का काम दिन में पेट्रोलिंग करना तथा रात में डाकुओं के आने-जाने के संभावित रास्तों पर घात लगाना होता है. पीएसी की टुकड़ियों में आपस में संवाद बनाए रखने का कोई साधन नहीं है. उन पर यदि डाकू गिरोह हमला कर दे, तो उसकी ख़बर वहां से हम तक पैदल चलकर पहुंचेगी. पीएसी की जिस टुकड़ी पर सूचना पाकर भी न पहुंचने का आरोप लगाया गया है, उसके बारे में उनका कहना था कि उस वक्त कैंप में सिर्फ़ चार पोस्ट गार्ड ही थे, जिन पर पोस्ट की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी. बाकी जवान पेट्रोलिंग पर गए हुए थे. फिर सूचना पाकर पेट्रोलिंग करती टुकड़ी को बेहमई से बाहर निकलने के डाकुओं के संभावित रास्ते पर घात लगाने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन शायद किसी ने डाकुओं को इसकी सूचना दे दी और उन्होंने लौटने का रास्ता बदल लिया. कमांडर महोदय के अनुसार, सैन्य दृष्टिकोण से यही उचित भी था, क्योंकि बेहमई में जो होना था, हो चुका था. हां, उस वक्त बेहमई जाकर लोगों को संतुष्ट करने का काम अवश्य किया जा सकता था.

लेकिन जिसे पीएसी के जवानों ने दूसरे नंबर का काम समझा, उसे राजनेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले नंबर का माना. जिस तरह दनादन घटना के बाद से बेहमई में अधिकारियों का तांता लग गया, उसने गांव के हताहत परिवारों को निश्चय ही एक संतुष्टि दी. प्रति व्यक्ति पांच हज़ार रुपये व एक कंबल भी बांटा गया. यह सामान बांटने गए पुखरायां के तहसीलदार साहब ने गांव पहुंचते ही जिस तरह लोट लगाई, उससे उनकी दयानतदारी का आभास मिलता था. चारपाई पर अधलेटे, उन्होंने गांव के मुखिया के ज़रिये मृतकों की बेवाओं को वहीं एक-एक करके आने का निर्देश दिया. शायद यही होता भी, किंतु तभी कोई अक्खड़ स्वर में बोला कि सबके घर जाकर रुपये दीजिए. इससे तहसीलदार की भौंहें ऐंठीं, लेकिन मौक़े की गंभीरता को समझ कर वह अपना कोट संभालते हुए उठ गए. चलते-चलते उन्होंने अपनी जीप के ड्राइवर को बुलाकर आस-पास के किसी खेत से चने का हरा साग तोड़ लाने का आदेश दे दिया.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

पूंजीपतियों का साथ लेना क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है

मेघनाद देसाई

बीता महीना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी हलचल का था. पिछले 25 वर्षों के दौरान दुनिया चीन के दोहरे अंक के आर्थिक विकास को आश्चर्य से देखती रही. भारतीयों के लिए भी यह ईर्ष्या का विषय बना हुआ था. लोग यह सवाल पूछा करते थे कि अगर भारत में तानाशाही होती, तो क्या भारत भी अच्छा कर सकता था? पिछले महीने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया. दरअसल, यह एक ऐसा गुब्बारा था, जिसके फटने का इंतज़ार काफी समय से किया जा रहा था. बहरहाल, चीनी अधिकारियों ने बाज़ार संभालने के लिए 200-300 अरब डॉलर बाज़ार में जारी किए और शेयरों की बिकवाली पर रोक लगाई. इससे साबित होता है कि उन्हें आधुनिक बाज़ार की कोई समझ नहीं है. इन उपायों के बावजूद बाज़ार संभल नहीं सका और एक बार फिर लुढ़क गया. कम्युनिस्ट पार्टियां एक खास उद्देश्य और काम की तकनीकी निश्चितता द्वारा संचालित होती हैं. उन्हें विकल्प दे दीजिए और उनका काम थोड़ा जटिल बना दीजिए, तो वे उलझ कर रह जाएंगी. सोवियत संघ के विघटन का यही कारण था.

फिलहाल यह साफ़ हो गया है कि चीन केवल निर्यात के आधार पर ही लगातार विकास नहीं कर सकता. चीन के 20 वर्षों का विकास सस्ते मज़दूरों (ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, जिनके पास न तो स्वास्थ्य बीमा था और न नौकरी की सुरक्षा) पर निर्भर था. अब मज़दूरी बढ़ रही है और विकसित देशों का बाज़ार सिकुड़ रहा है. चीन को अपनी अर्थव्यवस्था अपनी घरेलू मांग पर आधारित करनी होगी और अपने मध्यम आय वर्ग को दूसरे देशों के मध्यम आय वर्ग के बराबर करना होगा. इसका अर्थ यह है कि उसे विकल्प देना होगा, ऋण देना होगा और उद्यमशीलता का विकास करना होगा, जिससे नई मांग की पूर्ति हो सके. इसका यह भी अर्थ है कि नियंत्रण समाप्त किया जाए और नागरिकों को आज़ादी दी जाए. कम्युनिस्ट पार्टियां यह करने में असमर्थ हैं, ऐसा कहना दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रेरित लग सकता है, लेकिन चीन इसी सच्चाई को साबित करता है.

अब चीन भी किसी अन्य अर्थव्यवस्था की तरह हो जाएगा. जब तक बदलाव का दौर समाप्त नहीं हो जाता, उसे सीखने की कोशिश और अगले 20 वर्षों तक चार से पांच प्रतिशत की विकास दर स्वीकार करनी होगी. चीन का अंत सोवियत संघ जैसा नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि उसकी अर्थव्यवस्था अब चमत्कारी नहीं रहेगी. यह कहा जा सकता है कि ड्रैगन (चीन) ने फुंफकारना बंद कर दिया है. भारत एक लंबे समय से व्यापारिक (ट्रेडिंग) अर्थव्यवस्था रहा है. इसके शुरुआती दिनों से ही विश्वस्तरीय कपड़ा उद्योग मौजूद था. लेकिन, भारत ने सोवियत मॉडल का चुनाव किया, जो राज्यवादी (स्टेटिस्ट) और पूंजी प्रधान था और जो भारत की सबसे बड़ी ताक़त यानी इसकी श्रमशक्ति इस्तेमाल नहीं कर सका था. नतीजा यह हुआ कि भारत का विकास स्थिरता का शिकार हो गया. 1991 में भारत ने अपना रास्ता बदल दिया और बाज़ारोन्मुख नीति अपनाई, जिससे विकास फिर पटरी पर आ गया. इसके बावजूद भारत आराम नहीं कर सकता. वर्ष 1998 से लेकर 2007 तक की अवधि में भारत की ऊंची विकास दर विश्व की ऊंची विकास दर के कारण थी. फ़िलहाल विकसित देश निम्न विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति के दौर से गुज़र रहे हैं. ऐसे में भारत को विदेशी बाज़ार के उछाल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है. इसके लिए भारत के नेताओं को आधुनिक अर्थशास्त्र की जटिलताएं समझनी होंगी, उन्हें राज्यवादी समाजवाद का मोह छोड़ना होगा. भारतीय राजनेता व्यवसाय विरोध में गर्व महसूस करते हैं, खास तौर पर यदि वह व्यवसाय विदेश से संबंधित हो तो. उन्हें इस तरह के विरोध का त्याग कर देना चाहिए. याद रहे कि कृषि हमारा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र है और किसान एक व्यापारी. अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर व्यापार के अनुकूल विकास मॉडल तैयार करें. उन्हें सूट-बूट का कटाक्ष भूल जाना चाहिए. भारत को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूंजीपतियों का साथ लेना क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है. दरअसल, यही एकमात्र जनहितैषी नीति है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यह लगभग 9 मीटर तक ऊंचा वृक्ष होता है. इसकी छाल हलकी, धूसर वर्ण की होती है. इसकी पुरानी शाखाओं पर आमने-सामने मजबूत कांटे होते हैं. इसके पत्र विपरीत, 5-9 सेमी लम्बे एवं 3.2-6.3 सेमी चौड़े होते हैं. सूखने पर ये काले पड़ जाते हैं और मसलने से दुर्गन्ध आती है. इसके पुष्प हरिताभ पीत वर्ण के, असामान्य गंधयुक्त, 5-10 सेमी चौड़े होते हैं. इसके फल 8 मिमी व्यास के गोलाकार करौंदे की तरह के बैंगनी और काले होते हैं.

रक्त शुद्ध करती है अरणी बड़ी

आयुर्वेदोक्त दशमूल तथा बृहद् पंचमूल का यह (अरणी) भी एक अंग है. यह भारतवर्ष की एक खास औषधि है तथा अति प्राचीनकाल में इसका व्यवहार आयुर्वेद शास्त्रानुसार भिन्न-भिन्न रोगों पर किया जाता था. निघण्टुकारों ने इसके बड़ी और छोटी दो प्रकार बतलाएं हैं. यह उत्तर भारत में विशेषकर गंगा के मैदानों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड से भूटान तक की पहाड़ियों में 2,000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. दशमूल का उपादान होने से इसका मूल पंसारियों के यहां मिलता है.

बाह्यस्वरूप

यह लगभग 9 मीटर तक ऊंचा वृक्ष होता है. इसकी छाल हलकी, धूसर वर्ण की होती है. इसकी पुरानी शाखाओं पर आमने-सामने मजबूत कांटे होते हैं. इसके पत्र विपरीत, 5-9 सेमी लम्बे एवं 3.2-6.3 सेमी चौड़े होते हैं. सूखने पर ये काले पड़ जाते हैं और मसलने से दुर्गन्ध आती है. इसके पुष्प हरिताभ पीत वर्ण के, असामान्य गंधयुक्त, 5-10 सेमी चौड़े होते हैं. इसके फल 8 मिमी व्यास के गोलाकार करौंदे की तरह के बैंगनी और काले होते हैं. इसकी बीज संख्या में 3-4 होते हैं. इसकी लकड़ी मजबूत और सफेद रंग की होती है. उस पर बैंगनी रंग की धारियां पड़ी होती हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एंव प्रभाव

1. बड़ी अरणी अग्निवर्धक, शोथ, कफ, वात , तथा पांडुरोग को हरने वाली, कटु , पौष्टिक, कफघ्न, अनुमोलक तथा शीत-प्रशमनकारक होती है.

2. बड़ी अरणी के पत्र वातानुमोलक, स्तन्यवर्धक तथा आमाशयिक क्रियाविधिवर्धक होते हैं.

3. इसकी मूलत्वक स्तम्भक होती है.

4. इसकी मूल विरेचक, आमाशयिक क्रियाविधिवर्धक, अग्निवर्धक बलकारक, उत्तेजक तथा यकृत की पीड़ा को दूर करने वाली होती है.

5. इसके मेथेनॉल-सार का मौखिक प्रयोग व्याधिक्षमत्व नियामक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग, मात्रा एंव विधि

हृदय रोग

1. हृदय-दौर्बल्य- अरणी के पत्ते और धनिया दोनों को मिलाकर (5-7 ग्राम) क्वाथ बनाकर 30-40 मिली मात्रा में पिलाने से हृदय की दुर्बलता मिटती है.

उदर रोग

1. त्रिदोषज गुल्म-बड़ी या छोटी अरणी की जड़ों को 10-15 ग्राम की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं. 40 मिली गर्म काढ़े में 30 ग्राम गुड़ मिला कर देने से त्रिदोष गुल्म में लाभ होता है.

2. उदर रोग-अरणी की 100 ग्राम जड़ों को लेकर आधा लीटर पानी में मंद आंच पर 15 मिनट तक उबालें तथा 50-60 मिली पानी दिन में दो बार पीने से जठराग्नि प्रबल होती है. यह औषधि पौष्टिक भी है.

3. अरणी के पत्तों को 400 मिली पानी में उबालकर, मसलकर और छानकर 40-50 मिली की मात्रा में पिलाने से आमाशय शूल का शमन होता है.

4. अरणी के पत्तों का क्वाथ बनाकर 20-40 मिली मात्रा सुबह-शाम पीने से मंदादग्नि दूर होती है तथा अफारा में लाभ होता है.

5. अरणी के पत्तों का साग बनाकर खाने से पेट की बादी (वात) मिटती है.

6. अरणी मूल -(5-10 ग्राम) का क्वाथ बनाकर 20-40 मिली क्वाथ को दिन में दो बार पिलाने से ज्वर से पीड़ित व्यक्ति का उदरशूल मिटता है.

7. बद्धकोष्ठ-3 ग्राम अरणी के पत्ते तथा 3 ग्राम बड़ी हरड़ का छिलका लेकर 400 मिली पानी में पकाकर, 100 मिली क्वाथ शेष रहने पर इसे सुबह-शाम 40 मिली की मात्रा में पिलाने से बद्धकोष्ठता मिटती है.

8. अतिसार-अरणी के पञ्चाङ्ग का काढ़ा बनाकर 50 मिली मात्रा में सुबह-शाम पीने से अतिसार में लाभ होता है तथा पेट के कीड़े मर जाते हैं.

9. उदरशोथ-उबाल कर और ठंडा किए हुए जल में अरणीक्षीर घोलकर पीने से तथा उसी जल से अभ्यंग करने से उदरशोथ में लाभ होता है.

10. आध्मान-अरणी पत्र क्वाथ (20-40 मिली) को पीने से आध्मान में लाभ होता है.

11. विबन्ध-अरमई मूल क्वाथ (20-40) को पीने से विबन्ध में लाभ होता है.

गुदा रोग

1. अर्श (बवासीर)-अरणी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10-30 मिली मात्रा में पिलाने से तथा इसके पत्तों की पुल्टिस बनाकर बांधने से अर्श की वेदना कम होती है.

2. अर्श- अर्शांकुरों का स्नेहन करके मूली, त्रिफला, मदार, बांस, वरुण, अरणी, सहिजन तथा अश्मंतक के पत्तों के क्वाथ से भरी हुई द्रोणी (टब) में रोगी को बैठाने से स्वेदन होकर वेदना का शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग

1. हस्तिमेह-अरणी की जड़ व तने के छिलके का क्वाथ बनाकर 40-50 मिली क्वाथ सुबह-शाम पिलाने से हस्तिमेह में लाभ होता है. इस क्वाथ को पीने से वसा-मेह में भी लाभ होता है.

2. इक्षुमेह-अरणी मूल त्वक के क्वाथ (40-50 मिली) में मधु मिलाकर सेवन करने से इक्षुमेह में लाभ होता है.

3. वसामेह-40-60 मिली अरणी मूल क्वाथ का सेवन करने से वसामेह में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग

1. उपदंश- 10-12 मिली अरणी पत्र-स्वरस को प्रात: सायं दो बार कुछ दिनों तक पीने से जीर्ण उपदंश में भी लाभ होता है. उपदंशजन्य शोथ में इसके पत्रों को उबालकर सिकाई करना चाहिए, या इसकी पत्तियों को गर्म कर उसमें घी लगाकर शिश्न पर बांधने से भी लिंग शोथ में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग

1. गठिया-अरणी के पंचांग का क्वाथ बनाकर 40-60 मिली की मात्रा में सुबह-शाम पिलाने से गठिया और स्नायु की वात पीड़ा मिटती है.

2. आमवात-अरणी के पंचांग को पीसकर हलका गर्म करके संधियों पर लेप करने से आमवात में लाभ होता है.

त्वचागत रोग

1. शीतपित्त-2 ग्राम अरणी मूल चूर्ण को, घी के साथ मिलाकर 6 दिन तक सुबह-शाम दोनों समय खाने से शीतपित्त तथा उदर्द रोग मिटता है.

सर्वशरीर रोग

1. सर्वाङ्गशोथ (सूजन)-अरणी मूल की छाल का क्वाथ बनाकर 40 मिली मात्रा में सुबह-शाम पीने से सर्वाङ्गशोथ उदर-शूल तथा जलोदर में लाभ होता है. इसके साथ गोमूत्र अर्क का भी प्रयोग किया जाए तो जल्दी लाभ होता है.

2. अरणी की जड़ और पुनर्नवा की जड़ दोनों को एक साथ पीसकर गर्म कर लेप करने से शरीर की सूजन उतर जाती है. मोच की सूजन में भी लाभप्रद है.

3. ज्वर-बड़ी अरणी की जड़ या तने की छाल को पीसकर थोड़ा सा कपूर मिलाकर मस्तक पर लेप करने से शीत ज्वर में लाभ होता है.

4. अरणी के 10-15 पत्तों और 10 काली मिर्च को पीसकर सुबह-शाम देने से सर्दी के बुखार में लाभ होता है. बच्चों के लिए इसे कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए.

5. रक्तशोधनार्थ- 5 ग्राम अरणी मूल छाल तथा 3 ग्राम नीम की छाल लेकर, क्वाथ बनाकर 20-30 मिली की मात्रा में प्रात: और सायं पीने से रक्त का शोधन होता है.

6. 5 मिली अरणी के रस में मधु मिलाकर प्रतिदिन पिलाने से भी रक्त की शुद्धि होती है.

7. मेदो रोग-अरणी (10 ग्राम) तथा त्रिफला (5 ग्राम) लेकर रात को 1 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगों दें. सुबह क्वाथ बनाकर पीएं. इसी तरह दोनों समय इस प्रयोग को करें . हल्का व सुपाच्य भोजन लें. बढ़ा हुआ मेद व शोथ को दीर करने का यह एक अचूक प्रयोग है (यदि इसके प्रयोग से अतिसार की प्रतीति हो तो उसी के अनुसार मात्रा कम कर दें).

प्रयोज्याङ्ग- त्वक, पत्र, मूल तथा फल.

मात्रा- मूल चूर्ण 2-4 ग्राम, क्वाथ 20-40 मिली, पत्र-स्वरस 5-10 मिली चिकित्सक के परामर्शानुसार ■

आचार्य बालकृष्ण

कैसे करें सरकारी फाइलों का निरीक्षण

सूचना का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल अथवा किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनाई गई है और आप उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी फाइल का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है और यह क्यों ज़रूरी है. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक खास शुल्क अदा करना होगा. कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये मांगे गए. इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की यह मंशा होती है कि ऐसा करने से आवेदक सूचना की मांग नहीं करेगा. आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. इस कॉलम के जरिये हमआरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वाले सभी आवेदकों को सलाह देना चाहेंगे कि जब कभी उन्हें किसी फाइल से कोई सूचना मांगनी हो, तो अपने आरटीआई आवेदन में एक सवाल फाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें अथवा आप चाहें, तो उक्त फाइल के निरीक्षण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे)(1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम फाइल निरीक्षण से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ई-मेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.■

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन-201301

ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(सरकारी फाइल का निरीक्षण)

सेवा में, दिनांक
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम.
पता.

विषय: सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
मैं सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 2(जे)(1) के तहत अमुक फाइल..का निरीक्षण करना चाहता/चाहती हूं. इस संबंध में आप मुझे एक तय तिथि, समय और जगह के बारे में सूचित करें, ताकि मैं आकर उक्त फाइल का निरीक्षण कर सकूं. साथ ही इस बात की भी व्यवस्था करें कि मुझे उक्त फाइल का जो भी हिस्सा चाहिए, उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जा सके. इसके लिए नियत शुल्क का भुगतान मैं कर दूंगा/दूंगी.

मैं इस आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.
हस्ताक्षर.
पता.
दूरभाष.

जानें, क्या है शिक्षा का अधिकार?

- देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करानी होगी. यानी हर बच्चा पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पढ़ेगा.
- निजी ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक होगी और किसी बच्चे को शारीरिक सजा नहीं दी जा सकेगी.
- सभी तरह के सरकारी, अर्द्धसरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी स्कूल इस कानून के दायरे में आएंगे.
- स्कूल न तो प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस ले सकते हैं और न ही किसी तरह का डोनेशन. मनमानी करने पर स्कूल पर 25,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
- सभी स्कूल शिक्षित-प्रशिक्षित अध्यापकों को ही भर्ती करेंगे और अध्यापक-छात्र अनुपात 1:40 रहेगा.
- सभी बच्चों को घर के आसपास स्कूल में दाखिला हासिल करने का हक होगा.
- सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी अनिवार्य है. इसमें क्लासरूम, टॉयलेट, खेल का मैदान, पीने का पानी, दोपहर का भोजन, पुस्तकालय आदि शामिल हैं.
- गैर सरकारी स्कूलों को भी 25 प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्त करनी होंगी, जो ऐसा नहीं करेगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

आंदोलन के कारण नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. एक पखवाड़े से चल रहे आंदोलन के कारण आवश्यक वस्तुओं का निर्यात भारत से पूरी तरह से बन्द है. पेट्रोल, दूध, नमक, दवा, बिस्किट और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है. बावजूद आंदोलनकारी थरूहट और मधेश की मांग को लेकर डटे हैं. वे कैलाली एवं कंचनपुर को मिलाकर थरूहट प्रदेश और मधेश क्षेत्र के शेष जिलों को मिलाकर मधेश प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं.

नेपाल: मधेश और थरूहट प्रदेश की मांग

हिंसक होता जा रहा है आंदोलन

राकेश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

पूरा नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है. दशकों से सुलग रहे मधेश आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया है. मधेश और थरूहट प्रदेश की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 24 अगस्त को एकाएक तब हिंसक रूप ले लिया जब कैलाली जिले के टीकापुर में कर्फ्यू के दौरान सभा कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में दर्जनों मौतें हो गईं. अपुष्ट जानकारी के अनुसार, 50 से ज्यादा आंदोलनकारी मारे गये, जबकि एसएसपी लक्ष्मण न्यूपाने सहित दो इन्सपेक्टर और 17 पुलिस जवान मारे गये. घटना के बावत बताया जा रहा है कि कर्फ्यू को तोड़कर आंदोलनकारी सभा कर रहे थे. एसएसपी सशस्त्र जवानों के साथ सभा को रोकने पहुंचे. इसी दौरान झड़प हो गई और पुलिस ने गोलीबारी कर दी. गोलीबारी में तीन आंदोलनकारी मारे गये. इसके बाद आंदोलनकारी उग्र हो गये और पुलिस पर हमला कर दिया. नेपाली समाचार एजेन्सी के अनुसार भीड़ नें हेड कॉन्सटेबल रामवीर थारू को जिंदा जला दिया. आंदोलन की विकरालता को देखते हुये सेना बुला ली गयी है, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. गृह युद्ध जैसे हालात हैं. आंदोलन फैलता जा रहा है. आंदोलन की आग ने मधेश क्षेत्र के 22 जिलों को अपने गिरफ्त में ले लिया है. सरकारी आदेशों और निषेधाज्ञा का कोई असर नहीं है. लाखों आंदोलनकारी सड़कों पर उतर गये हैं. अनियंत्रित हालात को देखते हुए नेपाली सीमा में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इधर, भारत के गृह मंत्रालय ने भी नेपाल से सटे इलाकों में फैले हिंसा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है. एसएसबी के आला अधिकारी सीमा पर कैम्प कर रहे हैं.

आंदोलन के कारण नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. एक पखवाड़े से चल रहे आंदोलन के कारण आवश्यक वस्तुओं का निर्यात भारत से पूरी तरह से बन्द है. पेट्रोल, दूध, नमक, दवा, बिस्किट और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है. बावजूद आंदोलनकारी थरूहट और मधेश की मांग को लेकर डटे हैं. वे कैलाली एवं कंचनपुर को मिलाकर थरूहट प्रदेश और मधेश क्षेत्र के शेष जिलों को मिलाकर मधेश प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं.

मधेशी आंदोलन की सुगबुगाहट तो संविधान मसौदा निर्माण के समय से ही था. मधेशी और थरूहट समानुपातिक अधिकार की मांग कर रहे थे, जबकि यह भी माना जा रहा था कि इनकी उपेक्षा की जायेगी. नये संविधान के मसौदे में नेपाल में ब्याही गयी भारतीय महिला से जन्मे बच्चे को दोयम दर्जे की नागरिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है. मधेशी इसे अपने मौलिक अधिकारों का हनन मानते हैं. आंदोलन में उबाल का एक कारण यह भी है. लेकिन ये सभी तात्कालिक कारण हैं. इसके मूल में नेपाल का निरंकुश ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था है. नेपाल के शासन, प्रशासन, राजनीति और यहां तक कि मीडिया के उच्च पदों पर पहाड़ी ब्राह्मणों का एकाधिकार है. स्थिति पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा. जनसंख्या के आधार पर पूरे नेपाल में मधेशी 33 प्रतिशत हैं. वहीं जनजाति लोगों की संख्या भी 33 प्रतिशत है. जनजाति मे मगर, राई, गुरूंग, शेरपा, तमांग, नवार आदि उपजातियां शामिल हैं. वहीं क्षेत्री 16 फिसदी और ब्राह्मणों की आबादी 13 प्रतिशत है. स्पष्ट है कि ब्राह्मणों की संख्या अन्य सभी जातियों से कम है, लेकिन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर पहाड़ी ब्राह्मणों का कब्जा है. ऐसे में मधेशी व अन्य लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की नियमावली या नीति निर्धारण में पहाड़ी ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है. पहाड़ी और तराई के लोगों के संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है. शुरू से ही तराई के लोगों द्वारा प्रगतिशील परिवर्तन का प्रयास किया जाता रहा है. तराई के मधेशी और थरूहट के लोग समानुपातिक रूप से राज्य में अपना अधिकार मांगते रहे हैं. नेपाल का माओवादी आंदोलन भी इससे प्रभावित रहा है. हालांकि इन मांगों को कुचलने के लिए तराई क्षेत्र के आन्दोलन को दबाया जाता रहा है.

नेपाल के मधेशी क्षेत्र के सलाही क्षेत्र संख्या 6 के सांसद अमरेश कुमार सिंह के अनुसार, पहाड़ियों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमेशा से मधेशियों का हक छीनती रही है और आंदोलन को दबाने का प्रयास करती रही है. सांसद श्री सिंह के अनुसार, नेपाल में कुल 36,700 सशस्त्र बल के जवान हैं. इनमें से 23,000 सशस्त्र बल मधेशी क्षेत्र में पदस्थापित हैं, जबकि मात्र 13,700 सशस्त्र बलों के बूते पूरे नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था चलाई जाती है, जबकि चीन से जुड़े बडे सीमाई क्षेत्र एवं पूरे पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही राजधानी काठमाण्डू के लिए यह संख्या पर्याप्त नहीं है. फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मधेशी क्षेत्र में सशस्त्र बलों को केवल मधेशियों पर दबाव बनाकर आंदोलन को कुचलने के लिए रखा जाता है. इतना हीं नहीं, मधेशी क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई. इसके विकास के लिए कभी सार्थक प्रयास नहीं किया गया. मधेशी क्षेत्र विकास मद में बहुत कम राशि निर्गत की जाती है. विगत वर्ष विकास के लिए 37 अरब रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के विकास मद में 32 अरब की राशि दी गई. वहीं मधेशी क्षेत्र के लिए मात्र 5 अरब रुपये दिया गया. मधेशियों की उपेक्षा की यह एक बानगी है. हर क्षेत्र में इसी प्रकार उपेक्षित रखकर मधेशियों को गुलाम होने का एहसास कराया जाता है. इतिहास की चर्चा करते हुए सांसद श्री सिंह कहते हैं कि शुरुआती दौर में 104 वर्ष राणा घराने के शासन में ऐसी स्थिति नहीं थी. इसके बाद साह घराने का शासन हुआ. इसी काल में ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया. अब सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमाये हैं और मधेशी क्षेत्र से केवल रेवेन्यू और वोट चाहते हैं.

इस संदर्भ में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और डेनमार्क में नेपाल के राजदूत रह चुके विजय कान्त कर्ण के अनुसार, इसी वर्ष के प्रारम्भ में 16 देशों के लिए राजदूत प्रतिनियुक्त किया गया, जिसमें सभी पहाड़ी हैं. सेना के उच्च पदों पर मधेशी क्षेत्र के लोगों की बहाली नहीं की जाती है. देश के 97 प्रतिशत सीडीओ, जिलाधिकारी पहाड़ी ब्राह्मण ही हैं. मधेशी क्षेत्र भारत से जुड़ा हुआ है और आचार-विचार, व्यवहार लगभग एक समान हैं. एक-दूसरे के बीच बेटी-रोटी का संबंध है. ऐसे में मधेशियों द्वारा जब कभी हक के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत से सहयोग की मांग की जाती है, तब चीन से सहयोग लेने और साथ होने की बात पहाड़ी ब्राह्मणों द्वारा की जाती है. आज तक मधेश क्षेत्र के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है.

सांसद अमरेश कुमार सिंह कहते हैं कि इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है. मधेश और थरूहट प्रदेश की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में थरूहान मुक्ति मोर्चा, मधेशी मुक्ति मोर्चा, नवा मुक्ति मोर्चा, लिम्बवान मुक्ति मोर्चा, तंगवान मुक्ति मोर्चा, मगराथ मुक्ति मोर्चा, खसांग मुक्ति मोर्चा, तमसाली मुक्ति मोर्चा के साथ मधेश क्षेत्र के सभी दल एवं संस्थाए एक मंच पर आ गई हैं. इन्होंने बताया कि मधेश की उपेक्षा से जुड़ी खबरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है. नेपाल के 23 मीडिया घरानों में से 21 पर पहाड़ियों का कब्जा है. मीडिया द्वारा बातों को तोड़-मरोड़ कर परोसा जाता है. कैलाली की घटना के बाद नेपाली राजनीति में हडकंप मच गया है. नेपाल में प्रतिशोधात्मक राजनीति शुरू होने लगी है. कैलाली की घटना के दूसरे दिन ही पहाड़ियों द्वारा थारूओं का घर जला दिया गया, लेकिन बीबीसी नेपाली सेवा के पत्रकार ने इस घटना को महज तोड़-फोड़ बताया. जबकि सूत्र बताते हैं कि इस घटना में दर्जनों लोग मारे गए थे. फिर भी नेपाली मीडिया ने इस घटना को छापने की जहमत भी नहीं उठाई. इसी तरह रौटहत जिला के गौर में आंदोलनकारी राजकिशोर ठाकुर पुलिस की गोली से घायल हो गये, लेकिन पुलिस इन्हें घेर कर रखी रही. बाद में इलाज के लिए वीरगंज ले जाते हुए उनकी मौत हो गई. इन घटनाओं को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है. अब मधेशी और थारू आंदोलनकारियों से ज्यादा आक्रामक सरकार दिख रही है. गृह मंत्री आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं.

वहीं कैलाली की घटना में सांसद अमरेश कुमार सिंह, राजेन्द्र महतो और उपेन्द्र यादव का नाम भी उछाला जा रहा है. ज्ञात हो कि तीनों नेताओं ने कैलाली में सभा को संबोधित किया था. श्री सिंह के संबंध भी गृह मंत्री के साथ अच्छे नहीं रहे हैं. बताया जाता है कि कुछ दिनों पूर्व दोनों के बीच तू तू-मैं मैं भी हुआ था. इधर गृह मंत्री ने अमरेश सिंह द्वारा कैलाली में दिए गए भाषण का ऑडियो रिकॉर्ड संसद में पेश कर कार्रवाई की मांग की है. श्री सिंह नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय सभासद हैं. कैलाली की घटना पर कांग्रेस ने उनसे जवाब मांगा है. बहरहाल, आंदोलन हिंसक होकर भयावह होता जा रहा है, जिसका परोक्ष रूप से पड़ोसी भारत पर भी प्रभाव पड़ना तय है.■

युद्ध अपराधी है थॉमस लुबांगा

हेग में पूर्वी कांगो के संदिग्ध युद्ध अपराधी थॉमस लुबांगा पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पहले मुकदमे में लुबांगा पर बच्चों को फौज में भर्ती करने और युद्ध में झोंकने का आरोप है. 2002 से 2003 के बीच ऐसे 30,000 से ज्यादा बच्चों को बाल सिपाही बनाने का आरोप थॉमस लुबांगा पर था. थॉमस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इतुरी इलाके के सशस्त्र आंदोलन का नेता था. पूर्व का इतुरी क्षेत्र वहां पाए जाने वाले सोने की खानों की वजह से विभिन्न सशस्त्र गुटों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ था. 1999 से शुरू हुई इस लड़ाई में 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है.

लुबांगा ने अपनी सेना के साथ हजारों बच्चों को ट्रेन्ड किया. उसी के बाद उन्होंने खून और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया. 9-10 साल की उम्र के इन बच्चों को लुबांगा ने कहीं का नहीं छोड़ा था. उन बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी. वह कभी नहीं भूल सकते, जो उन्होंने किया और जो सहा. विश्व में ऐसे कई देश हैं, जहां जनता और उस देश की अदालत लुबांगा जैसे अपराधियों के आगे बेबस हैं. पूर्वी कांगो में रह रहे 16 वर्ष के रूकुंदो को अब तक स्कूल जाने की आदत नहीं पड़ी है. कुछ साल पहले तक वह बाल सैनिक था. जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थीं. विज्ञान और गणित से बेहतर उसे एके 47 बंदूक चलाना आता है. महज 9 साल की उम्र में ही वे लोग उसे उठा कर अपने साथ ले गए थे.■

तरुण फोर
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबरें

पाकिस्तान ने दी भारत को धमकी

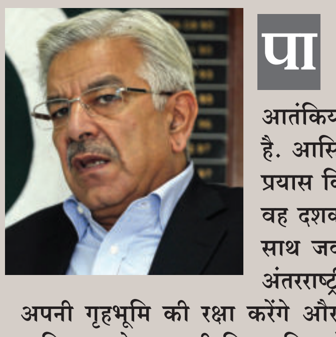

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. हाल में दो जिंदा आतंकियों के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है. आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपने का प्रयास किया तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसे वह दशकों तक याद रखेगा. आसिफ ने कहा कि हमें पूरी ताकत के साथ जवाब देने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि यदि भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करता है और आक्रमण फिर से होता है तो हम अपनी गृहभूमि की रक्षा करेंगे और 1965 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे. सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने खबर दी कि आसिफ ने कहा कि भारतीय बलों की कायराना कार्रवाई से मातृभूमि की रक्षा की देश की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि भारत का वास्तविक चेहरा उजागर हो गया है, क्योंकि वह पाकिस्तान में आतंकवाद की मदद करता है और सीमा और नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे की गोलीबारी कर तनाव पैदा करता है. उनकी टिप्पणी सीमा और नियंत्रण रेखा के पास बढ़ते तनाव के परिप्रेक्ष्य में आई है. भारत ने जब पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर पर बातचीत और अलगाववादियों के साथ उसे बैठक स्वीकार नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान ने पिछले दिनों एनएसए स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी. आसिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस मुद्दे को अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाएंगे.■

माउंट मैकिनले का नाम बदलकर रखा डेनाली

अलास्का में अमेरिका के मूल निवासियों की पुरानी मांग पूरी करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तरी अमेरिका में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट मैकिनले से बदलकर डेनाली रखने का फैसला किया है. वर्ष 1896 में मध्य अलास्का के पर्वतों में खनिजों की खोज करने वाले एक व्यक्ति को सूचना मिली कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विलियम मैकिनले को उम्मीदवार नामित किया गया है. उनके समर्थन में उस व्यक्ति ने अलास्का पर्वतीय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले रख दिया. मैकिनले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल के मात्र छह महीने बाद उनकी हत्या हो गई थी. व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने कभी अलास्का में कदम नहीं रखा और उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची और समुद्र तल से करीब 20,000 फुट उंचाई पर स्थित यह चोटी सदियोंसे डेनाली नाम से जानी जाती है. उसने कहा कि 1975 में अलास्का राज्य द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए राष्ट्रपति ओबामा घोषणा कर रहे हैं कि गृहमंत्री सैली जेवेल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पर्वत का नाम डेनाली रख दिया है.

सैली ने कहा कि अलास्का 1975 से आधिकारिक रूप से इस नाम का इस्तेमाल करता आया है. एक और अहम बात यह है कि इसे पीढ़ियों से डेनाली के नाम से ही जाना जाता है.■

एक वक्त की बात है

क्रिस्टोफर कोलम्बस

18 सितंबर 1502 को ही ओवेन्स क्रिस्टोफर ने अपनी चौथी और आखिरी यात्रा के दौरान कोस्टारीका में कदम रखा था. कोलम्बस का जन्म इटली में हुआ था. वह एक इटैलियन समुद्रि-नाविक, उपनिवेशवादी और खोजी यात्री के तौर पर विश्व में जाने जाते हैं. कोलम्बस बचपन से ही अपने सिद्धांतों पर चलने वाले और एक नई दुनिया को देखने के लिये ललायित रहते थे. इसी वजह से आगे चलकर कोलम्बस को खोजी यात्री कहा जाने लगा. उन्होंने अपनी इस खोज का प्रस्ताव राजसी दम्पत्ति के सामने रखते हुए कहा कि कृपया आप मुझे भारत की खोज के लिये जाने की अनुमति दीजिए. आगे उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारतीय गरम मसाले यूरोपीय मांस खानेवालों के लिये अत्यंत आवश्यक होने लगे थे. कोलम्बस ने भारतीय वैभव को हथियाने के मंसूबे से ही व्यापारी जहाज लेकर एक नई दुनिया की खोज में प्रवेश करने का निर्णय लिया. वे निकले तो थे भारत की खोज में, लेकिन पहुंच गये अमेरिका. कोलम्बस अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे, लेकिन कोलम्बस ने यूरोपवासियों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच विस्तृत सम्पर्क को बढ़ावा दिया. उन्होंने अमेरिका की चार यात्रा की, जिसका खर्च स्पेन की रानी इसाबेला ने उठाया. 1492 से 1503 के बीच अपनी चार यात्राओं के दौरान उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों की खोज की थी. इसी वजह से कोलम्बस की चार यात्राओं को पश्चिमी देशों के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है.■

बुद्ध ने कहा कि लोगों द्वारा स्तुति की वर्षा किए जाने पर या निंदा के अंगारे बरसाने पर ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है. प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई असर नहीं पड़ता. युवक ने अपने बारे में सोचा तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई. वह तुरंत बुद्ध के कदमों पर गिरकर बोला कि अब तक मैं भूल में था. मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है.

साईं वंदना

सद्गुरु में दिव्य ईश्वरीय चेतना होती है

वास्तव में सद्गुरु दो चेतनाओं के स्तर पर कार्य करते हैं. एक ओर उनमें दिव्य ईश्वरीय चेतना होती है और दूसरी ओर शरीर धारण करने के कारण वे सामान्य आदमी की चेतना के स्तर पर भी रहते हैं.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

हमने सुना है कि शिरडी में साईं बाबा रात भर नहीं सोते थे और हरि का नाम लेते थे. क्या यह सच है?

चूंकि सद्गुरु जीवनमुक्त हैं, इसलिए वे चाहे शरीर में रहें या शरीर छोड़ दें, हर समय पूर्ण चेतना-अवस्था में रहते हैं. जब उनको शरीर के माध्यम से स्थूल रूप से कार्य करना पड़ता है, तब भी वह स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही रूपों में सक्रिय रहते हैं. एक प्रकार से कहा जाए तो यह दिव्य आत्मा एक शरीर को ओढ़कर आती है जैसे कि कोई कंबल ओढ़ता हो. अपना कार्य पूरा होने पर, इच्छा से वह उसे छोड़ देते हैं, जैसे कि किसी ने अपने शरीर से कपड़ा उतार कर रख दिया हो. इसलिए शरीर रखने के लिए उन्हें स्थूल आहार या नींद की आवश्यकता नहीं है. यही कारण है कि उनकी इच्छानुसार बिना आहार के उनका स्थूल शरीर जिंदा रहता है. कई संतों ने तो सालों-साल तक न भोजन किया, न ही वे सोए थे. निद्रा मृत्यु का एक छोटा रूप है. मृत्यु के बाद आदमी की आत्मा एक तंद्रा या निद्रावस्था में रहती है. जन्म के समय वह फिर सचेतन होता है. उसे चेतना-शक्ति मिलती है. चूंकि सद्गुरु का जन्म या मृत्यु नहीं होती है, इसलिए वे हर समय जागृतावस्था में रहते हैं. जैसे वे यदि आंख भी बंद किए लेटे हों, तब भी वे जागृतावस्था में रहते हैं.

बाबा शारीरिक बीमारियों से अछूते क्यों नहीं?

श्री साईं सच्चरित्र में लिखित है कि बाबा कभी-कभी बीमार रहते थे. क्या सद्गुरु वास्तव में बीमार पड़ते हैं या वह उनकी कोई लीला है?

अधिकांश भक्तों ने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि चूंकि सद्गुरु दिव्य एवं चमत्कारी शक्तियों से युक्त होते हैं. अत: उन्हें जो शारीरिक कष्ट आदि होते हैं, उनका भी निवारण वे अपनी दिव्य चमत्कारिक शक्तियों से कर लेते होंगे. वस्तुत: लोगों की यह अवधारणा सत्य नहीं है. लोग सम्भवत: यह नहीं समझ पाते कि उच्चतम ईश्वरीय अवस्था में पहुंचने के पश्चात् भी यदि करुणावश सद्गुरु इस पृथ्वी पर आए हैं और उन्होंने देह-धारण की है, तो देह से संबंधित पीड़ा, कष्ट आदि भी वे झेलते हैं. उन्हें भी शरीरगत बीमारियां होती हैं, पर वे अपने कष्ट को भक्तों के समक्ष वयक्त नहीं करते हैं बल्कि साथ में भक्तों के कष्टों को भी अपने ऊपर लेते हैं. बाबा ने कहा था कि मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है. उनके कष्ट मेरे हैं. (सा.स अध्याय-7, पृ.-48) श्री रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था, पर उस हालत में भी वे अपने भक्तों को आखिर तक प्रवचन देते रहे.

वास्तव में सद्गुरु दो चेतनाओं के स्तर पर कार्य करते हैं. एक ओर उनमें दिव्य ईश्वरीय चेतना होती है और दूसरी ओर शरीर धारण करने के कारण वे सामान्य आदमी की चेतना के स्तर पर भी रहते हैं. जब वे परम चेतना या ब्रह्मानंद की स्थिति में रहते हैं, तो अपनी इच्छामात्र से अलौकिक कार्य कर सकते हैं. लेकिन उनकी महत् इच्छा में कुछ भी अपने लिए नहीं होता. उसमें भक्तों के लिए सर्वस्व त्याग है. दूसरी ओर जब वह सामान्य चेतना के स्तर पर रहते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति शरीर और समाज से जुड़ी हर समस्या एवं कष्ट को झेलते हैं.

शुभ्र मार्ग

बाबा ने शुभ्र मार्ग का उल्लेख किया है. यह शुभ्र मार्ग क्या है?

बाबा ने हठ योग, तंत्र-साधना, प्राणायाम एवं अन्य योग-साधना के बारे में कहीं नहीं बताया. उन्होंने मुख्यत मन को नियंत्रित करने का मार्ग सुझाया. वे सबके मन को जानते थे. श्री साईं सच्चरित्र में कई उदाहरण हैं कि जब भी लोगों के मन में गलत भावना उठी, तो उन्होंने तत्काल या बाद में टोका. उन्होंने उपासनी महाराज, काका साहेब दीक्षित, म्हालसापति आदि भक्तों को लोगों से अलग रहकर धर्म-ग्रंथ पढ़कर अशुद्ध-भावना से दूर रहने के लिए कहा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मार्ग में यह भी आवश्यक है कि भक्त अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए केवल गुरु को ही आधार माने, क्योंकि समर्थ सद्गुरु उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने में सक्षम हैं. जब भक्त की गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा होती है, तो समर्थ सद्गुरु शुभ्र-मार्ग पर अग्रसर होने की दिशा में उनकी सहायता करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

गवीपुरम गुफा मंदिर

साल में एक दिन सूर्य की रोशनी शिवलिंग पर पड़ती है

चौथी दुनिया ब्यूरो

दक्षिण भारत के शहर बेंगलुरु में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे गवीपुरम गुफा नाम से जाना जाता है. यह मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है. यह अपने वास्तुशिल्पीय बनावट के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है. इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह है कि हर साल एक खास समय पर सूर्य की रोशनी मंदिर के गर्भ गृह में रखी भगनाव शिव की प्रतिमा पर पड़ती है. भगवान शिव और गवी गंगाधरश्रवरा को समर्पित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है. इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में एक मोनोलिथिक रॉक से बनाया गया था. इस मंदिर की खासियत है मकर संक्रांति के दिन गवी गंगाधरश्रवरा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. मकर सक्रांति के दिन मंदिर में स्थित शिवलिंग पर करीब एक घंट तक पड़ती है. सूर्य की रोशनी मंदिर के सामने रखी नंदी के दोनों सिंघों के बीच से होकर गुजरती है. इससे यह पता चलता है कि हमारे प्रचीन मूर्तिकार खगोल विद्या और वास्तुशिल्प के कितने अच्छे जानकार थे. भगवान शिव का तीर्थस्थल होने के अलावा मंदिर में अग्नि के भगवान की एक दुर्लभ प्रतिमा रखी गई है. आज गवी गंगाधरश्रवरा गुफा मंदिर एक स्मारक है, जो पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1961 और कर्नाटक प्रचीन व ऐतिहासिक स्मारक के अंतर्गत संरक्षित है. यह मंदिर काफी हद तक शहर के अंतर्गत ही आता है और बसवनगुड़ी के पास है. पर्यटकों को

यहां पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. यहां जाने के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन से आप बेगलुरु जाएं और वहां से आप टैक्सी, ऑटो या बस से जा सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेहतर और कम बात करें

एक व्यक्ति दुनिया घूमकर आया और बड़ी-बड़ी बातें करने लगा. जो भी उसके पास जाता तो वह उससे कई प्रश्न किया करता. जब यह बात गौतम बुद्ध को पता चली तो वह वेश बदलकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे.

उस व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया. कौन हो तुम? कहीं ब्राह्मण तो नहीं. बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने शरीर और मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है. मैं ऐसा ही एक मनुष्य हूं. जब उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा कि आप अपना उत्तर फिर से दें. तब बुद्ध ने कहा कि जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नौका चलाता है और विद्वान वाद-विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष स्वयं पर ही शासन करता है. युवक ने फिर से पूछा कि ज्ञानी पुरुष भला स्वयं पर शासन कैसे करता होगा?

बुद्ध ने कहा कि लोगों द्वारा स्तुति की वर्षा किए जाने पर या निंदा के अंगारे बरसाने पर ज्ञानी पुरुष का मन शांत ही रहता है. प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई असर नहीं पड़ता. युवक ने अपने बारे में सोचा तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई.

वह तुरंत बुद्ध के कदमों पर गिरकर बोला कि अब तक मैं भूल में था. मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

एक ही मतदाता सूची से कराए जाएं चुनाव

निर्वाचन आयोग से मेरा एक सवाल है कि सभी चुनाव एक ही मतदाता सूची से क्यों नहीं कराए जाते? मैं लगभग दस आमचुनावों से अपने मताधिकार का प्रयोग करता आ रहा हूं. मैं तो यही देखते आया हूं कि रसूखदार प्रधान हमेशा से सूची में अपने समर्थकों के नाम बढ़वाते तथा विरोधियों के कटवाते आए हैं. चतुर पालिकाध्यक्ष व प्रधान अपने लोगों को मतदान अधिकारी बनवाते हैं. प्रात: वोटिंग शुरू होते ही अपने आदमी अंदर भेजकर विरोधियों के वोट अपने पक्ष में डलवा लेते हैं. सही व्यक्ति जब पहुंचता है, तो पता लगता है कि उसका वोट पड़ चुका है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनरोध है कि वह सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि सभी चुनाव एक ही मतदाता सूची से कराए जाएं. आम चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव अलग-अलग सूचियों से कराना असंवैधानिक है.

-राजकिशोर पाण्डेय (प्रहरी), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

अंधविरोध की हद

लोकसभा के पूर्व महासचिव सीके जैन ने अपनी पुस्तक में (ऑल इंडिया कांफ्रेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स) में यूरोप के विद्वान वाल्टर लिपमैन के हवाले से लिखा कि उच्च पदस्थ लोग संस्थाओं के प्रशासक मात्र नहीं होते, वे अपने देश के राष्ट्रीय आदर्शों, विश्वासों तथा अभिलाषाओं के संरक्षक भी होते हैं. इसीलिए डॉ राजेन्द्र प्रसाद से लेकर प्रणव मुखर्जी तक तथा नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने संसदीय गरिमा के संवर्धन के लिए आजीवन प्रयास किए. नरेन्द्र मोदी ने भी संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेककर यही संदेश दिया कि संसद प्रणम्य है, लेकिन आज कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है. जनता देख रही है कि अंध विरोध कर कांग्रेस संसदीय परंपरा को तहस नहस कर रही है. ऐसे में कार्यवाही में बाधा के खिलाफ सख्त प्रावधान होने चाहिए तथा देश हित में संसद में बैठकों की संख्या व समय को बढ़ाना चाहिए और उसमें सांसदों की उपस्थिति को बाध्यकारी बनाकर राष्ट्रक्षति की भरपाई की जानी चाहिए.

-सत्य प्रकाश(शिक्षक), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

किसानों की आत्महत्याएं कब रुकेंगी

कवर स्टोरी-किसानों की आत्म हत्या राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं (31 अगस्त-06 सितंबर 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. शशि शेखर ने बिल्कुल सही कहा है कि किसानों की आत्महत्या राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं? भारत की जीडीपी कृषि के ऊपर निर्भर है और कृषि किसानों से है, लेकिन आज किसानों की हालत दयनीय है और जब किसान ही नहीं रहेगा, तो खेती कौन करेगा? किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है. जो भी सरकार आती है, वो किसनों के हित की बात तो करती है, लेकिन किसानों के लिए करती कुछ नहीं है. कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया. किसान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई. मोदी सरकार भी किसानों के हित के लिए बड़ी-बड़ी तो बातें करती है. देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मन की बात में कई बार किसानों के हितों की बात कह चुके हैं. मोदी सरकार बने भी एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ. अब यह देखना होगा कि मोदी सरकार भी किसानों को पहली सरकारों की तरह केवल आश्वासन देती है या उनके लिए कोई काम भी करती है.

-शिवशंकर सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

विकास के खोखले दावे

आलेख-सरेया अख्तियार की सूनी गलियां, बिहार के हर गांव की यही कहानी है (31 अगस्त-06 सितंबर 2015) पढ़ा. मैं मनीष कुमार से सहमत हूं कि सरेया अख्तियार की सूनी गलियों की तरह बिहार के हर गांव की यही कहानी है. बिहार की सरकारें विकास की बड़े-बड़े दावें करती हैं, लेकिन बिहार के गांवों में जाओं तो असली सच्चाई का पता चलता है. बिहार से पलायन को रोकने में अब तक सभी सरकारें नाकाम रही हैं. बिहार की ट्रेनों में आप यात्रा करके देख लीजिए, तो बिहार भी जाने की जरूरत नहीं, आपको बिहार के सारे विकास की सच्चाई दिख जाएगी. बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, राजद की भी सरकार रही. आज बड़ी-बड़ी बाते करने वाले लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे और अब विकास की बाते करते हैं. एनडीए की सरकार भी रही है और वह भी पलायन रोकने में नाकामयाब रही. तब एनडीए में जदयू शामिल था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जदयू ने भाजपा से अपना 18 साल पुराना गठबंठन तोड़ लिया. अब नीतीश कुमार महागठबंधन(कांग्रेस, राजद, जदयू) के नेता हैं और बिहार में जीत का दावा कर रहे हैं. भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में मुख्य पार्टियां एलजेपी, रालोसपा आदि शामिल हैं. चाहे जिसकी सरकार बने उसके सामने बिहार के विकास से अधिक बिहार से पलायन रोकने की चुनौती होगी.

-रामेश्वर तिवारी, बक्सर, बिहार.

यह सराहनीय कदम है

जब तोप मुकाबिल हो-आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के महान योद्धा हैं(31 अगस्त-06 सितंबर 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के महान योद्धा हैं. आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों की खोज की है, जो कई लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं. बाबा रामदेव ने जिस प्रकार पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया है, वो काफी सराहनीय है. आचार्य बालकृष्ण असाध्य रोगों को ठीक करने के काम में आयुर्वेद और योग का प्रयोग कर पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं.

-रामवृक्ष यादव, दरभंगा, बिहार.

विवादों के बवंडर में युवा लेखक

अनंत विजय

इन दिनों हिंदी साहित्य जगत में युवा लेखन और लेखक को लेकर घमासान मचा हुआ है. दरअसल पूरा प्रसंग ये है कि दिल्ली की हिंदी अकादमी ने युवा कहानी और युवा कविता पर दो दिनों का आयोजन किया. हिंदी की वरिष्ठ और चर्चित लेखिका मैत्रेयी पुष्पा के हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनने के बाद अकादमी का ये पहला बड़ा आयोजन था. कविता पर जो आयोजन हुआ था, उसका नाम था 'कविता के नए रूपाकार, युवा कवियों के साथ एक शाम'. कहानी पर हुए आयोजन को नाम दिया गया था 'हमारे समय की हिंदी कहानियां, स्वरूप और संभावनाएं'. सरकारी कार्यक्रम के लिहाज़ से देखें तो आयोजन बेहतर था. पूरे आयोजन पर मैत्रेयी पुष्पा की छाप दिख रही थी, उनकी पसंद और नापसंद दोनों की. कविता पर हुए आयोजन पर जिन कवियों को बुलाया गया था उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब हो-हल्ला मचा. कवियों की उम्र को लेकर भी छींटाकशी की गई. विरोधस्वरूप दिल्ली के दर्जनभर से ज्यादा युवा कवियों ने एक अलग आयोजन किया और अपनी कविताएं पढ़ीं. यह सब तो साहित्य में हमेशा से चलता रहा है. सरकारी आयोजनों में जो उसके कर्ताधर्ता होते हैं उनकी ही चलती है लेकिन इस बार हिंदी अकादमी का चयन अपेक्षाकृत कम विवादित रहा. हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा ने सोशल मीडिया पर अपने अनेकानेक पोस्ट में इस बात को रखा कि अकादमी का यह पहला आयोजन है और उसको उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए, लेकिन युवा को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध जारी रहा. युवा शब्द पर हुए इस विवाद की भी वजह है जिसका जिक्र इस लेख में आगे आएगा. फेसबुक आदि पर मचे हो-हल्ले के बीच आयोजन के दौरान हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष मैत्रेयी पुष्पा ने मंच से एलान किया कि अगले आयोजन से युवा शब्द हटा दिया जाएगा. इसको हिंदी के युवा लेखक और कवि अपनी जीत के तौर पेश कर रहे हैं. उन युवा लेखकों को ये सोचना होगा कि साहित्य में जीत या हार नहीं होती है. बहुत दिनों बाद हिंदी अकादमी को एक सक्रिय उपाध्यक्ष मिला है. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो वस्तुनिष्ठ होकर साहित्य के लिए काम करेंगी. उनको थोड़ा मौका भी दिया जाना चाहिए. हालांकि उनको जो टीम मिली है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद बेमानी है, चंद लोगों को छोड़कर उनमें से ज्यादातर के साहित्यक अवदान को हिंदी साहित्य के सामने आना शेष है. हैरानी की बात तो यह है कि कहानी पर हुए आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पांडे को सौंपने का फैसला किस आधार पर लिया गया? कम से कम मेरे जैसा पाठक अब तक मैनेजर पांडे के कहानी पर किए गए काम से अनभिज्ञ है. कार्यक्रम में मैनेजर पांडेय ने मेरी की आशंका को सही साबित किया. उन्होंने इस आयोजन में न तो कहानी के स्वरूप और न ही संभावना पर गंभीरता से कोई अवधारणा प्रस्तुत की. एक अनाम पक्षिका के विशेषांक लेकर पहुंचे और उसके ही आधार पर कहानी के वर्तमान पर भाषण दे दिया. मैनेजर पांडे को बुलाने की वजह समझ से परे है. मैत्रेयी पुष्पा को मैं करीब डेढ़ दशक से ज्यादा वक्त से जानता हूं, वो जो ठान लेती हैं उस पर चलती हैं. तमाम विरोध और झंझावातों के बावजूद. इस वजह से ही शायद उन्होंने मैनेजर पांडे को नहीं बदला होगा. अगर चयन में थोड़ी बहुत खामी रह जाए या फिर अपने अपने लोगों को बुलाया जाए तो किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले सोशल मीडिया पर सक्रिय लेखकों को धैर्य रखना चाहिए. सावधान तो उपाध्यक्ष को भी रहना चाहिए, उन्हें अब काफी लोग तारीफ करनेवाले मिलेंगे. आनेवाले दिनों में उन पर संचयन, पत्रिकाओं के विशेषांक आदि भी निकलेंगे. अगर इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलता है तो ज़ाहिर तौर पर वो घिरेंगी लेकिन हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि ऐसा ही होगा. खैर ये एक अवांतर प्रंसग है, जिसपर भविष्य में चर्चा होगी.

मैनेजर पांडे

मैत्रेयी पुष्पा

बात हो रही थी हिंदी में युवा लेखकों पर. साहित्य में युवा कहने की कोई सीमा नहीं है. पचास पार या पचास को छूते लेखक को हिंदी साहित्य समाज में युवा माना जाता है. साहित्य अकादमी जो युवा सम्मान देती है उसके मुताबिक लेखक की उम्र पैंतीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हिंदी में एक साथ इतनी पीढ़ियां सक्रिय हैं कि सब गड्डमड हो गया है. जिसके जो मन हो रहा है वो लिख रहा है. इस तरह के अराजक माहौल में चालीस पचास साल पार के लेखक-लेखिका भी युवा हुए जा रहे हैं. इस संदर्भ में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग याद आता है. सन 2000 की बात होगी. हंस पत्रिका के दफ्तर में उसके संपादक राजेन्द्र यादव से मिलने गया था. हंस का ताजा अंक आया था जो यादव जी ने मेरी तरफ बढ़ाया. मैंने पन्ने पलटने के बाद उनसे पूछा कि बुढ़ाती लेखिकाओं की आप जवानी के दिनों की तस्वीरें क्यों छापते हैं. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में गंभीर बात कह दी. उन्होंने कहा कि हिंदी के कई पाठक लेखिकाओं की तस्वीर देखकर हंस खरीद लेते हैं. अब जब युवा लेखक की उम्र को लेकर जब एक बार फिर से विवाद हो रहा है तो राजेन्द्र यादव की बात जेहन में कौंधी. कहीं ऐसा तो नहीं कि युवा कहकर युवाओं से जुड़ने की जुगत में उदारता के साथ लेखक खुद को या आयोजक लेखक को या आलोचक लेखक को युवा घोषित कर देता है. हालांकि यह बहुत दूर की कौड़ी है लेकिन कौड़ी है अच्छी.

कुछ दिनों पहले मैत्रेयी पुष्पा जी ने भी स्त्री विमर्श को लेकर एक लंबा लेख लिखा था. उस लेख में मैत्रेयी जी ने लिखा था-'इक्कीसवीं सदी में जबसे युवा लेखन का फतवा चला है, लेखन की दुनिया में खासी तेजी आई है. लेखिकाओं की भरी-पूरी जमात हमें आश्वस्त करती है. किताबें और किताबें. लोकार्पण और लोकार्पण. इनाम, खिताब, पुरस्कार जैसा बहुत कुछ. प्रकाशक, संपादक भी अपने-अपने स्टाल लेकर हाजिर. अपने-अपने जलसों की आवृत्तियां. कैसा उत्सवमय समां है. कौन कहता है कि यह दरिद्रगी और दहशत भरा समय और समाज है? साहित्य जगत तो यहां आनंदलोक के साथ है. नाच-गाने और डीजे. शानदार पार्टियां और आपसी रिश्तों के जश्न. ऐसा लगता है जैसे कितनी ही कालजयी रचनाएं आई हैं. मगर इस समय की कलमकार के अपने रूप क्या हैं? युवा के सिवा कुछ भी नहीं, यह युवा लेखिका का फतवा किस दोस्त या दुश्मन ने चलाया कि इस समय की रचनाकार अपनी उम्र का असली सन तक अपने बायोडाटा में दर्ज नहीं करतीं, क्योंकि उम्र जगजाहिर करना युवा लेखन के दायरे से खारिज होना है. वे लेखन के हल्केपन की परवाह नहीं करतीं, जवानी को संजोए रखने की चिंता में हैं. इसी तर्ज पर कि रचना में कमी-बेसी से डर नहीं लगता साब, वयस्क कहे जाने से डर लगता है. परवाह नहीं उम्र पैंतालीस से पचास पर पहुंच जाए, युवा कहलाने का अनिर्वचनीय सुख मिलता रहे लगता है मैत्रेयी जी जब हिंदी अकादमी के आयोजनों के लिए लेखकों का चयन कर रही थीं तो उन्होंने अपनी ही कही इस बात को भुला दिया. युवा के नाम पर चालीस पार की लेखिकाओं और लेखकों को युवा घोषित करते हुए कार्यक्रम में जगह दे दी. क्या वो अपना कहा ही भूल गईं कि जो लेखिका अपने बायोडाटा में अपनी उम्र इसलिए दर्ज नहीं करती क्योंकि उम्र ज़ाहिर करना युवा लेखन के दायरे से खारिज होना है. क्या वो भी आमंत्रित लेखक-लेखिकाओं को वयस्क कहने से डर गईं. दरअसल सरकारी आयोजनों में एक कमेटी प्रतिभागियों का चुनाव करती है. संभव है उपाध्यक्ष ने चुनाव करते समय कमेटी के सदस्यों को छूट दी होगी. उस छूट का ही नतीजा है कि कुछ ऐसे लेखकों का चयन हो गया जिन पर और जिनके लेखन पर विवाद उठ खड़ा हो गया. यह भी संभव है कि युवाओं को जोड़ने का अनिर्वचनीय सुख हिंदी अकादमी भी लेना चाहती हो. हिंदी में युवा कहलाने का जो फैशन है उसपर गाहे-बगाहे विवाद होता रहा है. मेरा मानना है कि साहित्यक विवाद होने चाक्शि. इससे साहित्य की सेहत अच्छी बनी रहती है लेकिन जब विवाद के बीच व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं, किसी के चरित्र से लेकर व्यक्तित्व पर सवाल खड़े होने लगते हैं तब साहित्य बीमार पड़ने लगता है. साहित्य में विवादों की एक लंबी परंपरा रही है लेकिन जिस तरह से उसको सोशल मीडिया ने मंच और हवा दोनों दी वो चिंता की बात है. लेखन पर सवाल खड़े होने चाहिए तर्कों और तथ्यों के साथ, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा लेखक क्यों ना हो? युवाओं के लेखन को खास तौर पर कसौटी पर कसना चाहिए. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

हरिवंश राय बच्चन

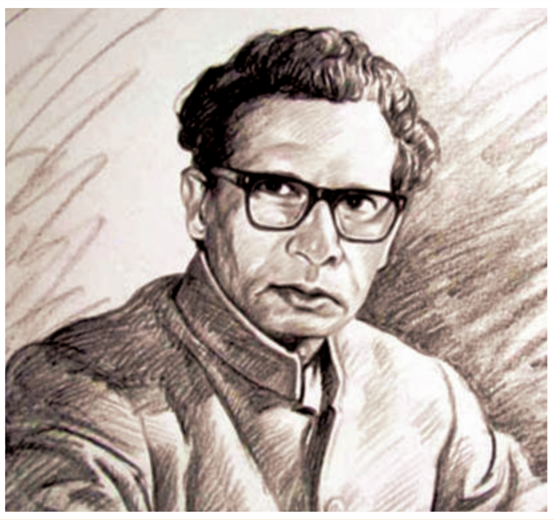

तुम तूफ़ान समझ पाओगे?

गीले बादल, पीछे रजकण,
सूखे पत्ते, रूखे तृण घन
लेकर चलता करता 'हरहर'
इसका गान समझ पाओगे?
तुम तूफ़ान समझ पाओगे?
गंध-भरा यह मंद पवन था,
लहराता इससे मधुवन था,
सहसा इसका टूट गया
जो स्वप्न महान, समझ पाओगे?
तुम तूफ़ान समझ पाओगे?
तोड़-मरोड़ विटप लतिकाएं,
नोच-खसोट कुसुम-कलिकाएं,
जाता है अज्ञात दिशा को!
हटो विहंगम, उड़ जाओगे!
तुम तूफ़ान समझ पाओगे?

आज मुझसे बोल, बादल!

तम भरा तू, तम भरा मैं,
गम भरा तू, गम भरा मैं,
आज तू अपने हृदय से
हृदय मेरा तोल, बादल!
आज मुझसे बोल, बादल!
आग तुझमें, आग मुझमें,
राग तुझमें, राग मुझमें,
आ मिलें हम आज
अपने द्वार उर के खोल, बादल!
आज मुझसे बोल, बादल!
भेद यह मत देख दो पल-
क्षार जल मैं, तू मधुर जल,
व्यर्थ मेरे अश्रु, तेरी बूंद है
अनमोल बादल!
आज मुझसे बोल, बादल! ■

(हरिवंश जी की प्रख्यात कृति निशा निमंत्रण से दो कविताएं.)

साहित्यकार

रॉबर्ट ब्राउनिंग

रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियाई युग के अंग्रेजी साहित्यकारों में अग्रणी स्थान रखते हैं. ड्रामाटिक वर्स और ड्रामाटिक मोनोलॉग में उनके महारत ने उन्हें अंग्रेजी के सर्वकालिक बेहतरीन साहित्यकारों में स्थान दिलवाया. उनकी कविताएं विडंबना, डार्क ह्यूमर, सामाजिक कमेंट्री, ऐतिहासिक परिपेक्ष्य, बेहतरीन शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास के लिए जाने जाते थे. उनकी रचनाओं में नायक के रूप में अक्सर संगीतकार और चित्रकार मौजूद रहा करते थे. उनकी कविताएं लास्ट राइड टुगेदर, प्रोसपिके, माई लास्ट डचेस, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन हैं. रॉबर्ट को अपनी कविताओं में रॉबस्ट आप्टिमिजम के प्रयोग के लिए जाना है. रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी एलिजाबेथ बैरेट को भी विक्टोरियाई युग के प्रमुख साहित्यकारों में गिना जाता है.

चलो गांव की ओर : एक अभियान

कुमार कृष्णन

आजादी के बाद जिस अनुपात में महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों का विकास हुआ उसी अनुपात में गांव पिछड़ता चला गया और शुरू हो गया गांव से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला. फलस्वरूप गांव में खेती,पशुपालन और घरेलू उद्योग चौपट हो गए. कल और आज के गांव में बुनियादी फर्क आ गया है, जिससे हमारे लोकजीवन में विकृतियां बढ़ी हैं. धीरे-धीरे लोक संस्कृति, लौकिक रीति- रिवाज और परंपराओं में भारी बदलाव के कारण गांव में रहनेवालों की जीवन-शैली बदल गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, रोजगार के मसले का समाधान आजादी के 67 वर्षों बाद भी नहीं हो पाया है. लोकतंत्र खत्म हो गया और विकास की किरणें पहुंची नहीं. नृपेन्द्र प्रसाद वर्मा का प्रकाशित ग्रामीण जीवन पर आधारित 51 कविताओं का संग्रह 'चलो गांव की ओर' टूटते और शहरीकरण की भेंट चढ़ते गांव की तल्ख सच्चाईयों को बयां करता है. इस संग्रह का शीर्षक 'चलो गांव की ओर' रखा गया है जो शहर से गांव की ओर लौटने का कवि का अभियान है. भारत कभी गांवों का देश कहलाता था पर अब शहरों का देश हो गया है. शहर फैलता जा रहा है और गांव सिकुड़ता चला जा रहा है. 92 हजार गांव विकास तथा शहरीकरण की भेंट चढ़ गए. खेती,पशुपालन एवं अन्य कार्यों के लिए कामगारों की कमी होती जा रही है. तभी तो कवि कहता है- 'सब के सब गांव छोड़कर/ भागे जा रहे हैं शहर की ओर/ भेड़ियाधसान हो रहे हैं/ भौतिकता के अंधे कुएं में/ठप्प पड़ गया है/ गांव में खेती और पशुपालन का धंधा.' पूरे देश को अन्न खनिज,श्रम और सीमा पर सुरक्षा के लिए जवान देनेवाले गांव अब खत्म होने की कगार पर हैं. राजनीतिक नफा-नुकसान के लिहाज़ से गांव के हक को मार कर सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है,जो गांव को खत्म कर ही बनेंगे. गांव का विकास तो नहीं हुआ परन्तु शहरी विकृति ने गांव की जीवन शैली को बदमिजाज़ जरूर कर दिया है. ग्रामीण संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है. स्थिति ऐसी हो गई है कि 'न घर के रहे न घाट के' कहावत चरितार्थ हो रही है. दलित और स्त्री चेतना के नाम पर ठगा जा रहा है. अब भी गांव में बंधुआ मजदूर और स्त्री के शोषण-उत्पीड़न की व्यथा-कथा सुनने को मिलती है. राजनीतिक छद्म-छल की धूल तेजी से गांव में उड़ने लगी है. गांव के लोग जितने सरल

पुस्तक समीक्षा

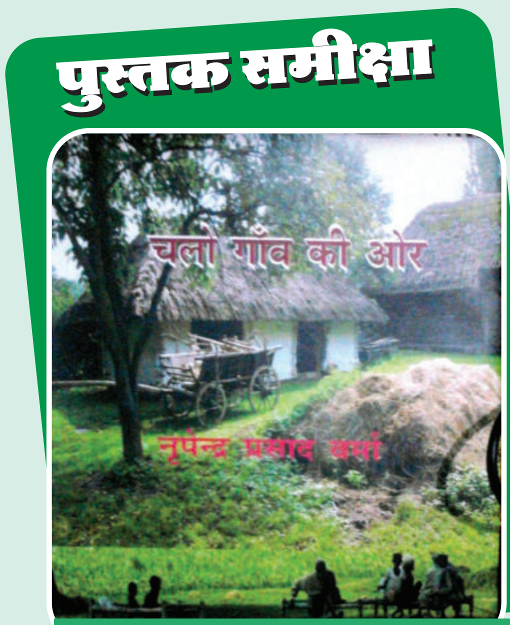

पुस्तक - चलो गांव की ओर
कवि - नृपेन्द्र प्रसाद वर्मा
मूल्य - 250/रूपये
प्रकाशक - मानव प्रकाशन,131, चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700073

और निश्छल भाव के होते थे अब उनमें प्रपंच के पौधें उगने लगे हैं. यह एक साजिश के तहत हो रहा है कि गांव के लोगों की चेतना न जगे. वे अपने अधिकार के लिए आवाज न उठा सकें.

इस दशा से कवि मर्माहत है. गंवई जीवन की भोगी हुई वास्तविकता की आहट इस संग्रह की प्राय: कविताओं में सुनाई पड़ती है. स्वावलंबी गांव को खत्म कर बाजार गांव का वैभव लूट रहा है. लगातार किसानों की आत्महत्या गांव की स्थिति को बयां करने को काफी है. मजदूरों का लगातार पलायन सरकारी योजनाओं की सफलता और उसके कार्यान्वयन पर सवाल खड़े करती हैंङ्क. कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा मिला है. जगह-जगह विस्थापन के सवाल पर संघर्ष विकास के विरोध में नहीं गांव को बचाने की लड़ाई है. ऐसी स्थिति में देश में आर्थिक समानता और वर्गविहीन समाज की बात करना बिल्कुल नाइंसाफी है. गांव के साथ हो रही इस छद्म राजनीति के कुचक्र को तोड़ने के लिए ही इस संग्रह की एक कविता 'जागो-जागो मजदूर किसान'में किसानों और मजदूरों को उद्बोधित करते हुए उसे अपने अधिकारों के प्रति जगाने का काम कवि करता है. यहां कवि की धारणा उन मार्क्सवादियों की तरह नहीं जो भारत में पश्चिमी देश के सिद्धांत के बूते आर्थिक समानता और वर्गविहीन समाज बनाने की बात करता है. कवि की स्पष्टोक्ति है कि इसका समाधान भारतीय दर्शन और चिंतन के आधार पर ही हो सकेगा. इसीलिए तो कवि अपनी कविता में कहते हैं- 'लाल चीन आदर्शन होगा/ न रूसी होगी मेरी पहचान/ कबीर की वाणी में गूंजेगा/ भारत में समाजवाद का ज्ञान.'

इस संग्रह की कविताओं में कवि की वहुविध दृष्टि की झलक मिलती है. गांव के जीवन का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कवि की दृष्टि नहीं पहुंच पाई है. बावजूद इसके गांव की कुछ ऐसी समस्या है जिस ओर कवि की दृष्टि नहीं पहुंच पाई है. उम्मीद है कि भविष्य में कवि का ध्यान उन समस्याओं की ओर भी जाना चाहिए ताकि गांव के वैभव को बचाने की सार्थक पहल की जा सके और गांव की ओर लोगों को लौटने के लिए प्रवृत किया जा सके. इस संग्रह की कविताओं के पीछे कवि का उद्देश्य भी यही है जिसे अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा भी है- 'इस संग्रह की एक भी कविता यदि गांव से पलायन करनेवालों को पुन: गांव की ओर लौटने के लिए प्रवृत कर सकी तो निश्चय ही कविता की प्रयोजनीयता सिद्ध हो सकेगी. इस संग्रह की कविताओं की अन्तर्यात्रा में मैंने अनुभव किया कि गांव को बचाने के लिए सार्थक पहल होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

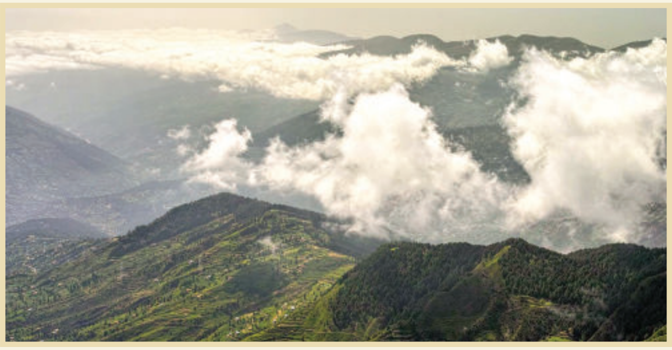

इस क्षेत्र में तीन मीठे पानी के झरने हैं, जो ठंडे पानी के मूल स्रोत हैं. इन झरनों के पानी में औषधीय गुण हैं. ठंड के मौसम के दौरान विभिन्न तरह की बाहरी गतिविधियों, जैसे स्कीइंग और ट्रैकिंग में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पटनीटॉप आते हैं. पटनीटॉप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स, घुड़सवारी और फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है. यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में नाग (कोबरा) मंदिर, बुद्ध अमरनाथ मंदिर, बाहु किला, कुद और शिवगढ़ प्रमुख हैं.

नासिक कुंभ

भारत में स्नान और ध्यान को शुरू से ही काफी महत्व प्राप्त है. भक्त स्नान को पापों से छुटकारा पाने के उत्तम साधन के तौर पर भी देखते हैं. कुछ इन्हीं विश्वासों और परंपराओं को मानते हुए नासिक कुंभ मेले में श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करते श्रद्धालु.

खाना पीना

लाजवाब है काकोरी कबाब

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज भी नवाबों की नगरी के रूप में जानी जाती है. कहा जाता है कि अवध के नवाब स्वादिष्ट खाने के लिये अपनी जान छिड़कते थे. काकोरी कबाब के बिना लखनऊ के कबाब की बात अधूरी लगती है. लखनऊ से 15 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी गांव बसा है, जिसने साहित्य और कविताओं के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जिस तरह काकोरी अपने मलिहाबादी आम के लिये जाना जाता है, उसी तरह वह काकोरी कबाब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. कहते हैं कि काकोरी कबाब की खासियत यह है कि यह इतना मुलायम होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है. आज भी हर रोज़ काकोरी कबाब का जायका चखने हजारों लोग यहां आते हैं. यूं तो काकोरी कबाब से जुड़ी काकोरी कांड से लेकर अवध के नवाब की दावत तक न जाने कितनी कहानियां है, लेकिन असल में पहली बार एक काकोरी बावरची ने मुंह में घुल जाने वाले कबाब अवध के नवाब के फरमान पर बनाया था, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से वो दन्तहीन हो चुके थे, जिससे उन्हें कबाब खाने में दिक्कत होती थी. तभी से इसका नाम काकोरी कबाब पड़ गया. आज भी काकोरी कबाब अपने में नवाबी अंदाज़ को समेटे हुए है.

सामग्री-

500 ग्राम बिना चर्बी का मीट कीमा बनाया हुआ.
3 टेबलस्पून कच्चा पपीता.
1 टेबलस्पून प्याज लंबाई में कटा हुआ.
1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट.
5 टीस्पून बेसन भूना हुआ.
2 टीस्पून गरम मसाला.
80 ग्राम घी.
1 टीस्पून कश्मीरी लालमिर्च पाउडर.
3 टेबलस्पून तेल.
स्वादानुसार नमक.

बनाने की विधि

कीमा को अच्छी तरह धो लें. कच्चे पपीते और प्याज को अदरक, लहसुन के पेस्ट से साथ मिक्सर में पीस लें. इसमें पानी न डालें. तैयार पेस्ट को कीमा में मिलाएं. अब इसमें बाकी बची हुई सामग्री तेल में छोड़कर, उसे मिलाकर 1 घंटे के लिए अलग रख दें. फिर इसका कबाब बनाकर सींक में लगाएं और तंदूर में पका लें. थोड़ी देर पकाने के बाद आंच से उतारकर तेल लगाएं और दोबारा सुनहरा होने तक पकाएं. ■

मुकाम

सोशल मीडिया में करियर बनाएं

टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे ने न सिर्फ लोगों की जीवन शैली में भारी बदलाव किया है, बल्कि इसी से जुड़े ऐसे करियर ऑप्शंस भी सामने रखे हैं, जिनके बारे में आज से कुछ साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा. युवाओं की पहुंच में हर वक्त रहने वाला सोशल मीडिया हो या फिर इन सोशल मीडिया को अपना बनाने वाले नए-नए एप्स, करियर के नए विकल्प तेजी से इनमें अपनी जगह बना रहे हैं. सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से इसके विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है. कई ऐसे नए करियर विकसित हो गए हैं, जिनसे बड़े स्तर पर लोग अभी भी अनजान हैं. सोशल मीडिया में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मियों के लिए गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन व ट्वीटर के अलावा विभिन्न मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों और आईटी क्षेत्र में काम

करने के अच्छे मौके हैं. सोशल मिडिया कोर्स कर के आप मोबाइल एप्लिकेशन मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर बन सकते हैं. अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन इंस्टीट्यूट्स से संबंधित कोर्स कर सकते हैं. साथ ही जरूरी वेबसाइट से भी मदद ले सकते हैं. इंस्टीट्यूट्स और वेबसाइट हैं :

डिजिटल विद्या इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
http://www.digitalvidya.com

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मीडिया, मुंबई
http://nismonline.org

एडिटवर्क्स स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नोयडा
http://www.digitalmarketingpro.co.in

दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, नई दिल्ली
http://dsim.in/

सैर-सपाटा

एडवेंचर्स पसंद है तो जाएं पटनीटॉप

पटनीटॉप जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है. इस स्थान को वास्तविक रूप से पाटन दा तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब. एक कहावत के अनुसार, राजकुमारी नहाने के लिए प्रतिदिन इस तालाब का उपयोग करती थीं. हालांकि कुछ सालों बाद इसका नाम पटनीटॉप हो गया. देवदार के घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां, लुभावने दृश्य और शांत वातावरण पटनीटॉप को पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं. इस क्षेत्र में तीन मीठे पानी के झरने हैं, जो ठंडे पानी के मूल स्त्रोत हैं. इन झरनों के पानी में औषधीय गुण हैं. ठंड के मौसम के दौरान विभिन्न तरह की बाहरी गतिविधियों, जैसे स्कीइंग और ट्रैकिंग में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पटनीटॉप आते हैं. पटनीटॉप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स, घुड़सवारी और फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है. लोकप्रिय पर्यटन स्थानों के अंतर्गत नाग (कोबरा) मंदिर, बुद्ध अमरनाथ मंदिर, बाहु किला, कुद और शिवगढ़ आते हैं.

कब जाएं

वैसे तो आप यहां साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सैर के लिए उपयुक्त समय मई से जून के बीच तथा सितंबर से अक्टूबर के बीच का ही है.

कैसे पहुंचें

पटनीटॉप में हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन नहीं है. फिर भी पर्यटक जम्मू से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. जम्मू रेलवे स्टेशन या जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पर्यटक राज्य परिवहन की बस या किराये की टैक्सी ले सकते हैं. ■

सामान की हिफाजत करेगी एमवाईएनटी डिवाइस

भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम अक्सर अपनी चाबियां, पर्स या दूसरे छोटे-मोटे सामान इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं और फिर उस सामान की जरूरत पड़ने पर परेशान हो जाते हैं. अब एक ऐसी डिवाइस आ गई है, जो इस परेशानी से आपको निजात दिला देगी. यह एमवाईएनटी डिवाइस आपके सामान की हिफाजत करेगी. यह डिवाइस ब्लूटूथ जीपीएस टेक्नोलॉजी के जरिए एक खास मोबाइल ऐप से कनेक्ट रहेगी तथा सर्च करने पर अपनी लोकेशन बताएगी. करीब 2 इंच की इस छोटी सी डिवाइस को उन सभी चीजों के साथ टैग करके रखा जा सकता है, जिनको रखकर आप भूल जाते हैं. इस डिवाइस से जिन चीजों के चोरी होने या खो जाने का डर होता है, उनकी सुरक्षा की जा सकती है. आप इस डिवाइस को कीचेन की तरह चाबियों में भी टैग कर सकते हैं. आप एक ही मोबाइल ऐप के साथ कई एमवाईएनटी डिवाइस को कनेक्ट रख सकते हैं, जिससे चाबी, पर्स, कार, लैपटॉप जैसी छोटी-छोटी चीजें आपकी पहुंच में होंगी. ■

बाज़ार में नया

सियाज डीजल का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च

ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति-सुजुकी ने सियाज डीजल का हाइब्रिड वर्जन बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को सियाज एसएचवीएस के नाम से लॉन्च किया है. सियाज एसएचवीएस हाइब्रिड कार में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेट तकनीक पर काम करेगी. इसमें ऑटोमैटिक स्टार्ट/स्टॉप फंक्शन भी मौजूद होगा. साथ ही कार का माइलेज पहले से और बेहतर होने की बात कही जा रही है. नई हाइब्रिड सियाज का माइलेज 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है. सियाज का मौजूद वेरिएंट 26.21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर का इस्तेमाल, रियर सीट एसी के साथ फुल ऑटोमैटिक एसी की सुविधा मौजूद है. मारुति सियाज के पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल में अलग-अलग वैरियंट मौजूद हैं. मौजूदा पेट्रोल सियाज कार की शुरूआती रेंज 6, 99, 000 लाख रुपये है. इसकी लास्ट कीमत 9,34,000 रुपये है. वहीं डीजल सियाज कार की शुरुआती कीमत 8,04,000 रुपये है. इसकी सबसे अधिक कीमत 9,50,000 रुपये है. ■

एथलीट

अंजू बॉबी जॉर्ज
सर्वश्रेष्ठ भारतीय एथलीट

अंजू ने साल 2003 में विश्व एथलेटिक्स स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं थीं.

अंजू बॉबी जॉर्ज एक पूर्व भारतीय एथलीट हैं. अंजू ने साल 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा था और विश्व एथलेटिक्स स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं थीं. इसके बाद साल 2005 में आईएएएफ विश्व एथलेटिक्स फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता, इस प्रदर्शन को वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानती हैं. हालांकि उन्होंने अपने एथलेटिक्स करियर की शुरूआत हेप्थेलॉन के साथ की थी, लेकिन बाद में उन्होंने लंबी कूद की स्पर्धाओं पर ध्यान केंद्रित करना किया. वर्ष 1996 में दिल्ली जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने लंबी कूद का खिताब जीता. उन्होंने 2002 में मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 6.49 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता. इसके बाद बुसान में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने साल 2003 में एफ्रो-एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीता. साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6.83 मीटर की छलांग लगाई और छठवें स्थान पर रहीं. उन्होंने 2006 में दोहा में आयोजित 15 वें एशियाई खेलों में महिला वर्ग की लंबी कूद में रजत पदक जीता, 2007 में अम्मान (जॉर्डन) में हुई 17 वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू ने 6.65 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता. विश्व रैंकिंग में वह चौथे स्थान तक पहुंच सकीं.साल 2002-2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया. साल 2005 में उन्हें देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया. 2004 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया. ■

एक खेल ऐसा भी

मिज़ोरम का सांस्कृतिक खेल
इंसुकनवर

इंसुकनवर पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम का एक सांस्कृतिक खेल है जो मिजो समुदाय की मुख्य फसल धान से जुड़ा हुआ है. इस खेल में धान की कुटाई के लिए उपयोग में आने वाले मूसल (जिसे मिजों भाषा में सूक भी कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है. इंसुकनवर खेल में युवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं. खेल 16 फुट व्यास के गोलाकार मैदान में खेला जाता है. सूक या मूसल की लंबाई 8 फिट और मोटाई 2.5 से 3 इंच होती है. इसमें दो खिलाड़ी होते हैं. जो एक मसूल के दोनों छोर को अपने हाथ के नीचे(कांख) में दबाते हैं और अपने प्रतिद्विंदी को गोले से बाहर निकालने के लिए जोर लगाते हैं. दोनों में से जो खिलाड़ी गोले से बाहर चला जाता है. वह हार जाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

हॉकी

भारतीय महिला हॉकी टीम को मिला रियो ओलंपिक का टिकट

भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई कर लिया है. लंदन में हुई यूरो हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के पहुंचते ही भारत को ओलंपिक में प्रवेश मिल गया. यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने स्पेन को हराया था जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने जर्मनी को शिकस्त दी थी. फाइनल में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के पहुंचने से एक कोटा स्थान खाली हो गया. ये दोनों ही टीमें पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, इसलिए जुलाई में बेल्जियम के एंटवर्प में महिला हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल्स में पांचवें स्थान पर रही भारत को यह कोटा स्थान हासिल हुआ है. अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ(एफआईएच) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय महिला टीम रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. भारत को हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल्स से क्वालीफाई नहीं करने वाली सबसे बेहतर रैंकिंग वाली टीम के रूप में कोटा मिला है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में रूस के मॉस्को में हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जहां उसे चौथा स्थान मिला था. मॉस्को ओलंपिक में ही भारत के पुरुष हॉकी टीम को आखिरी बार स्वर्ण पदक हासिल हुआ था. भारतीय पुरूष हॉकी टीम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पहले ही रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. भारत के अलावा ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी नौ अन्य टीमें दक्षिण कोरिया, अर्जेन्टीना, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका हैं.■

क्रिकेट

बाइस साल बाद लंका में बजा डंका

नवीन चौहान

युवा कप्तान के नेतृत्व में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया 22 साल बाद श्रीलंकाई धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुई है. इससे पहले श्रीलंका में सन 1993 में मोहम्मद अजहरूद्दीन की कप्तानी में जीत हासिल हुई थी. इसके अलावा यह भारतीय टीम की चार साल बाद विदेशी सरजमीं पर मिली पहली टेस्ट सीरीज विजय है. टीम इंडिया ने साल 2011 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज जीती थी. जो कारनामा महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली जैसे सफलतम भारतीय कप्तान नहीं कर सके, वह कारनामा विराट कोहली और उनकी युवी बिग्रेड ने कर दिखाया है. विराट ने बतौर कप्तान अपने दूसरे विदेशी दौरे में जीत हासिल की है. हालांकि दोनों टीमों के खेल में पुरानी धार नज़र नहीं आई. दोनों ही टीमें बदलाव के दौर से गुजर रही हैं. दोनों ही टीमों में नये खिलाड़ियों की बहुतायत है. ऐसे में भारतीय टीम श्रीलंका के सामने इक्कीस साबित हुई. अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे कुमार संगाकारा का फॉर्म में न होना भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ. यदि उनके बल्ले का जादू सीरीज में चल जाता तो सीरीज की परिणाम कुछ और ही होता. भारतीय टीम भले ही टेस्ट सीरीज जीत गई हो लेकिन टीम में अभी भी बहुत सी कमियां बरकरार हैं.

पहले टेस्ट में हारने के बाद भारतीय टीम कभी भी विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुई थी. यह पहला मौका है जब सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद भी सीरीज 2-1 के अंतर से जीतने में सफल हुई. टीम इंडिया के लिए चौथी पारी में रनों का पीछा करना अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है. खासकर स्पिन गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं. पहले टेस्ट की चौथी पारी में भारतीय टीम 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मजह 112 रनों पर ढेर हो गई. रंगना हीरथ की फिरकी के आगे भारतीय बल्लेबाज असहाय नज़र आये. रंगना ने 48 रन देकर सात विकेट लिए. इससे पहले सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज दिनेश चांदीमल के बल्ले पर लगाम नहीं लगा पाए. चांदीमल की 162 रनों की नाबाद पारी और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ उनकी साझेदारी की वजह से ही भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा. आखिरी के दोनों टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और दोनों ही मैच जीतने में कामयाब हुई. सीरीज के पांच भारतीय बल्लेबाज एक-एक शतक लगाने में कामयाब रहे. कोई भी बल्लेबाज अपनी इस सफलता को दोहराने में कामयाब नहीं हुआ. पहले टेस्ट में शिखर धवन (134) और कप्तान विराट कोहली (103) ने शतक जड़ा. दूसरे टेस्ट से पहले शिखर के चोटिल होने के बाद केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 108 रनों की शतकीय पारी खेली. तो दूसरी पारी में उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 126 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की. वहीं तीसरे टेस्ट में मुरली विजय के चोटिल होने की वजह से लंबे समय बाद अंतिम ग्यारह में शामिल हुए चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 145 रनों की पारी खेल 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीत की नींव रखी. भारत की ओर से बने पांच शतकों में से तीन शतक ओपनिंग बल्लेबाजों ने लगाए.

यह साल 2011 के बाद टीम इंडिया की पहली विदेशी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीत है.

विराट कोहली सबसे कम उम्र में (26 साल,300 दिन)विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

अश्विन ने सीरीज में 21 विकेट लेकर अनिल कुबले के साल 2005 के 20 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

आर अश्विन करियर में चौथी बार मैन ऑफ द सीरीज चुने गए. उनसे ज्यादा बार यह कारनाम सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग (पांच-पांच बार) कर चुके हैं.

ईशांत शर्मा ने श्रीलंकाई कप्तान एंजेलो मैथ्यूज को आउट कर करियर का 200 वां टेस्ट विकेट लिया.

तीनों ही टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की ओपनिंग अच्छी नहीं रही, पहला विकेट बहुत जल्दी गंवा दिया. लेकिन अच्छी बात यह रही कि दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज ने एक छोर थाम लिया और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया. लेकिन जब-जब दूसरा ओपनर भी सस्ते में पैवेलियन लौटा, टीम की हालत पतली हो गई. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में ओपनिंग विकेट जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाए बगैर जीत पाना आसान नहीं होगा. इसके अलावा खिलाड़ियों को इमरान ताहिर की फिरकी का तोड़ ढूंढकर रखना होगा, जिससे कि टीम इंडिया अचानक से स्पिन आक्रमण के आगे ढेर न हो जाए.

केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा की शतकीय पारियों के बाद खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी समस्या खड़ी हो गई है. इसके अलावा कौन सा खिलाड़ी किस क्रम पर खेलगा इसपर भी असमंजस की स्थिति बन गई है. चोट की वजह से टीम से बाहर गए खिलाड़ियों की जगह टीम में आए खिलाड़यों ने हाथ आए मौके का सही फायदा उठाया. ऐसे में रोहित शर्मा के सिर पर एक बार फिर खतरे की तलवार लटकने लगी है. रोहित शर्मा का गैर-जिम्मेदाराना रवैया बदस्तूर जारी है, उनपर

टी-20 और एकदिवसीय मैचों में बल्लेबाजी की खुमारी नहीं उतर रही है. ऐसा लगता है कि उन्हें मैदान में ज्यादा समय गुजरने में आलस आता है. हालांकि रोहित ने सीरीज में दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं. बावजूद उनके अंतिम ग्यारह में बने रहने पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं. रोहित भी युवराज सिंह और सुरेश रैना की श्रेणी के खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जो वन-डे और टी-20 में बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने में असहज दिखाई पड़ते हैं. इस दौरे में विराट कोहली ने जिस तरह की आक्रामक कप्तानी की है, वह काबिले तारीफ है. वह मैच जीतने के लिए ही मैदान में उतरी.सीरीज के दौरान बहुत कम ऐसे सेशन आए जिनमें भारतीय टीम श्रीलंका से पिछड़ती दिखी हो. बल्लेबाजी में असफल रहने के बावजूद उनकी कप्तानी के अंदाज में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था. पहले टेस्ट में असफल रहने के बाद, अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह को बाहर बैठाकर वह तीन तेज गेंदबाजों और दो स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरे, और अपन फैसले को सही साबित किया. पांचों गेंदबाजों ने थके बगैर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारतीय गेंदबाजों ने तीनों ही टेस्ट मैचों में श्रीलंकाई टीम को दो बार पैवेलियन भेजने का कारनामा कर दिखाया. अश्विन ने सीरीज में 21 विकेट लेकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया. वहीं 4 साल बाद टीम में वापसी करने वाले अमित मिश्रा ने 15 विकेट लेकर अश्विन का बेहतरीन तरीके से साथ निभाया और अपनी वापसी को भी सही साबित किया. वहीं ईशांत शर्मा ने सीरीज में 13 विकेट लेकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की और यह बता दिया कि वह टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं.

क्रिकेट में एक नया ट्रेंड सामने आया है कि टीमें घरेलू सरजमीं पर तो आसानी से जीत जाती हैं लेकिन विदेशी धरती पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है. ऐसा हालिया ऐशेज सीरीज में भी देखने को मिला. लेकिन भारतीय टीम ने इस तरह की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए श्रीलंका में जीत हासिल की. भले ही टीम इंडिया को श्रीलंका में आसानी से जीत हासिल हो गई है, लेकिन विराट एंड कंपनी की असली अग्नि परीक्षा तो 2 अक्टूबर से भारत दौरे पर आ रही दक्षिण अफ्रीका के सामने शुरू होगी. अफ्रीकी टीम श्रीलंका से ज्यादा मजबूत और संतुलित है, इसलिए लंका पर जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों को अतिआत्मविश्वास से उबरना होगा और रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, तभी अफ्रीकी शेरों का शिकार कर ढेर करने में कोहली एंड कंपनी सफल हो पाएगी.■

navinonline2003@gmail.com

रंगून में मुख्य भूमिका निभाएंगी कंगना

फिल्म रंगून द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की एक प्रेम कहानी पर आधारित है. फिल्म में तीन मुख्य किरदार हैं, जिनमें से एक मशहूर अभिनेत्री है, दूसरा उनका मेंटोर(मार्गदर्शक) और तीसरा एक सैनिक. फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभा रही कंगना को अपने मेंटोर से प्यार हो जाता है. फिल्म में अन्य दो भूमिकाओं में शाहिद कपूर और सैफ अली खान नज़र आयेंगे.

अभिनेत्री कंगना रनौत अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही हैं. वह अपनी आने वाली फिल्म रंगून के लिए काफी उत्साहित हैं. जाने-माने फिल्मकार विशाल भारद्वाज 1940 के दशक पर आधारित फिल्म रंगून बना रहे हैं. यह फिल्म द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की एक प्रेम कहानी पर आधारित है. फिल्म में तीन मुख्य किरदार हैं, जिनमें से एक मशहूर अभिनेत्री है दूसरा उनका मेंटोर(मार्गदर्शक) और तीसरा एक सैनिक. फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभा रही कंगना को अपने मेंटोर से प्यार हो जाता है. फिल्म में अन्य दो मुख्य भूमिकाओं में शाहिद कपूर और सैफ अली खान नज़र आयेंगे. कंगना खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री साबित कर चुकी हैं. उन्हें फिल्म फैशन और क्वीन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए भी कंगना की खूब तारीफ हुई है. इस फिल्म के अलावा कंगना केतन मेहता की फिल्म रानी लक्ष्मीबाई और हंसल मेहता की सिमरन में भी काम कर रही हैं. उनकी फिल्म कट्टी-बट्टी 18 सितंबर को रिलीज हो रही है. जिसमें उनके साथ इमरान खान काम कर रहे हैं.■

डिवोर्स स्पेशलिस्ट वकील आशिक अली

बतौर डॉयलाग डिलिवरी सहायक के अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने वाले संजय मिश्रा ने बॉलीवुड में असली पहचान अपने हास्य अभिनय से बनाई. लेकिन उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म मसान में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है. लेकिन गंभीर अभिनय से हट के अपने जाने-माने अंदाज में संजय मिश्रा एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने आ रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

संजय मिश्रा बॉलीवुड के उन चुनिंदा हास्य कलाकारों में से एक हैं जिनकी फिल्म में उपस्थिति मात्र से फिल्म का टेस्ट बदल जाता है. उनके अभिनय में वो परफेक्शन है जिसे आप किसी भी सूरत में चाहकर भी नज़र अंदाज नहीं कर सकते हैं. बतौर डॉयलाग डिलिवरी सहायक के अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने वाले संजय मिश्रा ने बॉलीवुड में असली पहचान अपने हास्य अभिनय से बनाई. लेकिन उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म मसान में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है. लेकिन गंभीर अभिनय से हट के पने जाने-माने अंदाज में संजय मिश्रा एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने आ रहे हैं.

फौजिया अर्शी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके किरदार का नाम आशिक अली है जो कि पेशे से वकील है. वह अपना परिचय में डिवोर्स स्पेशलिस्ट, एलएलबी फ्रॉम मार्शल आर्ट बताता है. किरदार का नाम है आशिक अली और काम है तलाक करवाना. इस तरह के विरोधाभास के बीच उनका किरदार बेहद प्रभावशाली नज़र आता है. इससे पहले भी संजय मिश्रा ने कई फिल्मों में वकील का किरदार अदा किया है जिसमें से भूतनाथ रिटर्न उन्होंने ऐसे वकील के रूप में नज़र आए हैं जो कि एक भूत(अमिताभ बच्चन) के चुनाव लड़ने में मदद करता है. फिल्म भूतनाथ का वकील थोड़ा हकीकत से थोड़ा दूर था, लेकिन वहां भी संजय ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया था. लेकिन होगया दिमाग का दही का आशिक अली वकीलों की उस जमात का प्रतिनिधित्व करता है जो पैसे लेकर कोई भी और कैसा भी काम कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. संजय मिश्रा को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई. वह बताते हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते वक्त उनके ज़हन में सत्तर के दशक की हास्य फिल्मों की यादें ताजा हो गईं थीं.

फिल्म होगया दिमाग़ का दही एक कॉमेडी ड्रामा है, इस फिल्म में संजय का साथ कॉमेडी के दिग्गज ओम पुरी, कादर खान, राजपाल यादव, रज्जाक ख़ान, विजय पाटकर और सुभाष यादव जैसे कॉमेडियन दे रहे हैं. ऐसे में उनसे एक बार फिर बेहतरीन अभिनय की आशा की जा सकती है. संजय मिश्रा के मुताबिक जब फिल्म की निर्देशक फौज़िया अर्शी ने उनसे फिल्म में काम करने के लिए संपर्क किया तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही ख्याल आया कि उस वक्त उनके दिमाग में कौन सा दही पक रहा है और कैसा दही बन रहा है.

संजय के प्रशंसकों को उनकी इस नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. होगया दिमाग का दही 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म के टीजर को देखकर तो लगता है कि संजय मिश्रा की ओमपुरी और राजपाल यादव जैसे कॉमेडियन के साथ जुगलबंदी निश्चित तौर पर दर्शकों को हंसा-हंसाकर उनके दिमाग का दही कर देगी.■

feedback@chauthiduniya.com

हल्क ने कहा, मैं बिहारी हूं

हॉलीवुड

हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म श्रृंखला एवेंजर्स में सुपरहीरो हल्क की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मार्क रफ्फालो ने सोलर बिहार परियोजना का समर्थन करते हुए लोगों से स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने का आग्रह किया है. मार्क रफ्फालो ने ट्विटर पर बिहार की परियोजना का समर्थन करते हुए लिखा कि मैं 100 प्रतिशत न्यूयार्कवासी हूं, साथ ही मैं 100 प्रतिशत बिहारी भी हूं. उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर इस अभियान के बारे में ब्लॉग लिखा है. सोलर बिहार एक गैर सरकारी संगठन सोलर विलेज परियोजना का हिस्सा है, जो भारतीय और अफ्रीकी मूल के परिवारों तथा व्यक्तियों को सौर ऊर्जा प्रणाली मुहैया करवाकर, उसके रख-रखाव और इस्तेमाल में मदद करके, उनके जीवन में सुधार करने में मदद कर रहे हैं. मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, विनय पाठक, स्वरा भास्कर, मियांग चांग और नीतू चंद्रा जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी सोलर बिहार परियोजना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है.■

सवाल नंबर-1

फिल्म होगया दिमाग का दही में मिर्जा किशन सिंह जोसेफ कितने धर्मों को मानता है?

A. एक
B. दो
C. तीन
D. चार

अपना जवाब मेल आईडी dailymultimedia1@gmail.com पर मेल करें सबजेक्ट Hogaya Dimaagh Ka Dahi QUIZONE (ऑप्शन A/B/C/D) शहर का नाम लिखें या मोबाइल नंबर पर 072104-38230 QUIZONE (स्पेस) (ऑप्शन A/B/C/D) जवाब मैसेज करें.

नोट

1. दो लकी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में होगया दिमाग का दही फिल्म के दो टिकट मिलेंगे.
2. विजेता का फैसला लकी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा.
3. फिल्म का टिकट आपके नजदीकी पीवीआर/ फन सिनेमा का दिया जाएगा.
4. आपका जवाब हमें 20 सितंबर,2015 को रात 12 बजे से पहले मिल जाना चाहिए.

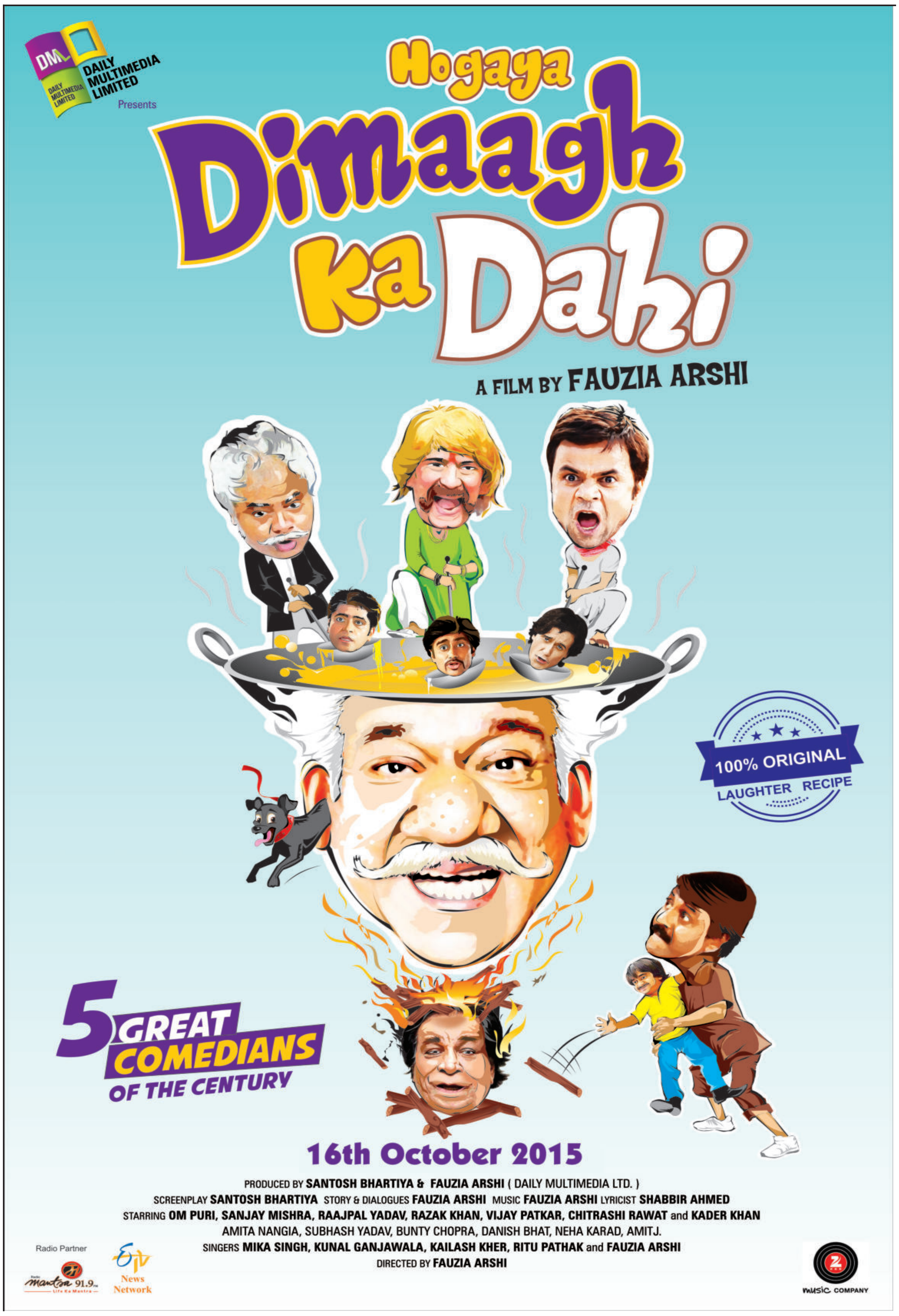

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
बिहार-झारखंड
14 सितंबर-20 सितंबर 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

समधियाने से ज्यादा, कांग्रेस में खलबली

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

महागठबंधन बनने के साथ ही इसके टूटने की आशंकाएं लगातार जाहिर की जाती रही हैं. समाजवादी पार्टी ने इससे खुद को अलग कर बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है. मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि सीटों के बंटवारे में 40 सीटें न देकर 28 सीटें ही दी जाएं. वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि आसन्न चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का असर यूपी चुनाव में भी पड़ सकता है. इसलिए वे कांग्रेस को उसकी हद में रखना चाहते थे. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. मुलायम ये भी जानते हैं कि बिहार के चुनाव से उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. इन सारी बातों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन से हटने में ही भलाई समझी. आइए महागठबंधन की टूट की वजहों की पड़ताल करते हैं...

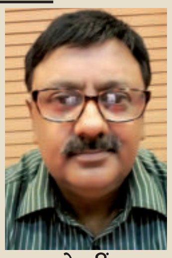
सरोज सिंह

बिहार में अलग चुनाव लड़ने के समाजवादी पार्टी के फैसले ने उन तमाम आशंका जताने वालों को सच साबित कर दिया जो बार-बार जनता परिवार की एकता की सफलता को लेकर बहुत आशान्वित नहीं थे. ऐसा कहा जा रहा था कि इतिहास अपने आप को दोहरायेगा और समाजवादी लोग अपनी-अपनी राह पकड़ लेंगे. लेकिन झटके इतने जल्दी लगने शुरू हो जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था. जिस दिन लालू और नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया उसी दिन से यह लगने लगा था कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. आप सब को याद होगा कि इस दिन सपा को सीट देने के सवाल पर लालू प्रसाद ने कह दिया था कि समधियाने की बात है, उन्हें तो हम अपनी सीट दे देंगे. लेकिन बात इतनी हल्की भी नहीं थी. जानकार सूत्र बताते हैं कि सपा की ओर से गंभीरतापूर्वक 12 सीटों की मांग रखी गई थी. सपा भी चाहती थी कि 100 सीटों पर जदयू और इतनी ही सीटों पर राजद चुनाव लड़े. 28 सीट कांग्रेस को और 12 सीट सपा को दिया जाए और एनसीपी को तीन सीट पर लड़ने को कहा जाए. सपा का आकलन था कि कांग्रेस को ज़रूरत से ज्यादा सीटें देने का नुकसान देर-सवेर यूपी के चुनाव में सपा को हो सकता है. इसलिए सपा हमेशा इस बात की पक्षधर रही कि कांग्रेस का कद छोटा रखा जाए. कमोवेश लालू भी यही चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार और राहुल गांधी की नई दोस्ती ने जनता परिवार की बुनियाद को हिला कर रख दिया. कांग्रेस को इतनी सीट मिल गई जितने की उम्मीद सही मायनों में उसे भी नहीं थी. इस तरह के फैसले से मुलायम सिंह इतने नाराज़ हुए कि वह स्वाभिमान रैली में नहीं आए. जानकार बताते हैं कि सपा के लिए दो चार सीट कम-ज्यादा पर भी मुलायम सिंह मान जाते लेकिन कांग्रेस को चालीस सीट देने के फैसले से वह बेहद ख़फ़ा हो गए. मुलायम सिंह के लिए बिहार चुनाव से कहीं ज्यादा यूपी का संग्राम मायने रखता है इसलिए कांग्रेस का फैलाव उन्हें रास नहीं आया. मुलायम सिंह जानते हैं कि बिहार में उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं है. बिहार का चुनावी रिकॉर्ड सपा के लिए उत्साहवर्धक नहीं रहा है. 2010 के चुनाव में सपा 146 सीटों पर लड़ी थी पर किसी उम्मीदवार की ज़मानत नहीं बच पाई थी. उसके सभी प्रत्याशियों को औसत 1101 वोट मिले थे. कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को 1,60,848 वोट मिले. बिहार विधानसभा में सपा इस लिहाज़ से हमेशा अभिशप्त रही कि जीतने के बाद उसके ज्यादातर विधायक पाला बदलते रहे. बिहार में सपा 1995 के चुनाव मैदान में कूदी थी. उस समय सपा के 176 उम्मीदवार मैदान में थे. उनमें दो विजयी रहे. एक की ज़मानत बची और बाकी की ज़मानत ज़ब्त हो गई. इस अनुभव से सपा ने अगले चुनाव में केवल छह प्रत्याशियों को खड़ा किया जिसमें उसके दो प्रत्याशी जीत गए. इस बार भी सपा कुछ कम-ज्यादा में मान जाती पर कांग्रेस का गुस्सा उन्होंने जनता परिवार पर उतार दिया. मुलायम नहीं चाहते हैं कि यूपी के चुनाव में उन्हें कांग्रेस, राजद या फिर जदयू के लिए सीटों का बंटवारा करना पड़े. मुलायम सिंह को यह डर सताने लगा कि अगर चालीस में से कांग्रेस अगर आधी सीटें भी बिहार में जीत गई तो यूपी के चुनाव में उसके तेवर बदले हुए रहेंगे. दो साल बाद मुलायम इस सकंट को सामने आने ही नहीं देना चाहते हैं. इसके अलावा सपा के थिंक टैंक ने यह हिसाब लगाया कि अगर बिहार के चुनाव में महागठबंधन की जीत होती है तो नीतीश और लालू एक बार फिर मजबूत नेता के तौर पर उभर जाएंगे जो राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर मुलायम सिंह के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं. उम्र के लिहाज़ से देखा जाए तो मुलायम शायद 2019 के बाद का लोकसभा चुनाव न लड़ें इसलिए तैयारी यह है कि 2019 की विघ्न-बाधाओं को अभी से ही दुरुस्त करते हुए चला जाए ताकि उस समय अनावश्यक परेशानी पैदा न हो. राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर मुलायम वामदलों की भी भूमिका देखते हैं पर महागठबंधन में वामदलों को कोई जगह नहीं दी गई. यह परिस्थिति भी मुलायम को सूट नहीं कर रही थी. अब जब सपा ने अलग रास्ता ले लिया है तो ऐसे में वामदलों से सामंजस्य बैठाने की वह पूरी कोशिश करेंगे. बिहार में लालू प्रसाद को अपनी हद में रखने के लिए मुलायम सिंह पप्पू यादव की भी पीठ ठोंक सकते हैं और इसके लिए तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर सकते हैं. महागठबंधन से नाराज़ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी साथ लेने का प्रयास मुलायम सिंह शुरू कर चुके हैं. सारी कोशिश यह है कि राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर अभी से ही सारे मोहरों को बारीकी से सजाया जाए. बिहार के चुनाव से मुलायम सिंह और उनकी पार्टी का कुछ बनना-बिगड़ना नहीं है. लेकिन इस चुनाव का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति के लिए करने के वास्ते महागठबंधन से नाता तोड़ना मुलायम के लिए ज़रूरी हो गया था और सही समय पर मुलायम ने यह फैसला ले लिया. अब अगर कोई पैचअप होगा तो वह कांग्रेस की सीटों की कीमत पर ही होगा वरना मुलायम ने तो अपना रास्ता तय कर ही लिया है.■

राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर मुलायम वामदलों की भी भूमिका देखते हैं पर महागठबंधन में वामदलों को कोई जगह नहीं दी गई. यह परिस्थिति भी मुलायम को सूट नहीं कर रही थी. अब जब सपा ने अलग रास्ता ले लिया है तो ऐसे में वामदलों से सामंजस्य बैठाने की वह पूरी कोशिश करेंगे. बिहार में लालू प्रसाद को अपनी हद में रखने के लिए मुलायम सिंह पप्पू यादव की भी पीठ ठोंक सकते हैं और इसके लिए तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर सकते हैं. महागठबंधन से नाराज़ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी साथ लेने का प्रयास मुलायम सिंह शुरू कर चुके हैं. सारी कोशिश यह है कि राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर अभी से ही सारे मोहरों को बारीकी से सजाया जाए.

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी
टिकट का विकट खेल

पूर्वी चंपारण की 12 विधान सभा सीटों के टिकट के लिए संभावित प्रत्याशियों में घमासान जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी टिकट को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा है. सभी अपने नेता को लुभाने में लगे है. टिकट के इस घमासान में ऐसे नेताओं की बल्ले-बल्ले है जिनकी थोड़ी बहुत भी पहुंच पटना के राजनीतिक गलियारों में है. एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के साथ ही अन्य पार्टियों का टिकट दिलाने का दावा करने वाले ठेकेदारों की बाढ़ आ गई है. ऐसे में कुछ भावी प्रत्याशी टिकट के लोभ में जानबूझ कर फंस रहे हैं तो कुछ अनजाने में शिकार बन रहे हैं. क्षेत्र से पटना तक के नियमित दौरे चल रहे हैं.

पार्टी, कार्यकर्ता और समाज पर ढीली पकड़ रखने वाले धन बल पर शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्षी को पटखनी दे सकने की क्षमता ही टिकट बंटवारे का इकलौता मापदंड है. इसका बड़ा असर यह पड़ सकता है कि बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की बाढ़ आ सकती है.

महागठबंधन के दलों ने स्वाभिमान रैली में पार्टी से टिकट चाहने वालों का शक्ति परीक्षण किया. टिकट मांगने वालों को रैली में अपना दमखम दिखाने का फरमान दिया गया. वहीं भाजपा गठबंधन के नेता क्षेत्र में सभा करके उम्मीदवारों की शक्ति का आकलन कर रहे हैं. लगातार भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा जारी है. पिछले दिनों गोविंदगंज विधान सभा क्षेत्र में सुशील कुमार मोदी का दौरा हुआ. इस दौरान भाजपा के भावी प्रत्याशियों सहित गठबंधन के अन्य दलों के भावी उम्मीदवारों के बीच शक्ति प्रदर्शन का ऐसा दौर चला कि आपसी फूट धरातल पर आ गई. भाजपा के प्रबल दावेदारों में रवि शंकर पांडेय और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील मणि तिवारी ने अपने समर्थकों की भीड़ जुटाकर मजबूत पकड़ का एहसास दिलाया. लेकिन गठबंधन की अंतर्कलह साफ झलकी. लोजपा के नेता और प्रबल दावेदार राजू तिवारी को सभा की सूचना भी नहीं दी गई थी. हालांकि राजू तिवारी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ सम्मिलित हुए. राजू तिवारी का नाम तक संबोधन में नहीं लिया गया. इस बाबत स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि सुशील मोदी के आने की ख़बर की सूचना राजू तिवारी को खुद लेनी चाहिए थी.

रविशंकर पाडेय

सुनील मणि तिवारी

ज्ञात हो कि गोविंदगंज क्षेत्र से जदयू की मीना द्विवेदी विधायक हैं. बीते चुनाव में यह सीट भाजप-जदयू गठबंधन के तहत उन्हें मिली थी. लेकिन इस बार पासा पलट गया है. भाजपा के साथ लोजपा है तो जदयू के साथ राजद का गठबंधन है. पिछली बार लोजपा-राजद गठबंधन के तहत राजू तिवारी ने चुनाव लड़ा था.

हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां आए थे. यह एक मौका था महागठबंधन के भावी प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन का. जदयू के प्रबल दावेदार रतन सिंह बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शरीक हुए. वहीं काग्रेस के दावेदार जय प्रकाश पांडेय ने भी शक्ति प्रदर्शन किया. जदयू विधायक मीना द्विवेदी के समर्थकों ने भी अपना दम दिखाने का प्रयास किया.

गोविंदगंज से दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित चन्द्रकिशोर मिश्र, मुन्ना गिरी और पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद दावेदारी कर रहे थे. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संवाद के बाद इनकी दावेदारी फिकी पड़ गई है. इधर कांग्रेस नेता ई. गप्पू राय उर्फ शशि भूषण राय भी दावेदार हैं. अरेराज नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके मंटू दुबे राजद के प्रबल दावेदार हैं. उनकी नजदीकियां हम के साथ भी बताई जाती हैं. यह तो एक बानगी है. लगभग सभी विधान सभा क्षेत्रों का यही हाल है. जिले के चार विधायकों के टिकट पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं? इसकी पुष्टि स्वयं विधायकों के बयानों से हो रही है कि अगर पार्टी उन्हें संगठन के काम में लगाती है तो वे आदेश का पालन करेंगे. ये बयान अंगूर खट्टे होने जैसा ही कहें जाएंगे.■

- राकेश कुमार

एक नज़र

चुनावी हलचल

बदलाव का मिल रहा संकेत : पंकज

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा के संभावित प्रत्याशी पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि अबकी बार क्षेत्र से बदलाव का संकेत आने लगा है. सूबे बिहार की सरकार का शासन अब लोगों को रास नहीं आ रहा है. विकास के नाम पर चारों ओर सरकारी खजाने की लूट मची है. जनता की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है. प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि केंद्र की सरकार ने अब ठान लिया है कि हर हाल में बिहार की सूरत को संवारा जायेगा. उन्होंने भरोसे भरे लहजे में कहा कि एनडीए गठबंधन के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ी है. 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव नया सवेरा लेकर आने वाला है. **– विभा**

धोखेबाजों का गिरोह है एनडीए : सुनील

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के संभावित युवा प्रत्याशी सह जिला राजद महासचिव सुनील कुमार यादव ने कहा कि एनडीए धोखेबाजों का गिरोह है. पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आम जनता से जो वादा किया था वह झूठा साबित होकर रह गया है. अबकी बार सूबे बिहार की जनता किसी धोखा में नहीं पड़ने वाली है. उन्होंने कहा कि रुन्नीसैदपुर के विकास के लिए इस बार जनता ने चुनाव में आने का न्योता दिया है. खास कर युवा मतदाता की मंशा है कि राजद के पक्ष को मजबूती के साथ जनता के बीच रखा जाये. उन्होंने कहा कि मौका मिलता तो क्षेत्र को विकास के शीर्ष पर स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. **– विकास**

फ्रेशर डे आयोजित

पटना के स्थानीय महंत हनुमंत शरण कॉलेज,राजापुर-मैनपुरा के प्रांगण में निर्मित प्रेमचन्द रंगमंच पर इंटर द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं ने शिक्षा जगत में वर्षों से चली आ रही एक आदर्श परंपरा को कायम रखते हुए नये नामांकित छात्र-छात्राओं के स्वागत फ्रेशर डे का आयोजन किया. इसका उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य तथा कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से किया. उक्त अवसर पर छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया. राजधानी के पिछड़े एवं कस्बाई इलाके में होने वाले उक्त आयोजन का कॉलेज से बाहर के लोगों ने भी खुलकर तारीफ की. प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास के प्रति संतोष जाहिर किया. उक्त अवसर पर पान बनारसवाला तथा मेरे सपने दुपट्टा जैसे गानों पर छात्र-छात्राओं का धमाल व मस्ती देखने लायक था. उक्त अवसर पर प्रो. आर.एस. तिवारी, प्रो. बी.के. राय, प्रो सी.सी. सिंह, प्रो. रंजना कुमारी, प्रो.संजय ठाकुर, प्रो. पंकज कुमार, प्रो.सरिता सिन्हा, सीएनआर्य, उपेन्द्र कुमार, मनोज कुमार, प्रो.नवीन कुमार, प्रो. अजय कुमार आजाद, प्रो. भूपेन्द्र कुमार, रीना सिन्हा, सुबोध कुमार, प्रो. गुलाम रब्बानी, डॉ. उर्मिला कुमारी, प्रो. धर्मनाथ सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिंह, योगेन्द्र शर्मा, मीनू, बिनोदेश्वर प्रसाद, रामाशीष ठाकुर इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किए. **– भारती**

निदान के बाद होगा मतदान : मनोज

सीतामढ़ी जिला भाजपा क्रीड़ा मंच के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार शक्ति ने कहा कि अबकी बार चुनाव का अंदाज निराला होगा. लोहापट्टी स्थित अपने आवास पर कहा कि अब तक स्थानीय समस्या के निदान को लेकर प्रतिनिधियों की नींद नहीं खुल रही थी. जब चुनाव का समय आया है तो सभी जाति व पार्टी का झंडा लहराने में लग गये हैं. उन्होंने कहा कि इस साल विधानसभा चुनाव से पूर्व जिला में समस्या निदान को लेकर लोग एकजुट होने लगे हैं. लोगों का नारा है कि – पहले समस्या का निदान, फिर करेंगे मतदान. मनोज ने कहा कि शहर में अतिक्रमण, नाली, लखनदेई नदी सभी बड़ी समस्या वर्षों से गंभीर चुनौती बनी है. परंतु निदान की दिशा में किसी का ध्यान नहीं है. **– ब्रजेश**

मूत्र संबंधी रोगों में बरतें सावधानी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo-XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL-D Cap Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

शिद्दत से याद किए गए साहित्य के सिपाही

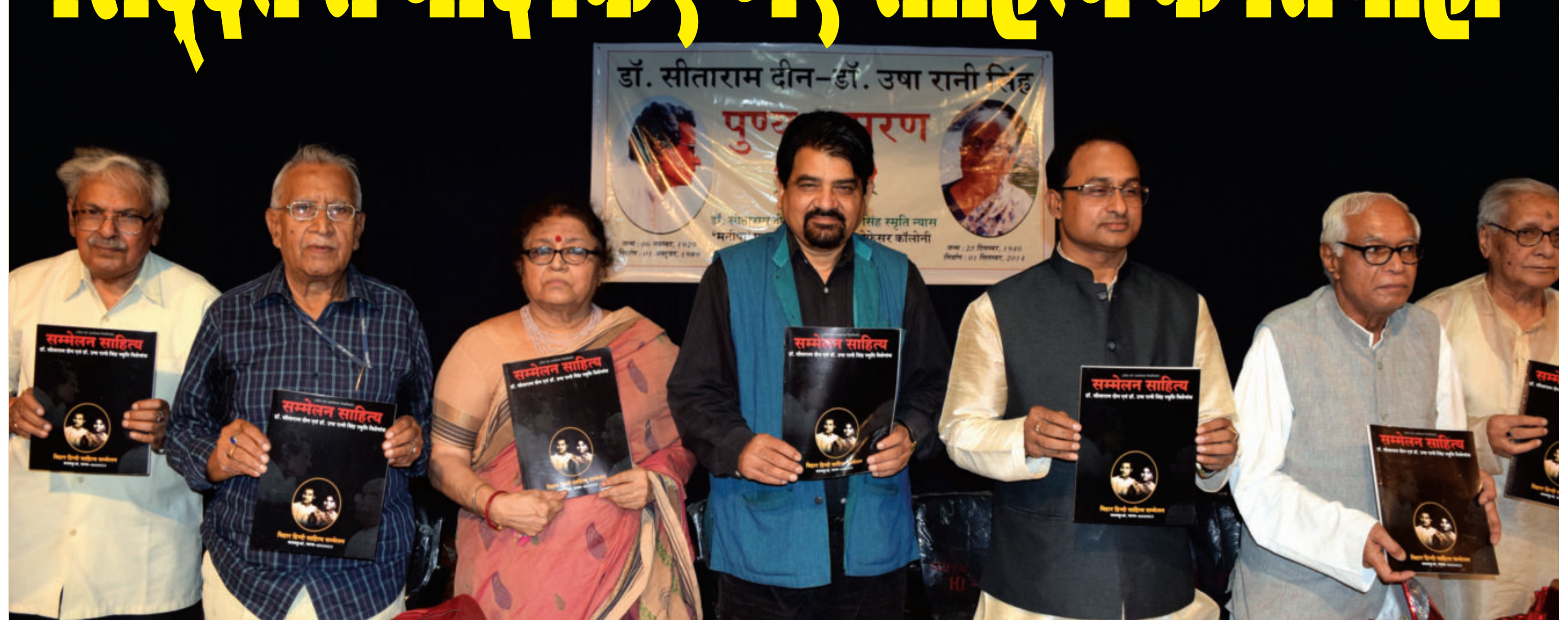

समारोह की अध्यक्षता हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने की. कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. सीताराम दीन और डॉ. ऊषा रानी सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया. इसके बाद शास्त्रीय संगीत की गायिका डॉ. रेखा दास और डॉ. रीता दास ने कबीर के भजनों से श्रोताओं को भक्ति और भावुकता से सराबोर कर दिया. 'हरि तुम हरो जन की पीड़ा, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीड़' समेत एक से बढ़कर एक कई सुरीले भजनों से दोनों बहनों ने श्रोताओं का मन मुग्ध कर दिया.

दिव्या त्रिपाठी

पटना का कालिदास रंगालय साहित्यकारों की भावनाओं के निश्छल उद्गार का गवाह बना. मौका था डॉ. सीताराम दीन और डॉ. ऊषा रानी सिंह के पुण्य स्मृति कार्यक्रम का. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय भी उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन डॉ. सीताराम दीन-डॉ. ऊषा रानी सिंह स्मृति न्यास की ओर से किया गया. समारोह की अध्यक्षता हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने की.कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. सीताराम दीन और डॉ. ऊषा रानी सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलीत कर किया गया. इसके बाद शास्त्रीय संगीत की गायिका डॉ. रेखा दास और डॉ. रीता दास ने कबीर के भजनों से श्रोताओं को भक्ति और भावुकता से सराबोर कर दिया. 'हरि तुम हरो जन की पीड़ा, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीड़' समेत एक से बढ़कर एक कई सुरीले भजनों से दोनों बहनों ने श्रोताओं का मन मुग्ध कर दिया. उनके साथ तबले पर शांतनू रॉय और हॉरमोनियम पर देवानंद ठाकुर थे. वहीं हृदय नरायण झा ने भोजपुरी और मैथिली में कबीर के भजन पर डॉ. सीमांचल दास ने भक्ति गीतों को गाकर इस शाम को यादगार बना दिया.

भजन के बाद डॉ. दीन के विचारों एवं व्यक्तित्व पर चर्चा हुई. मुख्य अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने कहा कि डॉ. सीताराम दीन तथा डॉ. ऊषा रानी दीन साहित्य सेवी थे. कबीर से भी उनका गहरा लगाव था और जिस व्यक्ति को कबीर अच्छा लगे वो औघड़ ही होता है. उन्होंने कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं यह कामना

करता हूं कि यह आयोजन हर साल हो और इन पुण्य आत्माओं को हर साल याद किया जाय. इस सामरोह में आए लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि श्री दीन की किताबों को देखकर यह एहसास हो रहा है कि कितनी मुफलिसी से इनका प्रकाशन किया गया है, लेकिन अक्सर बड़े लोग इसी मुफलिसी में ही बड़े बनते हैं. उनके कामों को लोग याद रखते हैं और जिस तरह से लोगों ने यहां मौजूद होकर उनका सम्मान बढ़ाया है, वह तारीफ के काबिल है. कवि सत्यनरायण ने डॉ. दीन के साथ अपनी यादों को साझा करते हुए कहा कि ऐसा नहीं कि वो आज उपस्थित नहीं हैं. उनके शब्द आज भी हमारी यादों उनकी मौजुदगी को बनाए रखते हैं. साथ उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. दीन एक फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे. वे किसी दायरे में बंध कर नहीं रह सकते थे. उनके निधन के पश्चात उनके आदर्शों और उनके साहित्य के प्रति लगाव को उनकी उनकी पत्नी ऊषा रानी सिंह ने बखूबी निभाया. दीन जी का यह विश्वास था कि कोई साथ दे या न दे फूल की पंखुड़िया और बारिश की बूंदें उनकी व्यथा-कथा जरूर सुनेंगी. उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं डॉ दीन और डॉ ऊषा रानी सिंह को इस सभागार में उपस्थि त सभी लोगों के सामने अपना प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता रहे. डॉ. ऊषा जी जी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वे हिन्दी गीत की बहुत संवेदनशील कवियत्री थीं जिनकी रचना आज भी हमारी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती है. संपादक संतोष भारतीय के कहे कुछ शब्दों को उनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार और साहित्यकार का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है.

उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रभात रंजन जी ने यह बीड़ा उठाया है. डॉ दीन और डॉ ऊषा आज हमारे बीच नहीं है लेकिन आज उनकी बातें हमें जीना सिखा जाती हैं जो दोनों कि उपस्थिति हमारे बीच कायम रखती है.यह आयोजन हम साहित्यकारों को एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है. प्रो. ऊषा किरण खान ने डॉ. ऊषा रानी को गहराई से अध्ययन करने वाली बताया. उनके साथ ही साहित्यकार आचार्य श्रीरंजन सूरीदेव, सियाराम तिवारी ए मेजर बलबीर सिंह भसीन प्रो. अमरनाथ डॉ. शोभित प्रसाद सिंह समेत कई हस्तियां मौजूद थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

धमदाहा विधानसभा

चुनावी समर पर दिग्गजों की नज़र

नीरज सिंह

पूर्णिया का धमदाहा क्षेत्र अक्सर भूमि विवादों बिहार में कुख्यात रहा है, जहां आम आदमी तो क्या प्रशासन के लोग भी रात के अंधेरे में जाने से कतराते थे. लेकिन बदलते परिवेश में सड़क इत्यादि बनने से यहां के हालात में सुधार आया. पूर्व में कभी धमदाहा कांग्रेस की परंपरागत सीट थी. इसके बाद नब्बे के दशक से यहां पारंपरिक मुकाबला जदयू और राजद के बीच होता रहा है. यहां से वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह विधायक हैं. वर्तमान में यह सीट जहां महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं एनडीए गठबंधन के लिए भी महत्व-पूर्ण है. जिसमें सेंधमारी को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की तरफ से राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है. विधान परिषद चुनाव में पूर्णिया-कटिहार सीट भाजपा की झोली में चले जाने से जहां भाजपा के हौसले बुलंद हैं. दूसरी तरफ पूर्व सासंद और भाजपा के मजबूत नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह लोकसभा चुनाव में जदयू के हाथों पराजित होने से नीतीश कुमार एवं लेसी सिंह से खार खाए हुए हैं. पप्पू सिंह ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हैं जिसके तहत उनकी योजना सीमांचल में विधानसभा चुनाव में जदयू-राजद-कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने नहीं देने की है. जदयू राजद कांग्रेस का महागठबंधन बनने के कारण नई रणनीति के तहत धमदाहा के पूर्व राजद विधायक दिलीप यादव पाला बदल कर भाजपा में चले गए हैं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से धमदाहा की जदयू विधायक और नीतीश सरकार की कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह को धमदाहा से जदयू की तरफ से पुनः टिकट मिलना तय है. मधेपुरा सांसद पप्पू यादव का कोसी के इलाके में खासा प्रभाव है और अब वे लालू-नीतीश का जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं कोसी इलाके के एक बाहुबली क्षत्रप आनंद मोहन सिंह व उनकी पत्नी लवली आनंद जीतन राम मांझी के 'हम' के साथ हो गए हैं जिससे एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है. यहां यादव-महादलित-राजपूत वोटरों का एक नया समीकरण भी बना है जिससे नये राजनीतिक परिणाम भी निकलने वाले हैं. मिली जानकारी से विगत 2010 के चुनाव में गठबंधन के कारण जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह को भाजपा और पूर्णिया सांसद उदय सिंह का भरपूर सहयोग मिला था. बड़हरा कोठी प्रखंड की धमदाहा से हटने से ब्राम्हण राजपूत, यादव मतदाता घटे हैं वहीं कोयरी मुस्लिम मतदाताओं में वृद्धि हुई है. धमदाहा सीट पर मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ भाजपा से प्रमुख रूप से दो दावेदार दिलीप यादव, एवं ज्योति रानी हैं तो रालोसपा की तरफ से निरंजन कुशवाहा की दावेदारी है. विदित हो कि दिलीप यादव धमदाहा से राजद के टिकट पर दो बार 2000 एवं 2005 में विधायक चुने गये थे और लेसी सिंह के चिर प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. दिलीप यादव से राजद से भाजपा में जाने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है. नरेन्द्र मोदी में, भारत के लोगों का विश्वास बढ़ा है. नरेन्द्र मोदी सुशासन के प्रतीक एक विकास पुरुष हैं और विदेशों में भारत के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाया है.

दिलीप यादव | ज्योति रानी | लेसी सिंह | निरंजन कुशवाहा | पप्पू यादव

नरेन्द्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में आया जबकि लालू यादव सुशासन के कभी प्रतीक नहीं रहे हैं सत्ता के लालच में उन्होंने खुद यादवों को हाशिये पर ला दिया और सबसे अधिक यादवों को प्रताड़ित करने का कार्य उन्हीं के द्वारा हुआ है. भाजपा को लालू यादव सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं जबकि सबसे बड़े सांप्रदायिक वे लोग हैं जो सांप्रदायिकता का जहर घोल कर वोट मांगते हैं. नीतीश कुमार ने 17 सालों तक भाजपा से गठबंधन करके राज किया और लालू राज को जंगल राज बता कर सत्ता पर काबिज रहे. आज नीतीश कुमार उन्हीं लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर चुनाव की नैया पार करना चाहते हैं. मैंने राजनीति में लालू यादव को कभी धोखा नहीं दिया लेकिन उन्होंने ही मुझे हाशिये पर ला दिया. स्पष्ट है कि अब सिद्धांत की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और अब राजनीति में कोई किसी का स्थाई दोस्त नहीं होता है और न ही स्थायी दुश्मन. धमदाहा से चुनाव लड़ने के बारे में उनका कहना था कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और भाजपा आलाकमान के निर्णय का पालन करूंगा. धमदाहा से भाजपा के टिकट की दूसरी प्रमुख दावेदार जिला परिषद सदस्य सह पूर्णिया जिला भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योति रानी हैं. जानकारी के अनुसार ज्योति रानी ने राजनीति में पहला कदम पूर्णिया जिला परिषद के चुनाव में रखा और क्षेत्र संख्या 10 से बतौर जिला परिषद सदस्य चुनी गईं. मृदुभाषी ज्योति पढ़ी-लिखी शिक्षित महिला हैं और पूर्णिया भाजपा की प्रखंड प्रवक्ता हैं. जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में उनकी पकड़ अच्छी है. ज्योति रानी भाजपा सांसद उदय सिंह के विश्वासपात्रों में से एक है और लेसी सिंह की राजनीतिक विरोधी हैं. नरेन्द्र मोदी और भाजपा के बारे में उनका कहना है कि नरेन्द्र मोदी सुशासन के प्रतीक हैं और उनके नेतृत्व में विदेशों में भारत का मान और गौरव बढ़ा है. नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार समेत पूर्णिया में पुनः जंगलराज कायम हो गया है. अफसरशाही बेलगाम है और नित्य अपराधिक घटनाएं घट रही हैं. मंत्री होते हुए भी धमदाहा अभी भी विकास की रोशनी से काफी दूर है. बिहार का विकास तभी संभव है, जब केन्द्र के साथ बिहार में भाजपा की सरकार बने. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संगठन सचिव निरंजन कुशवाहा धमदाहा से पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं. अपनी दावेदारी को लेकर उनका कहना है कि धमदाहा के नगर प्रखंड से जुड़ने से राजनीतिक समीकरण रालोसपा के पक्ष में हैं. पूरे पूर्णिया एवं कोसी क्षेत्र में एनडीए गठबंधन में रालोसपा को अगर कोई सीट चाहिए तो वह धमदाहा है. यहां के किसानों की समस्या को लेकर रालोसपा हमेशा लड़ाई लड़ती रही है. मंत्री लेसी सिंह के समर्थकों का कहना है कि मंत्री ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर विकसित धमदाहा तैयार किया है. मंत्री ने धमदाहा के लिए जितने काम किये हैं उसके सामने वर्तमान विधानसभा चुनाव में कोई टिकेगा ही नहीं.■

feedback@chauthiduniya.com

सीवान

देशरत्न की धरती पर बढ़ी राजनीतिक हलचल

बाबू राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि विकास से दूर

इस बार के विधानसभा चुनाव में राजग व महागठबंधन द्वारा इस सीट पर अपना कब्जा जमाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है. भाजपा द्वारा अपनी मंडलस्तरीय बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने में पूरी ताकत लगा दी गई है, वहीं जदयू के नेता घर-घर दस्तक के अलावा अन्य कई अभियान चला रहे है. ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन जनता की चुप्पी के सामने सभी दलों के नेताओं व संभावित उम्मीदवारों की एक नहीं चल रही है. इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र में जो प्रमुख चुनावी मुद्दे होगें, इनमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लचर विद्युत आपूर्ति में सुधार, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तथा मैरवा को अनुमंडल बनाने की मांग आदि शामिल है.

शंभू प्रसाद अभय/बाबर अली

विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बढ़े राजनीतिक तापमान की वजह से देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों के सभी संभावित उम्मीदवार जनता के बीच जाकर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं. हालांकि इसका कोई खास असर वहां की जनता पर नहीं पड़ रहा है. इसका कारण है कि राजेन्द्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई की हर सरकार द्वारा कि गई अनदेखी और इस बात को लेकर मतदाताओं में काफी रोष है. मतदाताओं का कहना है कि सभी लोग डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को जयंती व पुण्यतिथि पर ही याद करते हैं, लेकिन उनकी जन्मस्थली के विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता हैं. स्वास्थ्य सेवा के नाम पर 1957 में राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी के द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की गई. राजेन्द्र बाबू दमा रोग से पीड़ित थे. उनके लिए यहीं से दवा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जाती थी. यह औषधालय भी आज बदहाल है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. यहां बिजली की स्थिति भी काफी खराब है. जीरादेई की मुख्य सड़क आज भी 10 फिट की है, जिसका दोहरीकरण का कार्य नहीं हो सका. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर जीरादेई से चलने वाली सरकारी बसें लगभग एक दशक पूर्व ही बंद हो गई, वर्ष 1983 के आसपास यहां बिहार टूरिज्म का एक कार्यालय भी खुला था, जो 1990 के आसपास बंद हो गया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर द्वारा जीरादेई में राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं. जिसमें की राजेन्द्र बाबू की स्मृतियों को सजोंया जा सके. वर्ष 2005 में जीरादेई प्रखंड बना, लेकिन आज तक भवन नहीं बना, थाना भी अस्पताल भवन में चलता है. वर्ष 2010-11 के बीच में राज्य सरकार नें पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की जो आज तक पूरा नहीं हो सका. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 अक्टुबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर यह घोषणा की गई कि देशभर के सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे तथा इसे सांसद आदर्श ग्राम बनाने का कार्य करेंगे. प्रधानमंत्री के इस घोषणा के आलोक में स्थानीय भाजपा सांसद ओमप्रकाश यादव ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक गांव जीरादेई को गोद तो जरूर लिया, लेकिन विकास के नाम पर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है.

जीरादेई सीट पर कांग्रेस पांच बार, राजद व निर्दलीय दो-दो बार, एस.यूए, जेडीयू, जेएनपी व बीजेपी एक-एक जीत दर्ज करा चुकी है. वर्तमान में जीरादेई सीट पर बीजेपी का कब्जा है, आशा पाठक यहां से विधायक है, 2010 चुनाव में भाकपा के अमरजीत कुशवाहा यहां दूसरे स्थान पर रहे. भाजपा से आशा पाठक की इस बार भी चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है. वहीं भाकपा के अमरजीत कुशवाहा भी चुनाव लड़ सकते है. उधर भाजपा के राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह भी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने में जुटे हैं. पूर्व मंत्री शिवशंकर यादव बिगत चुनाव में यहां राजद के उम्मीदवार थे, उनके निधन के बाद उनके भाई चंद्रिका यादव राजद से टिकट के दौड़ में शामिल है. वहीं कांग्रेस से डॉ. विनय बिहारी सिंह की सक्रियता भी क्षेत्र में दिख रहीं है. महागठबंधन की ओर से जदयू के प्रमुख दावेदार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा का नाम भी जोरदार चर्चा में हैं. वहीं समाजवादी जनता पार्टी चन्द्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में जेपी आंदोलन के नेता महात्मा भाई भी तैयारी में है. कई अन्य लोग भी विभिन्न दलों से टिकट के जुगाड़ में लगे हैं. जीरादेई विधानसभा पिछले चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 248678 थी. वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 27.25 प्रतिशत, माले, राजद को 18.99 प्रतिशत, राजद माले 11.62 प्रतिशत व निर्दलीय, जदयू 8.09 प्रतिशत वोट था. वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.26 प्रतिशत, माले राजद 25.13 प्रतिशत, राजद माले 18 प्रतिशत, व निर्दलीय को 10.72 प्रतिशत वोट मिले थे.

जीरादेई की मुख्य सड़क आज भी 10 फिट का है, जिसका दोहरीकरण का कार्य नहीं हो सका. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर जीरादेई से चलने वाली सरकारी बसें लगभग एक दशक पूर्व ही बंद हो गई, वर्ष 1983 के आसपास यहां बिहार टूरिज्म का एक कार्यालय भी खुला था जो 1990 के आसपास बंद हो गया. तत्कालीन प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर द्वारा जीरादेई में राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं. जिसमें की राजेन्द्र बाबू की स्मृतियों को सजोंया जा सके.

इस बार के विधानसभा चुनाव में राजग व महागठबंधन द्वारा इस सीट पर अपना कब्जा जमाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है. भाजपा द्वारा अपनी मंडलस्तरीय बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने में पूरी ताकत लगा दी हैं. वहीं जदयू के नेता घर-घर दस्तक के अलावा अन्य कई अभियान चला रहे हैं. ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके. लेकिन जनता की चुप्पी के सामने सभी दलों के नेताओं व संभावित उम्मीदवारों की एक नहीं चल रही हैं. इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र में जो प्रमुख चुनावी मुद्दे होगें, इनमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लचर विद्युत आपूर्ति में सुधार, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तथा मैरवा को अनुमंडल बनाने की मांग आदि शामिल हैं. हांलाकि जीरादेई की प्रमुख जनसमस्याओं को लेकर जेपी आंदोलन के संघर्षशील एवं समाजसेवी तथा समाजवादी जनता पार्टी के चन्द्रशेखर को प्रबल दावेदार के रूप में महात्मा भाई का नाम भी जोरदार चर्चा में है. इस संबंध में जब महात्मा भाई से संपर्क स्थापित किया गया तो उनका कहना था, कि महागठबंधन में जीरादेई का सीट समाजवादी जनता पार्टी चन्द्रशेखर को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश महागठबंधन के दोनों नेता इस पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के बावजूद टिकट देने में आनाकानी कर रहे है. महात्मा भाई द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता रहा है. महात्मा भाई बताते है, कि जीरादेई व देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर घोषणाओं की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है. आखीर कब तक देशरत्न का यह क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सोनवर्षा में दिख सकता है नया चेहरा

संजय सोनी/विपिन यादव

feedback@chauthiduniya.com

सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र सोनवर्षा की लड़ाई को लड़ना किसी जंग से कम नहीं. अभी इस सीट पर महागठबंधन के प्रमुख घटक दल जदयू का कब्जा है और राजग गठबंधन की बिहार में प्रमुख पार्टी लोजपा इस सीट को बपौती मानती है. पूर्व में वर्तमान जदयू विधायक रत्नेश सादा से पराजित हुई लोजपा प्रत्याशी सरिता पासवान जनसम्पर्क का कोरम पूरा करने की प्रयास में निरंतर जुटी रहती हैं. जबकि जदयू को छोड़कर कमोवेश सभी दलों के संभावित दावेदार इस सीट को बाबा धाम से कम नहीं मानते हैं. कभी कहीं कुछ हुआ परिक्रमा कर लिए. लेकिन अब सब कुछ उलट हो गया है. कल तक अलग-अलग राग आलापने वाले आज गठबंधन व महागठबंधन के बैनर तले एक-दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं. इस वजह से महागठबंधन के सीटिंग कंडीडेट जदयू विधायक रत्नेश सादा की अकड़ देखते ही बनती है. वहीं राजग गठबंधन की लोजपा नेत्री सरिता पासवान पराजित होने के बाद भी खुद को राजग की कंडीडेट मान दावेदार बनी हुई हैं. शायद लोजपा को इस बार यह सीट भाजपा के लिए त्यागना पड़ सकता है. इस सीट त्याग किये बगैर लोजपा के निहितार्थ पूरे होंगे. महागठबंधन को भी अपनी सीट बरकरार रखने के लिए नये कंडीडेट की तलाश करनी पड़ सकती है. राजग के घटक रालोसपा नेता प्रेमलाल सादा भी दावेदारी कर रहे हैं. वे कहते हैं कि उन्होंने महादलितों के हक व अधिकार की लड़ाई खासकर कोसी दियारा क्षेत्र में बिना किसी स्वार्थ की लड़ी है. वोट की राजनीति से उपर उठकर महादलितों के मान व सम्मान को बरकरार रखना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. महादलितों के हुक्म का मैं गुलाम रहा हूं.

इस सीट के लिए एक नई मुसीबत शर्मा जाति के अनुसूचित जाति में शामिल होने के बाद खड़ी हो गयी है. इस सीट के लिए सुरक्षित जातियों में पहले पासवान, राम, सादा के बाद अब शर्मा में भी दावेदार उभरने लगे हैं. कल तक भाजपा से अमीर राम, लोजपा से सरिता पासवान तो अब बहुजन मुक्ति पार्टी से रेश्मा शर्मा भी इस सीट से दावेदारी करने लगी हैं. श्रीमति शर्मा नगर परिषद सहरसा के वार्ड सं.21 की पार्षद है और महिलाओं के बीच साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 8 सितम्बर 2004 को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है. वैसे इस इलाके के आम गरीब जनता के हिमायती कहे जाने वाले डॉ. शशिभूषण की धर्मपत्नी गीता पासवान को आम जनता अपने उम्मीदवार के रूप में पिछले टर्म में भी देखना चाहती थी. यहां तक कि राजद ने अपना कंडीडेट बनाने का प्रयास भी किया. लेकिन डॉ. शशिभूषण ने राजद के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया. अन्यथा इस क्षेत्र की विधायक कोई ओर नहीं गीता पासवान ही रहतीं. डॉ. शशिभूषण की लोकप्रियता के आगे इस क्षेत्र में गठबंधन व महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दल बौने साबित हो सकते हैं. नवहट्टा क्षेत्र से 2006 व 2011 से जिला पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे अशोक पासवान की भी इस आरक्षित सीट की तरफ पैनी नजर है. श्री पासवान जिला पार्षद के पहले 2001 में नवहट्टा पश्चिमी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. यही वजह है कि इनकी लोकप्रियता किसी से कम नहीं है. इनकी धर्मपत्नी भी वर्तमान में नवहट्टा प्रखंड के पंचायत नवहट्टा पश्चिमी के सामान्य सीट से लगातार 2006 व 2011 से दूसरे टर्म मुखिया हैं. श्री पासवान की छवि राजनीतिक से कहीं ज्यादा सामाजिक रही हैं. दलित समुदाय के साथ-साथ सभी जातियों में उनकी अच्छी पकड़ रही है. श्री पासवान जिला जदयू के उपाध्यक्ष भी

अशोक पासवान | अमीर राम | सरिता पासवान | रेश्मा शर्मा | प्रेमलाल सदा | मनोज पासवान

हैं और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद यादव व पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव का भी आशीर्वाद प्राप्त है. कोसी के इलाके में सांसद शरद यादव का एक ठिकाना श्री पासवान का घर भी होता है. इन सभी दावेदारों के अलावा क्षेत्रीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से मुखिया मनोज पासवान भी लड़ाई के मूड में है. अब तक स्थिति पर गौर किया जाय तो पासवान समाज में ही सबसे ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं. इलाके वासियों की मानें तो स्थानीय विधायक के नेचर से सभी तबके के लोग उब भी चुके हैं. शुरुआती दौर में ही प्रखंडकर्मियों के खिलाफ अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा कर खुद बांह पूजाने का काम किये थे. इस बात को भी लोग याद रखे हुए हैं. इस क्षेत्र की समस्याएं अनेक हैं पर कुसहा त्रासदी को भी लोग नहीं भुला पाये हैं. कई इलाके आज भी दुर्गम बना हुए हैं. अपराधी का यह क्षेत्र सबसे सुगम व सुरक्षित शरण स्थली है. नक्सल अपराध का खाता इसी क्षेत्र से खुला है. कुल मिलाकर नये दल के नये उम्मीदवार इस क्षेत्र की आम जनता की पहली पसंद हो सकती है.■

एक नज़र

चुनावी हलचल

विधायक ने भोलेनाथ को किया दूध अर्पित

सीतामढ़ी के नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने सोमवारी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध हलेश्वर स्थान स्थित बाबा भोले शंकर का अभिषेक दूध से किया. इस संबंध में व्यवसायी संघ सीतामढ़ी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रति वर्ष सोमवारी के अवसर पर विधायक बाबा के शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं. जिले में अमन व भाईचारा के साथ सर्वांगीण विकास की कामना को लेकर उनका यह व्रत पिछले कई सालो से चल रहा है. उन्होंने बताया कि विधायक की पहल पर राजोपट्टी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर का जिर्णोद्धार कराया जा रहा है. पिछले साल सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुनौरा धाम स्थित सीता कुंड से जल लेकर उक्त शिवालय में बाबा का जलाभिषेक किया था. **– ब्रजेश**

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ

एनसीवीटी नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त बेगूसराय के सर्वोत्तम आशीर्वाद औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लवहरचक रामदीरी के नौवें सत्र 2015-17 का शुभारम्भ मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद डॉ. भोला सिंह एवं ललन प्रसाद सिंह, अमरेन्द्र प्रसाद सिंह (लल्लू बाबू), अनीता राय कलाकार सीताराम ने संयुक्त रूप से मंगल द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया. केन्द्र के डायरेक्टर अमित रौशन ने अतिथियों का स्वागत एवं डा भोला सिंह को शाल प्रदान कर सम्मानित किया. अमित रौशन की मांग पर सांसद ने घोषणा की कि भारत सरकार द्वारा बेगूसराय में स्थापित किए जानेवाले कौशल विकास केन्द्र के किसी एक ट्रेड का केन्द्र यहां स्थापित किया जाएगा. प्राकृतिक परिवेश में स्थापित इस प्रशिक्षण केन्द्र की विशेषता है कि छात्रों का वर्ग संचालन नियमित रूप से होता है. छात्रों को सिलेबस की पुस्तकें संस्था द्वारा मुफ्त में दी जाती है. कैम्पस सेलेक्शन में उस संस्था से सर्वाधिक छात्र चयनित होते हैं.

एलआईसी का लोकप्रिय प्लान

एलआईसी ने ग्राहकों के लिए एक लोकप्रिय प्लान 'न्यू एंडॉव्मेंट प्लस' लांच किया. एलआईसी के सीनियर डिविजनल मैनेजर डीके नायक, मार्केटिंग मैनेजर जे मांझी एवं सेल्स मैनेजर एके श्रीवास्तव ने एलआईसी के डिवीजनल कार्यालय बेगूसराय के कॉन्फ्रेन्स हॉल में इस प्लान को लांच करते हुए पत्रकारों को इसके लाभ की जानकारी दी. डीके नायक ने बताया कि इस प्लान में बीमा तथा निवेश दोनों के तत्व सन्निहित हैं. प्रथम यूलीप प्लान में जोखिम, सुरक्षा एवं शेयर बाजार में निवेश का दोहरा लाभ निहित है. उस प्लान में चार विकल्प बॉन्ड फन्ड, सेक्योर्ड फंड, वैलेन्स फंड एवं ग्रोथ फंड उपलब्ध हैं. यह प्लान तीन माह से लेकर पचास वर्ष आयुवर्ग तक के लिए है. इस प्लान के प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही एंव वार्षिक किया जा सकता है. इस प्लान की परिपक्वता पर ग्राहकों को फंड वैल्यू के बराबर की राशि देय है.

रतन सिंह की दावेदारी

जदयू के वरिष्ठ नेता एवं जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह ने बेगूसराय विधान सभा सीट से चुनाव लड़ने की सशक्त दावेदारी पेश की है. रतन सिंह की अचानक इस दावेदारी की घोषणा से जदयू के अन्य संभावित प्रत्याशी सकते में हैं. वहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं. वर्तमान में बेगूसराय विधानसभा सीट भाजपा के पास है और सुरेन्द्र मेहता यहां के विधायक हैं. रतन सिंह राजनीति के मंझे हुए अनुभवी खिलाड़ी हैं. चुनाव जीतने की कला में निपुण हैं. लगातार तीन बार से जिला परिषद का चुनाव जीतते आ रहे हैं. एक बार वह जिला परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं. रतन सिंह समाज में काफी लोकप्रिय हैं. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के वे चेहते हैं.यदि जदयू रतन सिंह को प्रत्याशी बनाती है तो बेगूसराय विधानसभा के चुनाव मे बीते कल के दोस्त भाजपा के साथ काफी दिलचस्प मुकाबला होगा. **– सुरेश चौहान**

अशरफ अस्थानवी सम्मानित

वरीष्ठ पत्रकार, लेखक एवं आवामी उर्दू निफाज़ कमेटी बिहार के प्रमुख अशरफ अस्थानवी को भाषाई संगठन ऐवान-ए-इर्दू मजलिस (रजि) की ओर से अशरफ अस्थानवी के सम्मान में एक शाम का आयोजन किया गया. स्थानीय कंकड़बाग स्थित पटना उच्च न्यायालय के सेवा निवृत वरीय पदाधिकारी, श्री बदर आलम खान के निवास पर आयोजित इस समारोह में भारी संख्या में बुद्धिजीवियों ने भाग लिया तथा विगत तीन दशकों से अशरफ अस्थानवी के निर्भीक पत्राकारिता एवं उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी. ऐवान-ए-उर्दू मजलिस के महामंत्री प्रो सैयद अहसान अशरफ ने अशरफ अस्थानवी के बेबाक एवं शोध-खोज पर आधारित पत्रकारिता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला. प्रसिद्ध समाजसेवी ई मो हुसैन ने श्री अस्थानवी के अनेक पुस्तकों पर चर्चा करते हुए उनकी सहज भाषा एवं प्रभावपूर्ण शैली से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने को उर्दू साहित्य के लिए शुभ संदेश बताया. शिक्षाविद् और बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो शमशाद हुसैन ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में सम्मिलित होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मैं विगत तीन दशकों से अशरफ अस्थानवी के खोजपरक लेख को पढ़ता रहा हूं तथा मैं इनका प्रशंसक हूं. इनके लेखों को पढ़ने के बाद उन्हें निरंतर फोन करके बधाई दिया करता हूं. आज इस समारोह में उन्हें सम्मनित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. पत्रकारिता एवं पुस्तक लेखन के क्षेत्र में इनके बहुमूल्य योगदान पर उन्हें लाईफ एचिवमेंट अवार्ड देकर मैं खुश हूं. उन्होंने शाल एवं प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया. प्रसिद्ध कवि हसन नबाव हसन ने अशरफ अस्थानवी की प्रशस्ति में अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया. उनके अतिरिक्त नाशाद औरंगाबादी, मीर सज्जाद, प्रो मंज़र एजाज़, प्रो इज़हारुल हक इत्यादि ने अशरफ अस्थानवी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए.■

– चौथी दुनिया ब्यूरो

सुरसंड विधानसभा क्षेत्र

चुनावी मझधार में फंस रही मांझी की नैया

2015 का विधानसभा चुनाव पुराने राजनीतिक गठबंधन के पलटने के बाद होने वाला पहला चुनाव है. इसमें पिछले चुनाव में जदयू का साथ देने वाली भाजपा, अबकी बार सामने से टक्कर देने वाली है. वहीं दूसरी ओर पिछले चुनाव में सामने से चुनावी समर में ताल ठोंक चुकी राजद इस बार जदयू के साथ है. इसमें कांग्रेस भी राजद व जदयू का मजबूत सहारा बनी है. हाल में शाहिद अली खान ने नीतीश कुमार के जदयू को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की 'हम' पार्टी का झंडा थाम लिया है. अब 'हम' भाजपा गठबंधन में शामिल है. चर्चाओं पर यकीन करें तो इस दल के वर्तमान में इकलौते प्रत्याशी शाहिद अली खान ही हैं. उनकी चुनावी घेरेबंदी को लेकर महागठबंधन जोरदार तैयारी में लगा है. दूसरी ओर गठबंधन की राजनीति के बावजूद इस सीट से भाजपा के कई संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार कसरत कर रहे हैं.

वाल्मीकि/गोविंद

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारी व प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जाने लगी हैं. चुनाव में भाग्य आज़माने वाले संभावित प्रत्याशियों ने भी क्षेत्र में मतदाताओं के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है. बिजली के खंभे और मकान प्रत्याशियों के पोस्टरों से पटे नज़र आ रहे हैं. सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ पोस्टरों में नज़र आ रहे हैं. स्थानीय अख़बारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों का दौर भी जारी है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप स्थानीय अख़बारों की सुर्ख़ियां भी बनने लगे हैं. इस बीच चुनाव को लेकर चौक-चौराहे से गांव की गलियों तक जातिगत व पार्टीगत आंकड़ों का खेल भी अब आम बन गया है. हर संभावित प्रत्याशी दूसरे को मात देकर आगे निकलने की जुगत में जिले से लेकर राजधानी तक का लगातार सफर तय करने में लगे हैं. चुनाव में अभी वक्त है. कौन सीट गठबंधन की राजनीति के तहत किस दल के पाले में जाने वाली है, किसी को पता नहीं है. बावजूद इसके सभी दलों से संभावित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी का पैगाम प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना शुरू कर दिया है.

जहां तक सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो इस सीट से पूर्व सांसद व पूर्व विधायक से लेकर पूर्व प्रत्याशी एवं पार्टी जिलाध्यक्ष तक अपनी दावेदारी से परहेज नहीं कर रहे हैं. कोई खुद के लिए तो कोई अपने परिवार के सदस्य के लिए राजनीतिक गलियारों में हाथ-पांव मारने लगा है. एक नगर पंचायत समेत कुल 37 पंचायतों को मिलाकर बनाये गये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2 लाख 79 हजार 949 है. इसमें एक नगर पंचायत पुपरी के अलावा सुरसंड की 17, चोरौत की 7, पुपरी की 13 पंचायतों को शामिल किया गया है. जिसमें 1 लाख 47 हजार 779 पुरुष एवं 1 लाख 32 हजार 170 महिला मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं. इस सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू की टिकट पर शाहिद अली खान चुनाव जीते थे. दूसरे स्थान पर राजद के पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव एवं तीसरे स्थान पर कांग्रेस के विमल शुक्ला थे.

मंजू देवी

ऊषा यादव

डॉ. गोविंद ठाकुर

डॉ महेश कुमार

गुंजेश कुमार नवीन

जयनंदन प्रसाद यादव

बैद्यनाथ प्रसाद

मनोज कुमार यादव

मो. इसराफुल हक पप्पू

राज कुमार मंडल

रंजीत कुमार मुन्ना

शाहिद अली खान

सुनील नायक

उमा शंकर गुप्ता

भोगेन्द्र गिरी

विमल शुक्ला

2015 का विधानसभा चुनाव पुराने राजनीतिक गठबंधन के पलटने के बाद होने वाला पहला चुनाव है. इसमें पिछले चुनाव में जदयू का साथ देने वाली भाजपा, अबकी बार सामने से टक्कर देने वाली है. वहीं दूसरी ओर पिछले चुनाव में सामने से चुनावी समर में ताल ठोंक चुकी राजद इस बार जदयू के साथ है. इसमें कांग्रेस भी राजद व जदयू का मजबूत सहारा बनी है. हाल में शाहिद अली खान ने नीतीश कुमार के जदयू को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की 'हम' पार्टी का झंडा थाम लिया है. अब 'हम' भाजपा गठबंधन में शामिल है. चर्चाओं पर यकीन करें तो इस दल के वर्तमान में इकलौते प्रत्याशी शाहिद अली खान ही हैं. उनकी चुनावी घेरेबंदी को लेकर महागठबंधन जोरदार तैयारी में लगी है. दूसरी ओर गठबंधन की राजनीति के बावजूद इस सीट से भाजपा के कई संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार कसरत कर रहे हैं. अब तक सुरसंड सीट से संभावित प्रत्याशियों की सूचि में पूर्व प्रत्याशी रहे पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, भोगेंद्र गिरी, मंजू देवी, राज कुमार मंडल, रंजीत कुमार मुन्ना, उमा शंकर गुप्ता व सुनील नायक का नाम शामिल है. एनडीए से ही रालोसपा की टिकट पर एकमात्र राम प्रवेश यादव भी अपनी दावेदारी को लेकर पार्टी नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं.

सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ पोस्टरों में नज़र आ रहे हैं. स्थानीय अख़बारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों का दौर भी जारी है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप स्थानीय अख़बारों की सुर्ख़ियां भी बनने लगे हैं. इस बीच चुनाव को लेकर चौक-चौराहे से गांव की गलियों तक जातिगत व पार्टीगत आंकड़ों का खेल भी अब आम बन गया है. हर संभावित प्रत्याशी दूसरे को मात देकर आगे निकलने की जुगत में जिले से लेकर राजधानी तक का लगातार सफर तय करने में लगे हैं. चुनाव में अभी वक्त है. कौन सीट गठबंधन की राजनीति के तहत किस दल के पाले में जाने वाली है, किसी को पता नहीं है. बावजूद इसके सभी दलों से संभावित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी का पैगाम प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना शुरू कर दिया है.

चर्चा है कि महागठबंधन से जनता दल की टिकट पर पूर्व सांसद नवल किशोर राय के पुत्र गुंजेश कुमार नवीन एवं पार्टी की महिला कार्यकर्ता उषा यादव भी संभावित प्रत्याशी के रूप में चुनावी अभियान में लगे हैं. इनके अलावा कुछ और क्षेत्र में मतदाताओं की नब्ज़ टटोलने में लगे हैं. जबकि राजद से पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव, मनोज कुमार यादव, मो इसराफुल हक पप्पू व राजद जिलाध्यक्ष मो शफीक खां के पुत्र सह नगर परिषद सीतामढ़ी के पूर्व सभापति मो. जलालुद्दीन अपनी दावेदारी को लेकर प्रयासरत हैं. वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला इस बार पुन: चुनावी समर में भाग्य आज़माने को तैयार बताये जाते हैं. महागठबंधन की बदौलत इस बार उनकी राह आसान बताई जा रही है. उनके अलावा डॉ. गो-विंद ठाकुर व डॉ. महेश कुमार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने को आतुर हैं. वैसे अभी कई संभावित प्रत्याशियों का नाम अलग-अलग दलों से खुलकर सामने आना बाकी है.

चर्चाओं पर यकीन करें तो अबकी बार चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होने जा रहा हैं इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है. एनडीए से सुरसंड में अगर हम पार्टी की टिकट पर शाहिद अली चुनाव मैदान में उतरते है तो महागठबंधन से उनका सीधा चुनावी मुकाबला होना तय है. चर्चा यह भी है कि अगर चुनाव विकास के पैमाने पर हुआ तो संभव है कि शाहिद की नौका किनारे लगने से पहले ही कहीं भटक न जाये. वैसे चुनाव में अभी वक्त है. जाति व पार्टी के चुनावी शतरंज की बिसात अभी बिछना बाकी है.■

feedback@chauthiduniya.com

टिकारी विधानसभा क्षेत्र

टिकट का बंटवारा आसान नहीं

अभय सिंह कुशवाहा

कुन्डल वर्मा

महेश सिंह यादव

राकेश सिंह

ऋषि लाल

टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतरने के लिए कई दिग्गज कवायद कर रहे हैं लेकिन सभी के मन में शंका बनी हुई है. यहां से वर्तमान विधायक जदयू के डॉ. अनिल कुमार हैं. वे जदयू पार्टी के बागी नेता हैं. इस बार में मांझी की हम पार्टी से उम्मीदवारी के मूड में हैं. वहीं राजद का टिकट प्राप्त करने के लिए कई लोगों की दावेदारी है. यहां से राजद के पूर्व विधायक महेश सिंह यादव दो बार चुनाव जीते हैं. शिववचन सिंह यादव राजद से एक बार विधायक रह चुके हैं. जबकि राजद और जदयू दोनों पार्टी टिकट के लिए दावेदारी ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं. टिकारी विधानसभा क्षेत्र को यादव भूमिहार, बहुल क्षेत्र माना जाता रहा है. नये परिसीमन के बदलने के कारण अब स्थिति बदलने लगी है अन्य जातियों की संख्या बढ़ी है चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ी है. जदयू के टिकट के दावेदारों में अभय कुशवाहा लंबे अर्से से गया जिले की राजनीति में अपनी भागीदारी देते आ रहे हैं. टिकारी विधानसभा क्षेत्र का राजनैतिक व सामाजिक समीकरण अभय कुशवाहा के अनुकूल माना जा रहा है. जदयू से टिकट के दावेदारों में अभय कुशवाहा अगर चुनावी मैदान में आए तो वर्तमान विधायक अनिल कुमार शर्मा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जदयू के नेता कुंडल वर्मा नया चेहरा है और उनकी छवि भी बेदाग है. कुंडल वर्मा इस बार जदयू के टिकट के लिए कतार में है. आलम यह है कि जिले की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर कुशवाहा समाज के संभावित प्रत्याशियों ने राजनीतिक गलियारों में अपना ठौर तलाशना शुरू कर दिया है. यह अलग बात है कि किसी भी सीट पर कुशवाहा बिरादरी उस स्थिति में नजर नहीं आ रही है, जहां से उस जाति के प्रत्याशी अपने बूते चुनावी जंग जीत लेने की कूवत रखते हों. बावजूद इसके गठबंधन की राजनीतिक के बदौलत चुनावी अखाड़े में आजमाइश को लेकर उठक-बैठक शुरू हो गई है. अब तक तकरीबन एक दर्जन से अधिक संभावित प्रत्याशियों के राजद, जदयू व रालोसपा से चुनाव मैदान में आने की चर्चा है.

कुंडल वर्मा कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व जातीय समीकरण भी साधने में लगा है. इस क्रम में पटना और उसके आस-पास के जिलों में सम्मेलन कराए जा रहे हैं. भाजपा की नज़र लालू एवं नीतीश के साथ रहे 51 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समुदाय पर है. वर्मा कहते हैं कि 6 प्रतिशत आबादी वाली पासवान एवं दुसाध जाति को छोड़कर शेष 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के मतदाताओं को उन्होंने महादलितों का दर्जा दे दिया है. नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और 12 प्रतिशत आबादी वाले कोयरी, कुर्मी समाज पर उनकी विशेष पकड़ है. उस क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह भी प्रयासरत हैं. राकेश सिंह सुशील मोदी के चहेते हैं. इसलिए संभावना जताई जा रही है कि कहीं अनिल डॉ. अनिल कुमार की जगह राकेश सिंह की ही लॉटरी न निकल जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

मैं नेता नहीं चकाई का बेटा हूं- सुमित

इंटरव्यू

तरुण मिश्रा

बिहार के युवा नेताओं में से एक बिहार के पूर्व कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र सिंह के छोटे बेटे एंव चकाई के वर्तमान विधायक सुमित कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह का लगभग समय इन दिनों अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ही बीतता है. ऐसा नहीं है कि आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर यह क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बल्कि बीच-बीच में यह लोगों के बीच जाकर लोगों के दुख-दर्द में शरीक होना नहीं भूलते हैं. चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात करने वाले सुमित कुमार सिंह ने चौथी दुनिया से आगामी विधानसभा एंव अन्य मुद्दों पर जब बात की गई तो उन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी बात कही. उनसे जब पूछा गया कि जिस उम्र में राजनीति में जाने कि लोग सोचते हैं, उस उम्र में आप विधानसभा पहुंच गये कैसा अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो युवा नेता को ही चुने, युवा नेता में विकास करने का एक जज्बा होता है. लेकिन हमारे यहां गलत परिपाटी है कि नेता आजीवन राजनीति में बने रहना चाहते हैं. इसमे भी एक निश्चित उम्र के बाद सेवानिवृत्ति जैसा नियम होना चाहिए और मैं भी 60 या 65 वर्ष के बाद राजनीति से सन्यास ले लूगा. जदयू से अलग होने के कारणों पर उन्होंने बताया कि मेरे पूरे परिवार ने दलितों एंव महादलितों के सम्मान के लिए राजनीति की हैं. उन्होने बताया कि जब 1991 में रामसुंदर दास को अपमानित किया तो मेरे पिताजी ने स्वास्थ्य मंत्री के पद को ठोकर मार दी थी.वहीं काम जब नीतीश कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी के साथ किया गया तो दलित एंव महादलित के सम्मान के लिए मेरे पिताजी ने मंत्री पद को छोड़ना बेहतर समझा साथ ही नीतीश कुमार द्वारा दलित महादलित प्रेम का नाटक करने पर पार्टी भी छोड़ना बेहतर समझा. उन्होंने कहा कि मेरा परिवार दलितों एंव महादलितों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं.उनसे जब चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात की गई तो बताया कि मेरा सपना है, कि मैं चकाई को चंडीगढ़ बनाऊंगा

और मैं इसे पूरा कर के ही दम लूंगा. उन्होंने

बताया कि आज चकाई में सड़कों का जाल बिछा है, घर-घर बिजली पहुंचाई गई है, साथ ही साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में 44 विद्यालय को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है. मैं चकाई का चहुमूखी विकास के लिए प्रयासरत हूं. उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरूवात है, यहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है. यह पूछे जाने पर की कुछ विपक्ष के लोग चकाई में कुछ भी विकास नहीं होने का आरोप लगाते हैं तो उन्होंने बताया कि विकास हुआ या नहीं इसका प्रमाण पत्र तो जनता देती हैं न कि चंद नेता. आप क्षेत्र में जाकर जनता से पूछ लें वो बता देगें कि विकास हुआ और नहीं.चकाई की जनता को मैं ने जगाया है और वो अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली हैं. अन्त में जब आगामी विधानसभा के मुद्दे एंव चुनाव तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं किसी खास मुद्दे को लेकर जनता के बीच नहीं जाता, जनता की सारी समस्याएं मेरा मुद्दा है. मैं लोगों के बीच नेता बनकर नहीं जाता बल्कि उनका बेटा बनकर जाता हूं. वादे तो नेता करता है बेटा नहीं. नेता वादा कर भाग सकता है क्योंकि उसे कुछ दिन रहना है मैं तो यहां का बेटा हूं, मैं कहां भाग सकता हूं.

उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो युवा नेता को ही चुने, युवा नेता में विकास करने का एक जज्बा होता है. लेकिन हमारे यहां गलत परिपाटी है कि नेता आजीवन राजनीति में बने रहना चाहते हैं. इसमे भी एक निश्चित उम्र के बाद सेवानिवृत्ति जैसा नियम होना चाहिए और मैं भी 60 या 65 वर्ष के बाद राजनीति से सन्यास ले लूंगा.

जो भी हो वर्तमान विधायक सुमित कुमार सिंह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी आश्वसत दिखाई दे रहे हैं. अपने द्वारा किये गए विकास कार्यो के साथ-साथ एनडीए का साथ मिलने पर वो काफी उत्साहित हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 सितंबर-20 सितंबर 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

हिरासत में दलित की मौत

पुलिस की गुंडागर्दी पर ग्रामीणों का आक्रोश फूटा

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का नामोनिशान नहीं है. क़ानून व्यवस्था का यह हाल है कि प्रदेश की पुलिस पर बलात्कार और हत्या के आरोप लग रहे हैं. बाराबंकी जिले में एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसकी हत्या का आरोप भी पुलिस पर लग रहा है.

पाटेश्वरी प्रसाद

जनपद बाराबंकी के कोठी के बहुचर्चित नीतू हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पुलिस की लापरवाही के चलते कुछ अराजकतत्वों ने सिद्धौर में शांति भंग करने की कोशिश की. हालात अभी बेकाबू ही थे कि मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक कथित आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत पुलिस लॉकअप में ही हो गई. ऐसी घटना के बाद बचाव में पुलिसिया हाकिम कुछ भी कहें, लेकिन खाकी के दामन पर एक और खूनी दाग काबिज हो गया है. सच है कि सबसे पहले लोकतंत्र आता है, फिर भीडतंत्र, अभिजात वर्ग और अन्त में तानाशाही आती है. सपा सरकार की कार्यशैली कुछ यही बयां कर रही है. एक दलित युवक की मौत जिस प्रभारी निरीक्षक की कस्टडी में हुई वह भी यादव हैं. इसे संयोग कहें या दुर्योग, आख़िरकार सपा सरकार का यादव-प्रेम चुनाव के आते-आते उजागर हो ही रहा है. नीतू द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी थानाध्यक्ष राय साहब यादव और उनके साथी दरोगा अखिलेश राय अभी सियासत और जांच के बवंडर से बाहर नहीं आ सके हैं. मामला अभी भी सीबीसीआईडी के पाले में है. यह अलग बात है कि इस घटना ने जनपद बाराबंकी में पुलिसिंग की खूब फजीहत कराई. गत 30 अगस्त व 31 अगस्त को देवां कोतवाली में जो घटित हुआ उसमें पुलिस हिरासत में एक दलित युवक सुभाष राजवंशी की मौत हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस का रवैया मित्रवत नहीं था, बल्कि तानाशाही के दंभ में डूबा हुआ था.

मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कथित आरोपी सुभाष राजवंशी को पुलिस द्वारा देवा कोतवाली लाया गया. माती चौकी प्रभारी जेपी यादव ने कोतवाली प्रभारी की गैरमौजूदगी में सुभाष राजवंशी की जमकर पिटाई कर दी. सुभाष राजवंशी देवा कोतवाली क्षेत्र के सरसौंदी गांव में अपने मामा नरेंद्र कुमार के घर रहता था. सुभाष के पिता छोटेलाल सैरपुर थाना मड़ियांव लखनऊ के रहने वाले थे. पुलिस की पिटाई के बाद हवालात में सुभाष की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया. पुलिस ने सुभाष के उपचार का उपक्रम करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सवालों के घेरे में खाकी

दलित युवक सुभाष राजवंशी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को आत्महत्या साबित करने में पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है. लॉकअप के शौचालय में लटकती मिली लाश पहले ही पुलिसिया कार्यशैली पर उंगली उठा रही है, क्योंकि छत की ऊंचाई देखें तो वहां से फांसी लगाने का सवाल ही नहीं उठता. सुभाष के गले और पैर में चोट के गहरे निशान थे. गले में जो चोट के निशान पाए गए वह फांसी लगने के निशान से एकदम अलग थे. पोस्टमॉर्टम से जुड़े कर्मचारियों का भी कहना है कि मारपीट के दौरान गला घोंटे जाने से ऐसा होता है. लाश को परिजनों को नहीं सौंप कर लखनऊ ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना भी पुलिस के अपराध-बोध को उजागर करता है. ■

पुलिस मृतक सुभाष के शव को पोस्टमार्टम कराने जिला मुख्यालय लेकर पहुंची, जहां तीन डाक्टरों डॉ. वीके श्रीवास्तव, डॉ. डीसी पाण्डेय एवं डॉ. आईके रामचंदानी के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस शव लेकर लखनऊ चली गई और लखनऊ में ही सुभाष के शव का आनन-फानन अंतिम संस्कार कर दिया गया. सुभाष के शव को उसके परिजनों को नहीं सौपे जाने से नाराज ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया और यह गुस्सा खाकी पर कहर बनकर टूट पड़ा. पल भर में घटना से सम्बन्धित माती पुलिस चौकी तहस नहस कर दी गई. जनपद बाराबंकी की कानून व्यवस्था पहले से ही बदतर थी, इस घटना के बाद तो और भी बदहाल हो गई. शव न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने माती पुलिस चौकी को दिनदहाड़े फूंक डाला और पुलिस कुछ नहीं कर पाई. पुलिस चौकी में हुई आगजनी में सारे सामान और दस्तावेज जलकर राख हो गए, इससे पुलिस की सुविधा और बढ़ गई. अब तो इस बहाने उसे और काम नहीं करना पड़ेगा. ग्रामीणों की हिंसक नाराजगी के प्रकोप से बचे प्रत्यक्षदर्शी सिपाही राजेन्द्र बिष्ट और पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि लाठी डंडों से लैस महिलाओं और पुरुषों ने अचानक पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया. भीड़ ने बैरक में घुसकर सामान तोड़ा और आग लगा दी. पुलिस की चार बाइकों को आग के हवाले कर दिया. चौकी के पीछे खड़ी प्रभारी की कार तोड़ डाली, सारे फर्नीचर तोड़ डाले, आगंतुक कक्ष में आग लगा दी. करीब आधे घंटे तक देवा चिनहट मार्ग पर ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया.

घटना के दौरान जब आक्रोशित ग्रामीण माती चौकी को अपने गुस्से का निशाना बना रहे थे, तब सूचना पाकर सीओ सिटी अमिता सिंह मौके पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा देखते हुए वे मूकदर्शक बनी रहीं. जब ग्रामीण वापस चले गए तब वहां अधिकारियों का तांता लग गया. जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अब्दुल हामिद, अपर जिलाधिकारी हरिकेश चौरसिया, एसपी ज्ञानंजय सिंह सहित कई अधिकारी वहां पहुंचे और फिर मंडलायुक्त और डीआईजी भी मौके पर पहुंच गए. फिर घटना का जायजा लेने की औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने दलित युवत की पुलिस लॉकअप में हुई मौत की पड़ताल करने या पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई.

डीएम योगेश्वर राम मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों को जमकर इसलिए फटकारा कि उन्होंने सतर्कता से काम नहीं किया. उन्होंने एसडीएम नीलम यादव, तहसीलदार उमेश सिंह सहित आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए. घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश देने का रस्म पूरा किया गया. एसडीएम सदर नीलम यादव को ही जांच सौंपी गई. इस वारदात में करीब 25 नामजद और तीन सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.

दोषियों पर केस नहीं निलंबन का झांसा

देवा कोतवाली की हवालात में हुई सुभाष की मौत पर दो दरोगा सहित दो सिपाहियों को निलंम्बित किया गया. चौकी प्रभारी जेपी यादव, दारोगा संतोष कुमार, सिपाही रामराज व कामता प्रसाद को सुभाष की मौत के मामले में प्रथम द्रष्टया दोषी पाया गया, लेकिन इन चारों के खिलाफ केस दर्ज कर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. चारों को निलम्बित करने की औपचारिकता निभाई गई, जिसे इलाके के लोग झांसापट्टी बता रहे हैं.

बर्खास्त हों पुलिस अधीक्षक

स्थानीय जनता बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रही है. लोगों का कहना है कि एसपी के कारण ही बाराबंकी में कानून व्यवस्था लगातार खराबल होती चली जा रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही. बाराबंकी की भाजपा सांसद प्रियंका रावत ने कहा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद की है. इन्हें सभी की मौजूदगी में सुभाष का पोस्टमार्टम कराकर उसकी लाश परिजनो को सौंपनी चाहिए थी. ऐसा नहीं करने से पुलिस का संदेहास्पद चरित्र उजागर हुआ है. पुलिस अधीक्षक को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. ■

परिजनों का आरोप, पुलिस ने की सुभाष की हत्या

सुभाष राजवंशी के परिवार की सदस्य कुसुमा रावत का कहना है कि चौकी इंचार्ज जेपी यादव, राजेन्द्र व प्रभुनाथ ने बाइक चोरी के मामले में सुभाष को पकड़ा था और उसे चौकी ले गए थे. पूछताछ के दौरान उसे बर्बरता से पीटा गया. सुभाष के बेहोश हो जाने पर पुलिस वालों ने उसे नाटक बताया और उसे उसी हालत में देवा कोतवाली लाकर वहां उसकी फिर खूब पिटाई की गई. इसी में उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले को आत्महत्या का रूप देकर पोस्टमॉर्टम अपने अनुरूप करा लिया. ■

हत्यारी पुलिस लूट पर भी उतारू

माती पुलिस चौकी फूंकने की घटना को लेकर बेलगाम हो चुकी पुलिस लूटपाट पर उतारू हो गई है. बसपा के डीडीसी प्रत्याशी सहित कई लोगों ने लाखों रुपये की जेवरात व नकदी लूटने का आरोप पुलिस वालों पर लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के सिपाही बुजुर्गों को भी पीटने से बाज नही आ रहे. पुलिस को तांडव मचाने का जैसे बहाना मिल गया है. जरवां मुजफ्फरमऊ निवासी बसपा के लोकसभा प्रभारी देवेन्द्र वर्मा उर्फ रिंकू को माती पुलिस चौकी अग्निकांड और उपद्रव का मुख्य आरोपी माना जा रहा है. वर्मा के परिजनो का कहना है कि पुलिस ने गांव में जमकर तांडव किया. तोड़फोड़ की और करीब पांच लाख की नकदी व तकरीबन दस लाख के जेवर लूट ले गए. इसी गांव के 72 वर्षीय रामदुलारे पुत्र रामस्वरुप वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे संजय की शादी के लिए पांच लाख के जेवरात रखे थे. उसे भी पुलिस लूट कर ले गई. पुलिस ने बुजुर्ग की खूब पिटाई भी की. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सरसौंदी माती बाजार, जरवा, मुजफ्फरमऊ जाकर जनता से बात की और पुलिस बर्बरता का जायजा लिया. प्रतिनिधिमंडल ने भी पाया कि पुलिस ने कानून व्यवस्था के नाम पर गांवों के अंदर घुसकर दलितों और कुर्मियों के घरों में तोड़-फोड़ की. रामदुलारे वर्मा के घर में घुसकर उनकी मोटरसाइकिल, फ्रिज तोड़ डाली और उनके लड़के को उठा लिया. विभिन्न गांवों में पुलिस द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का दौर जारी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोगों की जान ले रहा है अवैध शराब का धंधा

वैध सत्ता का अवैध संरक्षण

{ प्रदेश में ऐसे कौन शराब माफिया हैं, जिनके संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है और उन्हें सत्ता संरक्षण दे रही है. इन लोगों के आगे खाकी वर्दी बौनी नजर आती है.

बुद्ध प्रकाश/सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले में एक बार फिर जहरीली शराब के कहर से छह लोगों की मौत हो गई. वर्ष 2015 में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद यह दूसरी बड़ी घटना है. प्रदेश में जहरीली शराब और उससे हो रही मौतों की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास एक बार फिर नाकाम साबित हुए हैं. इसी वर्ष लखनऊ और उन्नाव जिले की सीमा से लगे मलिहाबाद के एक गांव में क्रिकेट मैच के दौरान जहरीली शराब पीने से सिलसिलेवार पचास से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थीं और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग बीमार हुए थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन ने सख्त रुख अख्तियार करके पुलिस प्रशासन एवं जिला आबकारी अधिकारी समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. इस घटना के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान भी चलाया गया था. तब लग रहा था कि सरकार इस अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करके ही चैन लेगी. आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही शराब की भट्टियां फिर से दहकने लगीं. दंडित किए गए अफसर फिर से बहाल कर दिए गए. जाहिर है कि इसके पीछे निहित मंशा लोगों का ध्यान मुद्दे से हटाने की थी न कि जहरीली शराब के कारोबार का समूल विनाश करने की. इन कार्रवाईयों का प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ा, नतीजा यह हुआ कि पुनः घटना घट गई. घटना के बाद फिर से सक्रिय हुई पुलिस ने फिर से अवैध शराब की भट्टियों पर छापामार कर सैकड़ों लीटर कच्ची शराब, ड्रम, पाउच, स्प्रिट, वाश, अल्कोहल, ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन सहित भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए. इससे मालूम होता है कि प्रदेश के अंदर शराब माफियाओं ने इस गोरखधंधे में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से जमा ली हैं, जिसे उखाड़ना आसान काम नहीं है.

सवाल यह भी सामने आता है कि प्रदेश में ऐसे कौन शराब माफिया हैं, जिनके संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है और उन्हें सत्ता संरक्षण दे रही है. इन लोगों के आगे खाकी वर्दी बौनी नजर आती है. प्रदेश में जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो हमेशा की तरह कार्रवाईयों का दौर शुरू हो जाता है. कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करके मामले को दबाने के लिए परिजनों को मुआवजा राशि देकर कर्तव्य की इतिश्री कर दी जाती है. हर घटना के बाद कठोर कार्रवाई के नाम पर निलंबन और मुआवजा की घोषणा हो जाती है, लेकिन अवैध शराब के कारोबारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से यह साबित होता है कि अवैध शराब के गिरोह भी सत्ता के संरक्षण में ही चलते हैं. प्रदेश में जहरीली शराब का मृत्यु-तांडव रुटीन घटना है. पिछली अनगिनत घटनाओं में हजारों बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है. जहरीली शराब की चपेट में राजधानी से सटे सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी सहित पश्चिमी और पूर्वांचल उत्तरप्रदेश के कई जिले गिरफ्त में हैं. जहां सैकड़ों लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ रहे हैं.

वर्तमान समय में मौत का यह काला कारोबार कुटीर उद्योग बन चुका है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्टियां कुकुरमुत्ते की तरह उग आयी हैं. सामूहिक रूप से इसका खुलेआम उपयोग हो रहा है. सरकार ने जिन लोगों पर इस कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी दे रखी है, वे इसके मुनाफे से अपना हिस्सा लेकर चुप रहते हैं. मौत के इस कारोबार पर इसी वजह से अंकुश नहीं लग पा रहा है. प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही कच्ची शराब के उत्पादन व देसी और अंग्रेजी शराब की तस्करी से न सिर्फ राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि बेगुनाह लोगों की जानें भी जा रही हैं. प्रदेश सरकार ने आबकारी और पुलिस विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. लेकिन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि सत्ता तक ठीक से धन नहीं पहुंचाने पर निलंबन और स्थानान्तरण की कार्रवाई होती है. अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई नहीं होती. अवैध शराब के कारोबारी माफिया हैं और उनका राजनीति से सीधा सम्बन्ध है. उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. कानून के विशेषज्ञ कहते हैं कि अवैध शराब के कारोबारियों पर गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत गैंगस्टर एक्ट, एनएसए व गुंडा एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. आर्थिक लाभ के लिए शराब कारोबारी शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाते हैं जो संज्ञेय अपराध है. लिहाजा इन पर भारतीय दंड विधान की धारा 272 के तहत भी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है. लेकिन पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं करती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

केवल धन का धंधा हो रहा है

शराब का अवैध कारोबार रोकने के लिए बनाया गया आबकारी विभाग अपना मूल काम छोड़ कर केवल धन का धंधा करता है. आबकारी महकमा अकूत कमाई का स्रोत है, इसे नेता नौकरशाह सब जानते हैं. हर साल हजारों करोड़ की आमदनी करने वाले इस महकमे के अधिकारियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता. प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने पर पूरा जोर रहता है. इसके लिए उन्हें सत्ता-शीर्ष से भी निर्देश मिलता रहता है. एक तरफ ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ नसा रोकने के फर्जी प्रयासों पर करोड़ों रुपये फूंके जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में 23 हजार 175 शराब की लाइसेंसी दुकानें हैं. जबकि प्रदेश में कॉलेजों की संख्या 20,720 है. उत्तर प्रदेश में अवैध शराब पकड़े जाने पर एक्साइज एक्ट की धारा 60, 61 और 62 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें फौरन जमानत मिल जाती है. आबकारी व पुलिस विभाग शराब बनाने व बेचने का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता. प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार कम से कम सात हजार करोड़ रुपये का है. एक आबकारी अधिकारी ने ही कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का है. गांवों में पानी न मिले, लेकिन शराब आसानी से मिल रही है. गांवों का माहौल पूरी तरह दूषित हो चुका है.

मौत बेच कर कमा रहे हैं अकूत धन

सस्ती शराब के लालच में लोग मर रहे हैं. पुलिस आबकारी विभाग और सरकारी तंत्र की आपराधिक मिलीभगत के कारण कच्ची शराब की भट्टियां दहक रही हैं. मिथाइल अल्कोहल और अन्य खतरनाक रसायनों से जहर बेचने का धंधा बेरोकटोक चल रहा है. मिथाइल अल्कोहल प्लाईवुड और पेंट की फैक्ट्रियों में अधिक इस्तेमाल होता है. डिस्टिलरियों से जब यह केमिकल भरे टैंकर निकलते हैं, तो रास्ते में इन्ही टैंकरो से कच्ची शराब के कारोबारी इसे खरीदते हैं और इसमें स्प्रीट मिलाकर इसको कच्ची शराब के रूप में धड़ल्ले से बेचते हैं. 250 ग्राम का एक पाउच सरकारी दुकानों में जहां 64 रुपये में मिलता है, वहीं इस अवैध शराब का एक पाउच 20-25 रुपये में मिल जाता है. कम लागत और ज्यादा मुनाफा कमाने का धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है. अवैध शराब का बड़ा सिंडिकेट सहारनपुर से आजमगढ़ तक विस्तृत है. इसे पुलिस, आबकारी विभाग और स्थानीय नेताओं का संरक्षण है. उत्तर प्रदेश में हरियाणा और मध्य प्रदेश के रास्ते से भी अवैध शराब लाई जाती है. पेट्रोल और डीजल के टैंकरों की आड़ में अवैध शराब को शहरों में पहुंचाया जाता है.

किसान वर्ष 2015-16

किसान वर्ष 2015-16
''पारदर्शिता के साथ किसान की सेवा''

किसानों का विकास, प्रदेश का विकास

श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
का ऐतिहासिक निर्णय

रबी 2015 में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों के प्रमाणित बीजों पर 15 लाख से अधिक कृषकों का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में जायेगा।

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए देश में अनूठी पहल

- रबी 2015-16 के दौरान गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों इत्यादि के प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला **अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डी.बी.टी.** द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा।
- किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत अब तक **पंजीकृत 14 लाख** से अधिक कृषक स्वतः अनुदानित बीज पाने के पात्र माने जायेंगे।
- **पंजीकरण से वंचित कृषकों के लिए बृहद पंजीकरण अभियान 19 अगस्त, 2015 से 20 सितम्बर, 2015 तक चलाया जायेगा।**
- पंजीकरण पश्चात 'रबी 2015-16 में अनुदानित बीजों हेतु पंजीकृत कृषकों की सूची' में किसान का नाम देखा जा सकेगा।
- 25 सितम्बर, 2015 को विकास खण्ड के बिक्री केन्द्रों पर ग्रामवार पंजीकृत कृषकों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।
- कृषक अपनी इच्छानुसार **''पहले आओ, पहले पाओ''** के आधार पर विकास खण्ड के किसी भी निर्धारित विक्रय केन्द्र से पूरे मूल्य पर बीज खरीद सकेंगे।
- निजी विक्रेताओं के माध्यम से अनुदानित बीज की बिक्री का कार्य नहीं कराया जायेगा।
- अनुदान की धनराशि 15 दिन में कृषक के बैंक खाते में भेज दी जायेगी।
- जिन किसान भाइयों ने **अपनी खतौनी, पहचान-पत्र व बैंक खाते की नकल** अभी तक जमा न करवाया हो, वे **15 सितम्बर** तक इसे विकास खण्ड पर उपलब्ध करा दें।
- 2 हेक्टेयर की सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को उसकी जोत के आधार पर बीज प्राप्त होगा।

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।

वेबसाइट: http://agriculture.up.nic.in
टोल फ्री नंबर: 1800-180-1551
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

बन रहा है आज, सँवर रहा है कल twitter.com/cmofficeup facebook.com/cmouttarpradesh youtube.com/user/upgovtofficial upnews360.in
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश http://information.up.nic.in

हरीश सरकार दमनकारी है : भाजपा

रेनू शर्मा

भाजपा ने आरोप लगाया है कि हरीश सरकार चुन-चुन कर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है. भाजपा ने हरीश सरकार पर करारा हमला बोलत हुए कहा कि वह ड्रामेबाज एवं भ्रष्टाचारी सरकार है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भाजपा विधायकों को साजिश के तहत फंसा रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता की धौंस दिखाकर और प्रतिशोध की भावना से सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा विधायकों का लगातार उत्पीड़न कर रही है. कांग्रेस जेल में डालने, कुर्की कराने और एफआईआर से भयभीत कर भाजपा विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी हाल में

भाजपा ने कहा कि यदि सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो भाजपा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. प्रदेश भाजपा के महामंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कांग्रेस की सरकार पर खनन व आबकारी घोटालों में लिप्त होने का मामला उठाते हुए पूरी हरीश सरकार को घेरा. पंत ने कहा कि सरकार ने आबकारी व खनन में नियमों को ताक पर रखा है और प्रदेश गठन से लेकर अब तक इस तरह का कृत्य कभी भी सामने नहीं आया है.

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर दंगों में फंसाने का प्रयास किया. उसके बाद लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल व 40 अन्य कार्यकर्ताओं को बेवजह ही अल्मोड़ा जेल में ठूंस दिया. अब एक और भाजपा विधायक के पीछे लग गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरा धमका कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज दबा नहीं सकती. भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने आबकारी स्टिंग ऑपरेशन की मूल सीडी के नाम पर भाजपा विधायकों पर हो हल्ला के बाद एफआईआर दर्ज कराने के फैसले को वापस लिया. इससे कांग्रेस को डर था कि कहीं पूरी इससे कठघरे में खड़ी न हो जाए. भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए दस सवाल किए हैं. भाजपा ने कहा कि यदि सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो भाजपा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. प्रदेश भाजपा के महामंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कांग्रेस की सरकार पर खनन व आबकारी घोटालों में लिप्त होने का मामला उठाते हुए पूरी हरीश सरकार को घेरा. पंत ने कहा कि सरकार ने आबकारी व खनन में नियमों को ताक पर रखा है और प्रदेश गठन से लेकर अब तक इस तरह का कृत्य कभी भी सामने नहीं आया है. पंत ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता खनन व आबकारी घोटालों का जवाब चाहती है. उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भाजपा ने राज्यपाल को काफी पहले ही सौंप दी है, अहम सवाल यह है कि क्या सरकार ने सीडी की फॉरेंसिक पड़ताल कराई? सीडी में सामने आये व्यक्तियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गयी? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मोहम्मद शाहिद प्रथम नजर में ही दोषी पाए गए, राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? भाजपा ने यह भी कहा कि इतने बड़े घोटाले को सामान्य जांच के दायरे में क्यों लाया गया? आबकारी नीति में असंवैधानिक संशोधन के पीछे सरकार की मंशा क्या रही है? भाजपा ने खनन घोटाले पर भी सरकार पर सवाल दागे. पंत ने कहा कि बिना नीति में संशोधन किए निजी व्यक्तियों को खनन पट्टे क्यों जारी किए जा रहे हैं? नियमत: एक से अधिक पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन थोक में पट्टे बांटे गए हैं. भूमि दरियापुर्द होने की कार्यवाही न करते हुए खनन पट्टे क्यों जारी किये गए? गड्ढ़े खोदकर उप खनिज निकालने की पुष्टि होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गयी? बैंक में बंधक भूमि को भूस्वामियों द्वारा लीज पर देकर सरकार द्वारा खनन पट्टे क्यों जारी किये गए? जबकि बैंक में बंधक भूमि पर अधिकार संबंधित बैंक का ही होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी के पांच सूत्रीय एजेंडे पर ध्यान

राजकुमार शर्मा

हरीश रावत की रणनीति से प्रदेश की भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर दिया है. केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए पंचक्रांति

अभियान की कमान प्रदेश नेतृत्व ने अपनी युवा ब्रिगेड के हाथ में सौंपी है. इस अभियान के तहत युवा मोर्चा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के योग क्रांति, कन्याशक्ति, स्वच्छता क्रांति, कौशल क्रांति एवं निर्माण क्रांति के प्रति आम जनता के बीच जागरूकता फैला कर अपनी पकड़ मजबूत करने की मुहिम में जुटी है. केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जारी पंचक्रांति अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में भी युवा मोर्चा को यह काम सौंपा गया है. पंचक्रांति के जनजागरूकता अभियान के जरिए प्रदेश भाजपा ने समाज के हर वर्ग व व्यक्ति तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाई है. आपदा राहत घोटाला, सिडकुल घोटाला व आबकारी स्टिंग ऑपरेशन जैसे मुद्दों को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही है. भाजपा मोदी सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे को भी आम जनता के बीच प्रचारित करने में जुटी है. इस कड़ी में गढ़वाल और कुमांऊ मंडल में एक-एक मंडल स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है, जबकि इन दिनों जिला स्तर पर कार्यशाला की जा रही है. 27 अगस्त तक जिला कार्यशालाएं संपन्न होने के बाद भाजयुमो ने मंडल स्तर तक पंचक्रांति अभियान छेड़ने की रणनीति बनाई है. भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने बताया कि जिलों की तर्ज पर जल्द मंडल स्तर पर भी क्रांतिदूत के नाम से अभियान के संयोजक नियुक्त किए जाएंगे. योगक्रांति के तहत योग शिविरों के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी, जिनमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को योग शिविरों तक लाकर योग के प्रति जागरूक किया जाएगा. कन्या शक्ति क्रांति के तहत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बालिका मैराथन दौड़ों का आयोजन किया जाएगा. इसी तरह स्वच्छता, कौशल और निर्माण क्रांति के तहत भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

रोजगार में सहकार, समाजवादी सरकार

''निजी स्वामित्व वाले पात्र रिक्शा चालक से उनका रिक्शा लेकर आधुनिक तकनीक (बैटरी/मोटर चालित) से बनाये गये रिक्शों का मुफ्त तोहफा देने की योजना''
के अन्तर्गत ई-रिक्शों के वितरण का शुभारम्भ

सरपरस्त
श्री मुलायम सिंह यादव
मा. सांसद एवं पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार

मुख्य अतिथि
श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

अध्यक्षता
मोहम्मद आज़म ख़ाँ
मा. मंत्री, संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोज़गार एवं ग़रीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उ.प्र.

दिनांक: 18 अगस्त, 2015 | समय: प्रातः 11:00 बजे | स्थान: लोहिया पार्क, लखनऊ

रिक्शा योजना के प्रमुख बिन्दु
- प्रदेश के समस्त नगर निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का चरणबद्ध रुप से चयन।
- निजी स्वामित्व के रिक्शा चालक, जो प्रदेश के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के मूल रुप से निवासी हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे।
- रिक्शा चालक जो कि संबंधित जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में दिनांक 30.11.2014 तक पंजीकृत हों, इस योजना के पात्र होंगे।

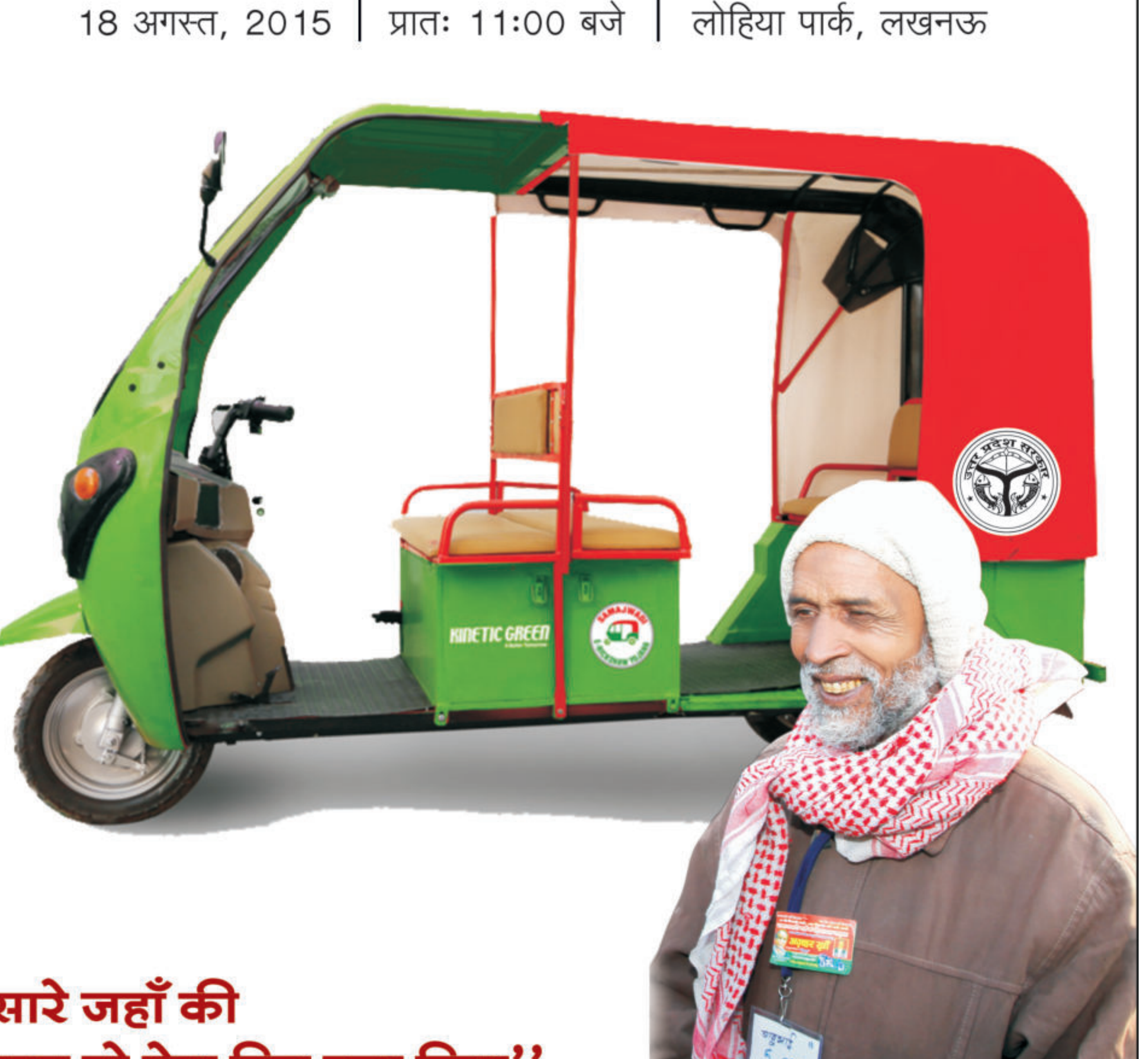

''मायूसियाँ समेट कर सारे जहाँ की
जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया''

बन रहा है आज, सँवर रहा है कल twitter.com/cmofficeup facebook.com/cmouttarpradesh youtube.com/user/upgovtofficial upnews360.in
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश http://information.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सभा और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण निर्धारण की अंतिम आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर प्रत्याशियों द्वारा जिस जोर-शोर के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उसने कई सवाल पैदा किए हैं. पहला सवाल तो यही है कि जब यह निर्धारित ही नहीं है कि किस निर्वाचन क्षेत्र से किस जाति वर्ग के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, उस क्षेत्र का आरक्षण स्वरूप क्या होगा, फिर इन प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र विशेष में किस आधार पर यह चुनाव प्रचार किया जा रहा है?

आया पंचायत गैंग का त्योहार

गांव के विकास पर नहीं, धन पर निगाह

पंचायती राज अधिनियम द्वारा गांवों में लोकतंत्र और निर्णयों में जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास सामंती ताकतों के कुचक्र में फंस गया है. गंभीर राजनीतिक चिंतकों का भी मानना है कि आज पंचायतें जिस रूप में काम कर रही हैं वह बहुत ही निराशाजनक है.

हरे राम मिश्र

उत्तर प्रदेश में जल्द ही ग्राम और जिला पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं. प्रशासनिक मशीनरी जहां निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण, परिसीमन तथा मतदाता सूची के संशोधन के काम में दिन-रात लगी हुई है वहीं, कई प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार पूरी भव्यता से शुरू भी किया जा चुका है. सोशल मीडिया, एसएमएस, व्यक्तिगत संपर्क के साथ विजिटिंग कार्ड बांटकर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए देखे जा सकते हैं. चूंकि इन चुनावों में राजनीतिक दल सीधे भाग नहीं लेते, लिहाजा सड़क, नाली, राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, विकास जैसे स्थानीय सवाल ही इनके मुद्दे होते हैं. प्रत्याशियों द्वारा एक ओर जातिगत नजदीकी, बिरादरी और रिश्तेदारी जोड़कर मतदान समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिशें चल रही हैं तो दूसरी ओर जो इस समीकरण में सेट नहीं हो रहे या विपक्षी खेमे में शामिल हैं, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने से लेकर चरित्र हनन कराने तक के प्रयास तक किए जा रहे हैं. यही वजह है कि इन दिनों ग्रामीण इलाकों में फर्जी मुकदमों की बाढ़ जैसी आ गई है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सभा और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण निर्धारण की अंतिम आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर प्रत्याशियों द्वारा जिस जोर-शोर के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उसने कई सवाल पैदा किए हैं. पहला सवाल तो यही है कि जब यह निर्धारित ही नहीं है कि किस निर्वाचन क्षेत्र से किस जाति वर्ग के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी, उस क्षेत्र का आरक्षण स्वरूप क्या होगा, फिर इन प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र विशेष में किस आधार पर यह चुनाव प्रचार किया जा रहा है? प्रचार में इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? क्या यह प्रचार केवल स्वान्तः सुखाय है? इस प्रचार के पीछे की असल राजनीति क्या है और ग्रामीण समाज के सामाजिक ताने-बाने को यह किस तरह से प्रतिबिंबित करता है. इसके विश्लेषण की जरूरत समय की मांग और लोकतंत्र के हित में है.

यह देखा गया कि चुनाव प्रचार में शामिल

प्रत्याशियों में ज्यादातर सवर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं. उत्तर प्रदेश में यह समाज मजबूत सामाजिक-आर्थिक आधारों वाला है. ये प्रत्याशी दो आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. पहला यह कि या तो ये प्रशासन में इतनी ज्यादा पहुंच रखते हैं कि चुनाव प्रचार वाले क्षेत्र का परिसीमन-आरक्षण अपने पक्ष में करवा लेंगे, कायदे कानून चाहे कुछ भी हों. दूसरा यह कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण और परिसीमन का स्वरूप आने वाले चुनाव में चाहे जिस जाति वर्ग के पक्ष में खड़ा हो, इन प्रत्याशियों के पास संबंधित जाति वर्ग से एक मोहरा पहले से मौजूद है. अभी वह मोहरा इनके

- पंचायत चुनाव में धन-बल का बोलबाला है
- लोगों को फर्जी मुकदमे में फसाने का प्रयास हो रहा है
- पंचायत चुनाव का प्रचार-प्रसार जोरों पर है
- अधिकारी और पंचायतें साठगांठ कर धन हड़प रही हैं
- पंचायतें जिस तरह काम कर रही हैं वह निराशाजनक है

साथ एक कदम पीछे चल रहा है. परिस्थिति बदलने पर वह आगे चलेगा. उससे इनके वर्चस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

प्रतापगढ़ के एक इलाके में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रचार कर रहे एक बाहुबली सवर्ण से जब यह सवाल किया गया कि अभी आरक्षण की घोषणा हुई ही नहीं है, तब आप किस आधार इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? उनके उत्तर चौंकाने वाले थे. उनका कहना था कि उनके गुट में ओबीसी से लेकर एससी और एसटी तक सभी चेहरे हैं. अगर परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होता है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी जगह पर चुनाव लड़ेगा वह अपना ही आदमी होगा और हमारे साथ इस समय चुनाव प्रचार में भी साथ है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई दलित या पिछड़ा जिला पंचायत या ग्राम पंचायत का चुनाव जीत भी जाए तो भी वह प्रभावी ताकतों के हाथ का खिलौना ही रहेगा. वह पूरे पांच साल केवल एक रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल होता रहेगा. ग्राम पंचायतों के अधिकांश निर्वाचित ग्राम प्रधानों की स्थिति यही है.

दरअसल हाल के वर्षों में ग्राम और जिला पंचायतों में विकास के नाम पर जो अथाह धन आया है, उसे निपटाने और हड़पने की कोशिशों ने पंचायती चुनावों को एकदम विषाक्त बना डाला है. इस अथाह धन पर कब्जे की होड़ में बाहुबली और सामंती किस्म के लोगों के नेतृत्व में एक ही क्षेत्र में कई गैंग बन गए हैं, जो गैंग चुनाव जीत जाता है वह पंचायत से मिलने वाले लाभों को पांच साल खाता है. इस धन को हड़पने की यह राजनीति इस हद तक हिंसक हो गई है कि चुनाव के बाद छह माह तक चुनावी दुश्मनी निकाली जाती है, हत्याएं होती हैं. आम ग्रामीण परिवार जो इस गैंग में सेट नहीं हो सकता उसके हिस्से में कुछ आता भी नहीं है.

कुल मिलाकर पंचायती राज अधिनियम द्वारा गांवों में लोकतंत्र और निर्णयों में जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास सामंती ताकतों के कुचक्र में फंस गया है. गंभीर राजनीतिक चिंतकों का भी मानना है कि आज पंचायतें जिस रूप में काम कर रही हैं वह बहुत ही निराशाजनक है. उससे बेहतर यही है कि वे नष्ट हो जाएं. ये पंचायतें अपने समाज के लिए कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर रही हैं. वास्तव में इस अराजकता के लिए पंचायतों को पूरी तरह दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता. सवाल तो यह भी है कि देश की पूरी राजनीति ही कौन सा सृजनात्मक कार्य कर रही है? वास्तव में अर्थव्यवस्था और राजनीति की अराजकता तथा उसका संकट समूचे समाज में प्रतिबिंबित होता है. राजनीति में जिस किस्म की अराजकता पैदा हुई है उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब ग्राम और जिला पंचायत के चुनाव में भी दिखता है. अगर संसद में बड़े धन कुबेरों-घोटालेबाजों और अपराधियों का कब्जा है, तो पंचायतों पर छोटे धन कुबेर, सामंत और अपराधी तत्व काबिज हो रहे हैं. आम आदमी के लिए राजनीति ने किसी भी स्तर पर कोई जगह नहीं छोड़ रखी है. यही हाल ग्राम पंचायतों का भी है. अगर पंचायतों को जनोन्मुखी होना है, तो सबसे पहले देश की राजनीति को जनोन्मुखी बनाना होगा.

विधानसभा चुनाव के पहले का तापमान बताएगा पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां दिखने लगी हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के लिए ताकत नापने का जरिया बनेगा. इससे सभी दलों को विधानसभा चुनाव का राजनीतिक-तापमान पता चलेगा. सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के लिए पंचायत चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी भी विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनावों के जरिए अपनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहती है. भाजपा ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है.

पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशियों पर कयास लगने लगे हैं. लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रोफेशनल-गिरोहों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन गिरोहों के पास हर जाति के प्रत्याशी तैयार हैं. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. आप जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान है. पंचायत चुनाव में सपा को चुनौती देने के लिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन भी ताल ठोक रही है. उसके मुस्लिम व दलित गठजोड़ बनाने के प्रयास सपा को चिंतित कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का महत्व विधानसभा चुनाव से कम नहीं है. पंचायत स्तर तक आने वाला सरकारी धन इतना है कि वह विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं को भी चौंधिया रहा है.

चुनाव के लिए प्रदेश के सभी जिलों का परिसीमन करा लिया गया है. 70 जिलों के परिसीमन के बाद प्रदेश में 7,122 ग्राम पंचायतें बढ़ गई हैं. जबकि संतकबीरनगर, गोंडा, संभल, मुरादाबाद और गौतमबुद्धनगर में परिसीमन नहीं हो पाया है. इस तरह परिसीमन के बाद प्रदेश में कुल 58,036 पंचायतें हो गई हैं. ग्राम पंचायतों के लिए 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक आरक्षण रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कहां से कहां पहुंच गईं यूपी की पंचायतें

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई. इसे संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम-1947 के तहत लागू किया गया था. संविधान बनने के बाद पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई. संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद-40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार देने का प्रयास किया जाए. इस तरह उत्तर प्रदेश में उस समय पाच करोड़ चालीस लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने काम करना प्रारम्भ किया था. साथ ही लगभग 8 हजार पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई थीं. 1951-52 में गांव सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 और पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8492 हो गई. फिर यह संख्या बढ़ती ही गई. क्रमिक रूप से पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने की प्रक्रिया जारी है. एक समय यह भी आया कि राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) में एकरूपता लाने के लिए पंचायतों के संगठन और संरचना में ढांचागत बदलाव किया गया. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. पंचायतों का निश्चित कार्यकाल किए जाने के साथ-साथ पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व का विस्तार किया गया. पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की गई. इतनी सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद पंचायतों का क्या हाल हुआ और पंचायतें गांवों का कितना भला कर पाईं, यह सब सामने है. विकास योजनाओं का धन भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में भरा जा रहा है. पंचायतों में विकास योजनाओं के धन की खुली लूट हो रही है. महज तीन महीने में अमेठी जनपद में पंचायतों के विकास के नाम पर 27 करोड़ का घोटाला सामने आया. यही हाल पूरे प्रदेश की पंचायतों का है. प्रदेशभर में ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चलाई जा रही विकास योजनाओं में मचने वाली लूट अब किसी से छिपी भी नहीं है. पंचायतों का विकास करने के बजाय अधिकारी और पंचायतें साठगांठ कर धन हड़प रही हैं. मनरेगा में अरबों का घोटाला हो चुका है. राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में जामो, सिंहपुर, मुसाफिर खाना, अमेठी संग्रामपुर और भादर सहित अमेठी के 13 विकास खंडों की 586 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है. मनरेगा के घोटालों की तो सीबीआई जांच भी कर रही है. अमेठी में वर्ष 2011 में सबसे पहले मनरेगा के तहत समदा ताल परियोजना शुरू की गई थी. अमेठी शहर से महज दो किलो मीटर दूर शुरू हुई इस परियोजना में आधा-अधूरा काम करके करोड़ों की हेराफेरी कर ली गई. ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश की है. मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में एक लाख से अधिक के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रावधान है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा. ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में एक लाख से अधिक के पक्के कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाए जाने का नियम है, लेकिन इस नियम का कोई भी पालन नहीं करता. अधिकांश ग्राम पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही है. पक्के कार्य की फाइलों में फर्जी तरीके से टेंडर की नोटिस चस्पा की जा रही है. सत्ता से संरक्षित प्रधानों के यहां पंचायतों और मनरेगा का भ्रष्टाचारी-धन खुलेआम संचित हो रहा है. ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, कार्यवाही लिखना, प्रस्ताव एवं कार्य योजना तैयार करना, बजट बनाना, खर्च करना, उसका लेखा-जोखा रखना और प्रशासन से पत्राचार आदि का काम पंचायत सचिव का होता है, लेकिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों का अकाल है. ग्राम विकास अधिकारियों के भी हजारों पद खाली हैं. सरकारी धन लूटने के लिए यह जानबूझ कर किया जा रहा है, ताकि अंगूठाछाप प्रधानों से मनमाने निर्णयों पर अंगूठा लगवाया जा सके. समुचित प्रशासनिक मशीनरी के अभाव में ग्राम प्रधान और अधिकारी मिल कर बड़े पैमाने पर फ़र्ज़ी काम या मज़दूरी दिखाकर मनरेगा का पैसा हड़प रहे हैं. विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम पिछले तीन दशक से नहीं हुआ है. उत्तर प्रदेश का सत्ताधारी नेतृत्व और नौकरशाही चाहती ही नहीं कि सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण हो, ताकि लूट का सिलसिला चलता रहे.